हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

06.03.2017/1400/जेके/एजी/1

स्थगित प्रश्न संख्याः 3604

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, यह पिछले सत्र का प्रश्न है, जो कि पोस्टपोन प्रश्न था। अखबारों में, समाचारों में बताया गया कि बहुत ज्यादा भर्तियां हो गई है। इसलिए हम सदन के माध्यम से जानना चाहते हैं कि किस-किस केटैगरी की भर्तियां चयन बोर्ड द्वारा की गई? क्या यह सूचना इसी सत्र के अन्दर-अन्दर दे दी जाएगी ?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी यह सूचना माननीय सदन में दे दी जाए।

06.03.2017/1400/जेके/एजी/2

प्रश्न संख्याः 3708

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इस योजना को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए विभाग ने पांच सेवा प्रदाता कम्पनियों को पंजीकृत किया है। पहले तो मंत्री जी यह बताएं कि ये पांच कम्पनियां कौन-कौन सी हैं?

दूसरे, यह भी बताने की कृपा करें कि इस योजना के अन्तर्गत कितनी मिनिमम भूमि आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहां पर छोटे-छोटे होर्डिंग वाले किसान है और ये कम्पनियां कह रही है कि जो मिनिमम लैंड है वह इतनी होनी चाहिए। उसी हिसाब से इन्होंने रेट भी तय कर रखे हैं। कृपया इस बारे में मंत्री जी बताने की कृपा करें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, ये पांच कम्पनियां हैं मैसर्ज़ एस0एम0 इन्टरप्राइजर्ज़, मैसर्ज़ इंडल ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, मैसर्ज़ जी0के0

ट्रेडर्ज़, मैसर्ज़ कॉनसोलर पॉवर कौंसिल सिस्टम और मैसर्ज़ साईंस स्टील कम्पनी। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि कितनी भूमि होनी चाहिए? आपको मेरे ख्याल से किसी ने बताया होगा। मुझे नहीं पता, आप बताएं कि कितनी होनी चाहिए?

श्री कुलदीप कुमारः माननीय मंत्री जी को पता नहीं है तो वे पता करें कि कितनी भूमि होनी चाहिए? क्योंकि ये जो कम्पनियां हैं और मिनिमम लैंड की जो वायबिलिटी बनाती है कि इतनी लैंड होनी चाहिए तभी ये कम्पनियां उसमें काम करेंगी। हमारे यहां पर छोटे-छोटे किसान है और आपने एक सामुदायिक स्कीम बनाई है, वे सारे के सारे इकट्ठे नहीं हो पाते। उस स्कीम को न चलने का कारण भी मैं यही समझता हूं।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो सामुदायिक सिस्टम है उससे काफी फायदा है,

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

06.03.2017/1405/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 3708 क्रमागत

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री क्रमागतः

क्योंकि एक बीघा के ऊपर जितना खर्चा आयेगा, एक हैक्टेयर उससे 15 गुणा ज्यादा होता है तो उसके ऊपर 15 गुणा खर्चा नहीं आयेगा, वहां पर ज्यादा -से- ज्यादा 5 गुणा खर्चा आयेगा। इसलिए सामुदायिक का तो यह फायदा होगा। परन्तु जहां तक आप बता रहे हैं कि कितनी मिनिमम जमीन चाहिए और कम्पनियों ने यह कहा है तो लोगों ने आपसे कहा है कि कम्पनियों ने यह कहा है तो आप वह मुझे क्यों नहीं बता देते।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूचना सभापटल पर रखी है उसमें यह कहा गया है कि केवल इस कार्य के लिए पैसा खर्च होगा जहां पर खेत के चारों तरफ आपको कोई इलैक्ट्रीफिकेशन करके बाड़बंदी करनी है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पहले तो किसान के खेत में प्राकृतिक आपदा से या उनके मकान में दरार आती थी तो प्रोटैक्शन वॉल देने के लिए प्राकृतिक आपदा मद में प्रावधान था कि जो पैसा आयेगा वह लगाया जायेगा। क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात है? यदि है तो क्या आप ऐसा प्रावधान करेंगे क्योंकि वहां तो बंदिश हो गई कि अब कोई भी प्रोटैक्शन वॉल नहीं दी जायेगी? इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की जो बहने वाली जमीन है, जहां पर स्लाइडिंग एरिया है और जमीन बह रही है या घर में दरारें आ रही हैं वहां सुरक्षा के लिए प्रोटैक्शन वॉल देने का प्रावधान करेंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह तारबंदी जो है यह खेतों की फसल को पशुओं से बचाने के लिए है। यह मकानों को बचाने के लिए नहीं है और कौन-से खेत में दरार जा रही है जो तार ने रोक देनी है।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आप बाड़बंदी कर रहे हैं इस बाड़बंदी में आप सोलर लाइट लगा रहे हैं, करंट लगा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में गांव के कुछ लोगों ने इकट्ठे हो कर हज़ार रुपया पर

कैनाल डाल कर बाड़बंदी की है। जो आपका बाड़बंदी का खर्चा है वह बहुत ज्यादा है क्योंकि आप उसमें सोलर लाइट लगा रहे हैं, करंट लगा रहे हैं तो लोग चाहते हैं कि हमें करंट न दिया जाए, सोलर लाइट न दी जाए, सिर्फ बाड़बंदी दी जाए। क्या आप इसको बाइफरकेट कर देंगे कि जो लोग यह चाहते हैं कि अकेला बाड़ ही लगाया जाए और आप जो दूसरा सोलर लाइट और करंट का ड्रामा चल रहे हैं वह न रचा जाए?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः यह तो यहां पर इनकी प्रेजैंटेशन है। कोई यहां कोशिश और ड्रामा नहीं कर रहा है कि ऐसे किया जाए या वैसे किया जाए, जैसे कि ये बता रहे हैं। एक बात के मैं भी हक में हूं कि अगर तार लगाई जायेगी और टॉप की तार में करंट होगा तो स्पोज़ यहां से पशु छलांग लगाता है और वह तार उसको टच कर जाती है और पशु इस तरफ नहीं पड़ता बल्कि खेत में पड़ता है तो उस फसल को कोई बचाने वाला नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सोचने वाली बात है। यह मैं सोचूंगा।

Speaker: Mr. Kalia, you use appropriate words.

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, लोग सरकार की योजना का लाभ नहीं ले रहे। जैसा कि मैंने पहले कहा क्या आप बाइफरकेट करेंगे या नहीं?

अध्यक्षः मंत्री महोदय, क्या आप स्कीम को बाइफरकेट कर सकते हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये क्या बाइफरकेट करवाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि वह नहीं लगाई जायेगी।

श्री सुरेश भारद्वाजः ये कह रहे हैं कि जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं क्या वह बंद करेंगे या नहीं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः यह क्या ड्रामेबाजी है? जो काम आपने किया है वह हम कर रहे हैं तो क्या वह ड्रामेबाजी है? जो बात मैं इनको कह रहा हूं, यह मेरे दिमाग में भी है कि जो हम ऊपर इलैक्ट्रिक तार लगा रहे हैं उसके साथ अगर पशु छू जायेगा और पार खेत में पड़ेगा तो यह बात पहले ही मेरे ध्यान में है।

06.03.2017/1405/SS-AG/3

श्री राकेश कालियाः यह बात लोगों पर छोड़ दो कि वे करंट वायर में लगाना चाहते हैं या नहीं, उसमें आपका खर्चा कम आयेगा।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः हम उनको इसके बारे में पूछेंगे, तभी लगायेंगे। ---(व्यवधान)-- अभी नहीं लगा रहे, अब आपने यह इश्यु रेज़ किया और मेरे ध्यान में भी यह है।

अध्यक्षः आप मंत्री जी को लिख कर दें he will examine it and then take appropriate decision.

प्रो प्रेम कुमार धूमल जारी श्रीमती के0एस0

06.03.2017/1410/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3708 जारी---

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत मिनिमम कितनी भूमि का रकवा चाहिए जिसमें यह बाड़बन्दी का प्रावधान किया जाएगा? दूसरे, क्या इस स्कीम में ऑप्शन है कि लोग केवल बाड़ ही चाहते हैं या सोलर लाईट के माध्यम से करंट वाली बाड़ चाहते हैं ? ये दो अलग-अलग है। एक तो साधारण बाड़ होती है जिसका जिक्र कालिया जी कर रहे थे और इनके चुनाव क्षेत्र में मैंने भी देखा है कि गांव के लोगों ने स्वयं बाड़ लगाई है। तो क्या आप दोनों ऑप्शन्ज़ देंगें और इसके लिए कम से कम कितनी भूमि चाहिए?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, हम दोनों ऑप्शन्ज़ देंगें। जो चाहेगा कि बिजली की तार भी लगाओ तो हम वह भी लगा देंगें और वह तो हमारी स्कीम में ऑलरेडी है। अगर लोग ये चाहेंगें कि हमें इलैक्ट्रिक शॉट नहीं चाहिए तो हम वह भी करेंगें। जहां तक ये पूछ रहे हैं कि कम से कम कितनी जमीन चाहिए, यहां पर तो एक कनाल वाला भी कह रहा है कि मेरे खेत को बाड़ दो।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मंत्री जी, आप बताएं कि आपने लिमिट क्या रखी है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः धूमल जी, आप मुझे इतने सालों से जानते हैं और आपको क्या मालूम नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं होता।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने स्कीम में कोई लिमिट रखी है या नहीं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे लिमिट का पता नहीं है। इसका पता करवा लेंगें।

06.03.2017/1410/केएस/एएस/2

प्रश्न संख्या 3709

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के "क" भाग के उत्तर में कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है लेकिन मुझे लगता है कि यह सूचना इतनी लम्बी नहीं है। जो आऊटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी सूचना सभी विभागों के पास उपलब्ध है। दूसरे, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही आपके एक सम्मेलन हुआ था और ये सभी पीटरहॉफ के प्रांगण में उपस्थित थे। उनको वहीं पर गिन लेते। यह कठिन काम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी सूचना देने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें कहीं कमी है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या इसी बजट सत्र के दौरान इस सूचना को उपलब्ध करवा देंगें?

दूसरे, "ख" भाग के उत्तर में कहा गया है कि मामला विचाराधीन है। मै जानना चाहता हूं कि विचाराधीन क्या है? क्योंकि जनसभा में तो जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए उसमें तो लगभग अपनी ओर से सरकार ने घोषणा कर दी है। एक तरफ कहते हैं कि मामला विचाराधीन है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगें? इन दोनों बातों के बारे में अगर स्थिति स्पष्ट हो जाए तो उचित रहेगा।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के दो भाग है। "क" एवं "ख"। जहां तक "क" भाग का प्रश्न है, हमने कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है और "ख" भाग में हमने कहा है कि मामला विचाराधीन है।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या इसी सत्र में इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध हो पाएगा?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आऊटसोर्सिंग कर्मचारी सैंटर गवर्नमैंट के भी है और स्टेट के भी हैं और जो हम पॉलिसी बना रहे हैं वह स्टेट के कर्मचारियों के बारे में बनाई जा रही है।

अगला प्रश्न अ0व0 की बारी में

6.3.2017/1415/av/as/1

<u>प्रश्न संख्या : 3710</u>

श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखी गई सूचना के मुताबिक हमीरपुर डिपो में बसें सरप्लस हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो चार रूट सुजानपुर-चण्डीगढ़, रक्कड़-देहरादून और दो संधोल-चण्डीगढ़ सैंक्शन हुए हैं; क्या उन पर बसें चलाई गई हैं? अगर नहीं चलाई गई है तो उनको न चलाने के क्या कारण हैं और उनको कब तक चलाने का विचार है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने पूछा है तो उसके बारे में मैंने बताया है कि 20 रूट अभी चालू किए हैं और मैंने उसका 'क' भाग पर पूरा ब्यौरा लगाया हुआ है। हमीरपुर-बस्सी वाया कोट, हमीरपुर-दख्योरा वाया भोटा, हमीरपुर-टौणीदेवी, हमीरपुर-बस्सी वाया भोटा, हमीरपुर-मनियाना, हमीरपुर-धनेटा वाया गलोड़, हमीरपुर-अवाहदेवी वाया भोटा, हमीरपुर-भरेड़ी वाया लम्बलू, हमीरपुर-दयोठसिद्ध वाया धनेड़, हमीरपुर-ऊना वाया मैहरे, हमीरपुर-ऊहल वाया कोट, हमीरपुर-उखली वाया धगोटा, हमीरपुर-भरेड़ी वाया

टौणीदेवी-कंज्याण, हमीरपुर-कठेड़ा, घोड़ाधवीरी-चण्डीगढ़ वाया मैहरे, सुजानपुर-मनाली वाया लम्बलू, हमीरपुर-धनेटा वाया गलोड़, हमीरपुर-जाहू वाया वण्डवी-तढरोण, हमीरपुर- अमृतसर वाया भोटा मैहरे-ऊना होशियापुर। ये सारी बसें पिछले साल लगाई हैं तथा इसके अतिरिक्त पिछले चाल वर्षों में और भी 50 रूट चालू किए हैं। मगर यह मैटर माननीय कोर्ट में है। चण्डीगढ़ की रूट्स को लेकर के किसी ने स्टे लिया हुआ है। इसके लिए मैंने पहले ही आदेश दिया हुआ है कि इसको माननीय न्यायालय से शीघ्रातिशीघ्र सोर्टआउट करवायें। माननीय कोर्ट से जैसे ही इसके बारे में निर्णय आयेगा मैं आर0टी0ओ0 को आदेश करूंगा कि इसको जल्दी-से-जल्दी चालू करवायें।

प्रश्न समाप्त

6.3.2017/1415/av/as/2

प्रश्न संख्या : 3711

श्री हंस राज : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पूछने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि बंझराडू से वाया अलवास-सकलोगा-बनयोगा जो रोड है इसी पर ही एक मोडल स्कूल का निर्माण होना है जो कि स्वीकृत है। इसको 5-6 वर्ष का समय हो गया है और यह मोडल स्कूल गवर्नमैट सीनियर सैंकेंडरी स्कूल खुशनगरी में चलता है। बंझराडू से अलवास तक के क्षेत्र में केवल वन भूमि आती है इसमें कोई निजी भूमि नहीं है। उत्तर में भी कहा गया है कि 76 प्रतिशत वन भूमि है और 24 प्रतिशत निजी भूमि है। अलवास क्षेत्र में जहां पर यह मोडल स्कूल बनना है वहां तक बहुत पुराना राज रास्ता है। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे आदेश करेंगे कि कम-से-कम वहां तक रोड बन जाएं ताकि इस मोडल स्कूल का काम भी चल पड़े।

Chief Minister: Speaker, Sir, a survey work of Satloga-Chatong-Chakrog-Shalang Road in Gram Panchayat Khushnagari, has been done by the

Department. This road is eligible under PMGSY. But in this alignment, 76% forest land and 24% private land is involved, in a total length of 8.520 k.m.

Continue by DC in Eng….

06/03/2017/1420/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
प्रश्न संख्याः 3711 - - क्रमागत

Speaker: Sh. Hans Raj ji, you would like to ask?

श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में सिर्फ इतना ही लाना चाहता था, जैसाकि इन्होंने खुद कहा कि इसमें 6 परसेंट फॉरेस्ट लैंड है, और यह फॉरेस्ट लैंड पहले आती है। इसके बाद निजी भूमि आती है। यहां पर जो स्कूल बनना है उसके लिए ही इस रोड़ को बनाने की कोशिश की जा रही है और लोक निर्माण विभाग ने इस रोड़ को बनाने के लिए सरहानीय प्रयास किए हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इतना आश्वास्त करेंगे कि जो अढ़ाई किलोमीटर फॉरेस्ट के अंडर आता है, उसकी डी0पी0आर0 बनाकर फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए भेजेंगे? यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता था क्योंकि पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत तो इसका केस पहले ही गया हुआ है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि उस सड़क को स्कूल तक पहुँचने के लिए प्रायोरिटी पर बनाया जाएगा।

प्रश्न समाप्त

06/03/2017/1420/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

प्रश्न संख्याः 3712

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सूचना सभापटल पर रख दी गई है। लेकिन यह सूचना अधूरी है। इसमें 'क' भाग की सूचना तो शामिल है, लेकिन इसके 'ख' भाग में मैंने पूछा था कि गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी सीटें खाली रह गई है? उसमें बारे में इन्होंने यहां पर कोई विवरण नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में कितनी-कितनी सीटें आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली रह गई है? आपने कहा कि आई0टी0आई में 35000, पॉलिटेक्निकल-9000 और इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 7000 हजार सीटें है। इनमें से पिछले तीन सालों में कितनी सीटें भरी गई और कितनी सीटें खाली रह गई ?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 में आई0टी0आई0 (सरकारी) में 15441 सीटें थी जिनमें से 13336 भरी गई और 2100 खाली रह गई थी। 2015-16 में आई0टी0आई0 में 16000 सीटें थी, जिसमें से 3500 खाली रह गई थी। वर्ष 2016-17 में 17911 सीटें थी, जिनमें 4021 खाली रह गई थी। इसके अलावा गैर-सरकारी संस्थानों में वर्ष 2014-15 में 11509 सीटें थी जिनमें से 6689 भरी गई और 4820 खाली रह गई थी। 2015-16 में 10221 सीटें थी, जिनमें से 6654 भरी गई और 3567 सीटें खाली रह गई थी। वर्ष 2016-17 में 17198 सीटें थी, जिनमें से 8190 भरी गई और 9008 खाली रह गई थी। इसका कुल योग 13629 है। इनमें से अगर प्राइवेट की 9000 निकाल लें तो सरकारी 4000 सीटें तथा बाकी 13000 सीटें है। राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों (सरकारी) में 162 सीटें खाली हैं और गैर-सरकारी में 6275 सीटें खाली हैं। ऐसे ही बी-टैक (सरकारी) में तीनों वर्षों में कुल 35 सीटें खाली हैं और गैर-सरकारी में 5574 सीटें खाली हैं तथा एम-टेक में 306 सीटें खाली है।

श्रीमती एन0एस0 - - द्वारा जारी ।

06/03/2017/1425/ns/dc/1

प्रश्न संख्या : 3712 ----- क्रमागत।

श्री संजय रतन : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से यह कहना चाहता हूं कि जो सीटें खाली रह जाती हैं, उसमें ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई टैस्ट रख दिया और उसमें बच्चों ने मिनिमम मार्क्स लेने हैं या मैट्रिक और ज़मा दो की प्रसेंटेज़ है उसको हम एक फिक्स नम्बर पर रख देते हैं और स्टूडैंटस दूसरी स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं। वहां पर वे पैसे डिपोज़िट कर देते हैं। लेकिन बाद में हमारा संबंधित विभाग उनको रिलैक्सेशन दे देता है परन्तु उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उसको अगर पहले ही मिनिमम पर रखा जाए तो स्टूडैंटस बाहरी राज्यों में एडमिशन नहीं लेंगे। हमारे प्रदेश के मैक्सिमम स्टूडैंटस पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों में टैकनीकल इंस्टीच्यूशन्ज़ में एडमिशन लेते हैं। उनको वहां से वापिस आने में दिक्क्त होती है क्योंकि वे पैसा एक बार डिपोजिट कर चुके होते हैं तो वह उन्हें वापिस नहीं मिलता है। इसलिए यहां की सीटें खाली रह जाती हैं और दूसरे राज्यों में स्टूडैंटस एडमिशन ले लेते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो भी एलिज़िबिलिटी रखनी है उसको एक ही बार जब भी एडमिशन स्टार्ट होती है, प्रोसपैक्टस मिलने शुरू होते हैं उसी समय उसको फिक्स कर दिया जाए और उसको बार-बार रिलैक्स न किया जाए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, डिपार्टमैंट की कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि हम बार-बार उसको चेंज करें। हम तो चाहते हैं कि मैक्सिम क्वालिटी हो। क्वांटिटी की बजाए क्वालिटी करना बेहतर है। सरकारी संस्थानों में बहुत कम सीटें खाली हैं। ये सीटें उनकी खाली हैं जो स्टूडैंटस पहले पॉलीटैक्निक में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में उनको इंनीनियरिंग कॉलेज़ में भी एडमिशन मिल जाती है, तब वे

वहां से शिफ्ट हो जाते हैं तब वह सीट खाली हो जाती है। गैर-सरकारी वाली सीटें इसलिए खाली हैं क्योंकि वे क्वालिटी का स्टैंडर्ड नहीं दे पाते हैं और लोग अपने

06/03/2017/1425/ns/dc/2

बच्चों को वहां पर भेजना ही नहीं चाहते हैं। उसके लिए 35 प्रतिशत अंक होते हैं और वैसे भी 35 प्रतिशत से कम अंक हो ही नहीं सकते हैं। मगर कॉउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्ज़ ने जो डिसाईड किया था उसके ऊपर लोगों की कई रिप्रैजेंटेशन्ज़ आईं थी। उनको देखते हुए इसको फिर चेंज़ किया गया था लेकिन उसके बाद यह दोबारा चेंज नहीं हुआ है।

डॉ0 राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम क्वालिटी को एश्योर करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रसेंटेज़ निर्धारित करते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं। पहला, किसी कट-आउट डेट के बाद उसको रिलैक्स करके जो छात्र एडमिशन लेते हैं उससे क्वालिटी कैसे मैनटेन होती है यानि एक ही बैच में दो क्वालिटी के बच्चे आ रहे हैं तो हम क्वालिटी कैसे मैनटेन कर रहे हैं? दूसरा, वही छात्र हरियाणा, पंजाब से 40 और 45 प्रतिशत पर एडमिशन ले करके बी.टेक. करके जब हिमाचल में आ जाते हैं। Basically they are Himachalis तो उनको और हमारे यहां के इंस्टीच्यूशन्ज़ के छात्रों को सैगरीगेट करने का किसी भी प्रकार का प्रावधान हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हम अपने बच्चों को इसके आधार पर फोर्स कर रहे हैं कि वे बाहर के संस्थानों में जा करके और ज्यादा खर्चा करके पढ़ें। मंत्री महोदय आप हमें क्वालिटी एश्योर करने का तरीका बताएं और पर्टिकुलर डेट के बाद क्यों रिलैक्स किया जाता है? मंत्री महोदय यह हमारा आपसे एक विशेष प्रश्न है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.आई.सी.टी.ई. नॉर्म्ज के हिसाब से बहुतकनीकी संस्थानों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक दसवीं पास के साथ 35 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा (पैट) में भाग लेना भी अनिवार्य है। अगर सीटें बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा (पैट) की

06/03/2017/1425/ns/dc/3

मैरिट के पश्चात खाली रह जाती हैं तो खाली सीटें प्रार्थी द्वारा प्राप्त, पहले 35 प्रतिशत थी, वह ए.आई.सी.टी.ई. का नॉर्म्ज़ फिक्स है, अगर उसके बाद भी खाली रह जाती हैं तो कम-से-कम 50 प्रतिशत जनरल के लिए और 45 प्रतिशत रिज़र्व केटेगिरी के लिए योग्यता के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किए गए आंकड़ों के मुताबिक ले ली जाती हैं। यह बार-बार चेंज नहीं होता है, यह डिसाईडिड है। पहले 35 प्रतिशत की पात्रता के साथ होती हैं लेकिन फिर भी अगर सीटें खाली रह गई तो उसके लिए 50 और 45 प्रसेंट वाला नॉर्म्ज बना दिया गया है वह दोबारा चेंज़ नहीं हुआ है।

श्री संजय रतन : सर, माननीय मंत्री महोदय ने आई.टी.आई की बात की लेकिन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज़ की भी बात कर रहा हूं। 35 प्रतिशत अंक वाले की इंजीनियरिंग कॉलेज़ में एडमिशन नहीं होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जमा दो वाले छात्रों की एडमिशन होती है मैट्रिक वालों की नहीं होती है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी।

06/03/2017/1430/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3712... जारी

श्री संजय रतन ...जारी

इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसा ही हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के बच्चे बाहर के कॉलेजिज़ में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में जो टैस्ट में एक परसैंटेज रखी होती है उसको रिलैक्स

करके 3-4 महीने के बाद यहां एडमिशन कर दी जाती है। लेकिन बच्चे वापिस नहीं आते हैं। जिसने एक बार एडमिशन ले ली वह वापिस नहीं आएगा। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि प्राइवेट वाले क्वालिटी को एनश्योर नहीं कर रहे हैं। अगर प्राइवेट संस्थान क्वालिटी को एनश्योर नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर सख्त नियम बनना चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन हो। जो संस्थान नॉर्म्स को पूरी नहीं कर रहे हैं, उन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा सुझाव आया है। जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज़ पूरा नहीं है, उन संस्थानों को बंद करने के लिए एक-एक एम.एल.ए. की कमेटी बना देते हैं ताकि शिक्षा में क्वालिटी आ सके। उसके लिए यदि यह सुझाव है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। जहां पर फंडामैंटल बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज़ नहीं हैं, उन संस्थानों को चलाने का कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा है तो इसके लिए मैं पहले अधिकारियों की कमेटी से रिपोर्ट ले लेता हूं और उस रिपोर्ट को हम अगले सत्र में यहां पर "ले" कर देंगे। अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज़ पूरा नहीं है तो उन संस्थानों को बंद करने का मुझे कोई एतराज़ नहीं है। छात्रों की जो खाली सीटें है, उनका कैरियर खराब न हो, उन्हें हम पास के सरकारी संस्थानों में ले आएंगे और वहां पर उनकी पढ़ाई करवाएंगे। हमें वाक्य में ही क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि जो कम्पिटिटिव इरा है उसमें जाकर वे अपनी नौकरी ले सके। अगर आप कहते हैं तो मेरे पास यहां पर पूरा क्राइटेरिया है I can send it to you as also other Members that what is the criterion available. अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई झीझक नहीं है। अगर हम क्वालिटी नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देता हूं। हम सब लोग

06/03/2017/1430/RKS/AG/2

डेमोक्रेसी में बहुत से लोगों को मिलते हैं। सुबह-सुबह बच्चों के मां-बाप आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे को नौकरी दिलाओ और वह बच्चा कहीं पर भी कम्पीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए इंजीनियर्ज़ जो आप पंजाब वाली बात कर रहे हैं Bindal Sahib, let us be practical. I am prepared and open to discuss any point. You can discuss later on and here also. The point is if we are not producing quality in today's world,

they will not get the job. आज इंजीनियर पांच हजार रुपये की नौकरी करने को तैयार है और आई.टी.आई. वाले को आठ हजार रुपये की नौकरी मिल रही है। इसके ऊपर हमें आपस में सोच-विचार करना चाहिए और इसके लिए मैं तैयार हूं, सरकार तैयार है और माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार है। मगर कृपा करके हमें इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए।

06/03/2017/1430/RKS/AG/3

प्रश्न संख्याः 3713

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 87 नए टांसफार्मर्ज़ और 2242 नए खम्भे लगाए गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत ही दुर्गम व बर्फ वाला क्षेत्र है। उसमें जो ये खम्भे गाड़े गए हैं, बहुत सारे खम्भे बर्फ के कारण उखड़ गए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 15-15 दिन तक बिजली नहीं आती है और 15 दिनों तक बिजली के सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो देहा से चौपाल के बीच 28 किलामीटर बर्फ वाला एरिया है, उसके लिए अलग से बज़ट का प्रावधान किया जाए। जब बर्फ गिरती है तो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में बिजली बंद हो जाती है। इसलिए उस एरिया में खम्भे की हाइट भी ज्यादा हो और जो हमारा 28 किलोमीटर का स्नो बाउंड एरिया है उसके लिए कोई स्पेशल बजट का प्रावधान किया जाए और

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

06.03.2017/1435/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 3713... क्रमागत

श्री बलबीर सिंह वर्मा ...जारी

उसके लिए खंबा गाडने की प्रक्रिया भी डिफरैंट की जाए और खंबे का साइज भी ऊंचा किया जाए। ऐसा करने से ही मेरे निर्वाचान क्षेत्र में बिजली ठीक से रह सकती है।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, इन्होंने अपनी बात में सलाह भी दी है**। जो यह 28 किलोमीटर का एरिया इन्होंने बताया है इसकी हम इंस्पैक्शन करवा लेंगे और इनकी इस समस्या के समाधान के लिए वहां पर जो कुछ भी करना पड़े, वह हम करेंगे।**

श्री बलवीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जब यह बिजली 15 दिनों तक बिल्कुल बंद रहती है, उस समय सारे डिविजन भी बंद रहते हैं। आपने पिछले सत्र में आश्वासन भी दिया था कि हम वहां पर एक जनरेटर की व्यवस्था करेंगे। बिजली के बिना हम तो अधिकारियों से भी बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर टेलिफोन चार्ज नहीं हो पाते। ऐसा होने से सभी ऑफिसिज के काम बंद होते हैं। जैसे चौपाल डिविजन है, तहसील नेरवा है और तहसील कुपवी है, इन 3-4 स्थानों में जनरेटर उपलब्ध करवाया जाए जिससे कम-से-कम हमारे आफिसिज के कार्य तो सुचारू रूप से चल सकें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा कि हम इनकी समस्या को हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अगर पीछे मैंने किसी सत्र में कोई आश्वासन दिया है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह पूरा नहीं हुआ तो आप मेरे साथ बात कर लेना, हम उसको पूरा करेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, मेरे चुनाव क्षेत्र में 66 के.वी. चौपाल, 22 के.वी. नेरवा और 33 के.वी. कुपवी में स्थापति हो रहे सब-स्टेशंज का कार्य प्रगति पर है। मैं आग्रह करना

चाहता हूं कि आप विभाग को आदेश दें कि वह तीनों सब-स्टेशंज जल्दी-से-जल्दी तैयार हों।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : **जैसा माननीय सदस्य ने चाहा है, विभाग को निर्देश दे दिया जाएगा।**

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ये बर्फ वाले एरियाज हैं, जैसे कि चौपाल है, रोहड़ू सर्कल में सबसे कम एनर्जी चौपाल को दी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बर्फ वाले क्षेत्रों और शिमला जैसे स्थान पर जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, अगर यहां भी बर्फ गिर जाए तो 7 दिन तक बिजली बंद हो जाती है। क्या आप इन क्षेत्रों में अंडरग्राऊंड केबलिंग का प्रावधान करेंगे ताकि पेड़ गिरने से या बर्फ के कारण या बाढ़ आने से बिजली बंद न हो और इन सब स्थानों में बिजली मिलती रहे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, वैसे तो यह प्रश्न चोपाल विधान सभा क्षेत्र का है। जैसा इन्होंने कहा कि यहां बाढ़ आ जाए, मैं नहीं समझता कि शिमला में कहीं बाढ़ आएगी। ...(व्यवधान)...आप पूछना क्या चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज : मैं यह पूछना चाहता हूं कि चौपाल क्षेत्र में काफी संख्या में पेड़ होते हैं, अगर वहां पर पेड़ गिर जाते हैं तो खंबे टूट जाते हैं तथा लाइनें भी टूट जाती हैं। बर्फ पड़ जाती है, तब भी लाइनें टूट जाती हैं। क्या आप इन क्षेत्रों में अंडरग्राऊंड केबल का प्रावधान करेंगे ताकि खंबे और तारें न टूटें और लागों को, जैसे बाकी जगह बिजली मिलती है, वैसे ही चोपाल में भी बिजली मिलती रहे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं इसके बारे में विभाग से टैक्निकल ऐडवाइस लूंगा। फिर ख़र्चे का हिसाब लगाऊंगा कि कितना ख़र्चा आता है। उसके बाद मैं दो-चार मंत्री साथ में लूंगा और फिर मुख्य मंत्री जी के पास जाऊंगा कि

इसमें जो अरबों रुपये का प्रावधान चाहिए वह प्रावधान करें। अगर वह कर देंगे तो मैं अंडरग्राऊंड केबलिंग भी कर दूंगा।

समाप्त अगला प्रश्न .. श्री गर्ग जी

06/03/2017/1440/RG/AS/1

प्रश्न सं.3714

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि राजकीय उच्च विद्यालय हलाण-। में किराये के मकान में शिक्षा दी जाती है। इसमें उत्तर में दिया गया है कि इसके दो कमरे किराये पर हैं और कुछ कमरे सरकारी भवन में चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इतने लंबे समय से लगभग दस वर्ष बीतने पर भी पाठशाला प्रबन्धन समिति द्वारा उन कमरों का किराया दिया जाता है जोकि अनावश्यक बोझ बच्चों के माता-पिता पर है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इतना समय बीतने पर भी कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं और किस कारण से इसकी जमीन के पेपर्ज इत्यादि अभी तक नहीं बने? क्या उन पर कोई जिम्मेवारी तय की जाएगी? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि दिनांक 25-03-2015 को जब शिक्षा विभाग के नाम भूमि हस्तांतरित हो चुकी है, दो वर्ष बीतने के पश्चात भी अभी तक इसका नक्शा, प्राक्कलन इत्यादि नहीं बने हैं, तो जो इसके लिए फॉर्मलिटीज हैं इनको कब तक पूरा किया जाएगा और कब तक इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि भवन का निर्माण कार्य जल्दी-से-जल्दी हो?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय हलाण-। के बारे में जैसा बताया गया कि इसके अधिकांश कमरे किराये पर हैं, तो ऐसा नहीं है। ये अधिकांश कमरे सरकारी हैं, सिर्फ दो कमरे किराये पर लिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि यहां भवन बनना चाहिए, **अगर ये बात मेरे संज्ञान में पहले आती, तो यह भवन कभी का बन गया होता। मगर कुछ न होने से, देर भली। अब मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि इस स्कूल के लिए भवन का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन का प्रावधान किया जाएगा।**

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस स्थान पर पहले भी एक बार फॉउन्डेशन स्टोन रखा गया था और शिक्षा विभाग के नाम भूमि हस्तांतरित भी हो गई थी जिसके लिए इस सारे इलाके के लोगों ने भूमि दी थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने जबरदस्ती वह पट्टिका भी उखाड़ कर फेंक दी और इस जमीन पर अपना कब्जा बताया। लेकिन जब दुबारा से निशानदेही इत्यादि हुई, तो वह भूमि सरकारी ही निकली। तो क्या इस

06/03/2017/1440/RG/AS/2

भूमि पर जल्दी-से-जल्दी फैन्सिंग इत्यादि करके बजट का प्रावधान किया जाएगा और क्या ऐसे शरारती तत्व जो शिक्षा विभाग की सरकारी भूमि पर जबरदस्ती दादागिरी करके वहां गड़बड़ करते हैं, उन पर नियंत्रण लगाएंगे? अध्यक्ष महोदय, यह आशंका अब भी है कि वे फिर से गड़बड़ कर सकते हैं इसीलिए यह देर हुई है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी ने सरकारी भूमि का अधिग्रहण करके, जहां स्कूल बनना था उस पर कब्जा किया है, तो निश्चित रूप से उनको वहां से उखाड़ा जाएगा और उस भवन का निर्माण वहीं पर किया जाएगा।

एम.एस. द्वारा अगला प्रश्न शुरू

06/03/2017/1445/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 3715

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक जमीन भी उपलब्ध है और विभाग ने पैसा भी करन्ट फाइनेंशियल ईयर में उपलब्ध करवा दिया है लेकिन ड्राईंग्ज एण्ड ऐस्टीमेट और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, पिछले बजट सत्र में मंत्री जी ने कहा था कि अगर हम जमीन उपलब्ध करवा देंगे तो इस बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमने जमीन उपलब्ध करवा दी है और 7-8 महीने का समय भी निकल गया है। क्योंकि अभी ड्राईंग्ज ही नहीं बनी है तो

क्या आप किसी ऑफिसर को डेजीग्नेट करेंगे जोकि लोक निर्माण विभाग के आर्किटैक्ट के साथ लाइजन करके इस ड्राईंग को पूरा करे क्योंकि यह कोई बहुत बड़ी ड्राईंग तो होगी नहीं। आपकी आई0टी0आई0 की जो बिल्डिंग्ज हैं उनकी जमीन के हिसाब से सोर्ट ऑफ नक्शे बने हुए हैं। उनको थोड़ा सा मोडिफाई करके जो जमीन के हिसाब से फिट होता है, बनाएं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि आपका विभाग कब तक इसकी ड्राईंग्ज चीफ आर्किटैक्ट से करवा लेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल कब तक दे देंगे? मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी आप अगले महीने या डेढ़ महीने के अंदर आकर इसका शिलान्यास भी करेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, विभाग ने बड़ी तेजी से काम किया है। यह जमीन 5-6 महीने पहले ही 23 जुलाई, 2016 को उपलब्ध हुई है। उस पर हमने बजट भी रख दिया है और आर्किटैक्ट को 5 सितम्बर, 2016 को पत्र भी लिख दिया था और फिर उसका रिमाईंडर भी 17 फरवरी, 2017 को तीन महीने बाद दे दिया है। जो आपने कहा, आपको पता है कि आर्किटैक्ट के पास काम करने का दबाव होता है। वहां साइट के हिसाब से प्लान करना है। मैं बेसिकली अधिकारियों को यह कहूंगा कि एक बार वे साइट देख लें। अगर साइट नॉर्मल है तो फिर जो दूसरा नक्शा है उसको लेकर अगर नक्शा बन जाए तो उसके ऊपर जितनी तेजी ला सकेंगे, करेंगे। मैं अपने आप भी वहां एक बार बनीखेत में लचोरी जाने का कार्यक्रम बना रहा हूं। उस समय निदेशक वगैरह सब साथ में रहेंगे तो उस समय एक्शन ले लेंगे।

06/03/2017/1445/MS/AS/2

प्रश्न संख्याः 3716

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री गोविन्द राम शर्मा।
(अनुपस्थित)

06/03/2017/1445/MS/AS/3

प्रश्न संख्याः 3717

श्री रवि ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि हमारी स्पिति घाटी केलांग से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और कुन्जुम दर्रा के कारण जोकि 15000 फुट ऊंचा है, यह घाटी बिल्कुल कट जाती है। क्या यहां पर एक सब-डिपो की जरूरत नहीं है, एक तो मेरा प्रश्न यह है? दूसरे, यह जानना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी लाहौल-स्पिति के अंदर बसिज हैं वे ज्यादातर बड़ी बसें हैं। छोटी बसों के बारे में जवाब में कहा गया है कि एक ही मिनी बस है। अध्यक्ष जी, हमारे यहां ज्यादातार जो सड़कें हैं वे लिंक रोड्ज हैं इसलिए वहां पर छोटी बसिज ही सही तरीके से चल सकती हैं तो ये कितनी ऐसी बसिज उपलब्ध करवाएंगे? जैसे 16 बसिज को रिप्लेस करके हमें नई बसें दी गई हैं तो मिनी बसिज कितनी देंगे और कब देंगे? इसके अलावा, जो काजा-रिवाल्सर बस है। जैसे लिखित उत्तर में कहा है कि कन्डक्टर्ज की शॉर्टेज के कारण वहां बस नहीं चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कन्डक्टर्ज कब तक आ जाएंगे क्योंकि काजा-रिवाल्सर और योचे-रिवाल्सर हमारा बहुत अहम रूट है, मैं पब्लिक इंट्रस्ट में यह जानना चाहता हूं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य अभी 16 बसों के बारे में कह रहे हैं, तो छोटी बसें हम उनको गिन रहे हैं जो 37 सीटर हैं। 37 सीटर से छोटी तो फिर जीप में गिनी जाएगी। अगर आपको उससे छोटी गाड़ी की रिक्वायरमैंट है तो आप अलग से बताएं। दूसरा, अध्यक्ष महोदय केलांग में डिपो है। जो माननीय सदस्य ने रिवाल्सर के लिए बस सेवा की बात कही है उसके लिए जैसे ही कन्डक्टर उपलब्ध होते हैं वैसे ही बस सेवा चालू कर दी जाएगी।

अगला प्रश्न श्री जे0एस0 द्वारा-------

06.03.2017/1450/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 3718

श्री बिक्रम सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में आया है कि राजकीय महाविद्यालय डाडासीबा की कक्षाएं राजकीय प्राथमिक पाठशाला डाडासीबा में वर्ष 2015 से चल रही है। वहां पर इस समय विद्यार्थियों की संख्या 232 के करीब है। प्राईमरी स्कूल के अन्दर बिल्डिंग छोटी है और बच्चे ज्यादा है। इसलिए क्या वहां के लिए कोई नया प्रावधान किया जाएगा ताकि वहां पर बच्चों को ठीक तरीके से शिक्षा मिल सके। यहां पर यह भी बताया गया है कि जो वहां की भूमि है वह शिक्षा विभाग के नाम हो गई है और जो भूमि की किस्म है वह बगीचा और कब्जा वन विभाग है। दो साल से शिक्षा विभाग ने इसको लिया है और उसकी किस्म बगीचा है। क्या बगीचे के ऊपर कॉलेज की बिल्डिंग बन सकती है? इसकी फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए क्या कुछ हुआ है ? दूसरे, रक्कड़ का कॉलेज सीनियर सैकंडरी स्कूल में चल रहा है। उस बारे में आपने कहा कि उसके लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दे दी है और अभी तक केवल एक लाख रूपया विभाग को भेजा है। जो एक लाख रूपया आपने भेजा है वह भी फतेहपुर के लिए भेज दिया है। यहां पर लिखा हुआ है कि लोक निर्माण विभाग फतेहपुर में पहुंच गया है। 5 करोड़ रूपया आपने स्वीकृत किया। 1 लाख रूपया आपने भेजा और वह भी आपने फतेहपुर में भेज दिया। क्या कारण है कि यह पैसा फतेहपुर में चला गया जबकि यह पैसा देहरा में आना चाहिए था। क्या आप इसको भी ठीक करेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, डाडासीबा के अन्दर डिग्री कॉलेज खोला गया है और रक्कड़ के अन्दर भी डिग्री कॉलेज खोला गया है। ये दोनों कॉलेज चालू हालत में है और वहां पर नियमित रूप से क्लासें चल रही हैं। जहां तक डाडासीबा का प्रश्न है उसके लिए 5 करोड़ रूपया सरकार ने मन्जूर किया है और पहली किश्त दी है। 5 करोड़ में कोई कॉलेज नहीं बनता उससे बहुत ज्यादा लागत लगती है। लेकिन अभी 5 करोड़ रूपया इसके लिए स्वीकृत है और यह वन विभाग के द्वारा खरीदी हुईजमीन है। इसमें आम के पौधे थे उस जमीन को इस कॉलेज के लिए चयनित किया गया है। उसके लिए जो आवश्यक

स्वीकृतियां हैं, वे वन विभाग द्वारा प्राप्त हो गई हैं। अब इस नई साईट के ऊपर नए भवन का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू किया जाएगा। जहां तक रक्कड़ का प्रश्न है, उसके लिए

भी 5 करोड़ रूपए सरकार ने मन्जूर किए हैं और वहां पर जो भूमि चयनित है, जब वह लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित की जाएगी उसके बाद उसके ऊपर भवन का निर्माण होगा।

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष महोदय डाडासीबा के अन्दर जो प्राईमरी स्कूल है जिसमें कॉलेज चलाया जा रहा है वह बहुत छोटा है इसलिए वहां पर कोई अस्थाई व्यवस्था हो जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई वहां पर ठीक तरीके से चले। मैंने यह पूछा है कि जो बगीचा है और जो आप वन विभाग की स्वीकृति की बात कर रहे हैं, अगर हो गई है तो आप बताएं कि इसकी स्वीकृति कब से हो गई है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति हो गई है। इस स्वीकृति को लगभग दो महीने हो गए हैं। आपको इसके लिए बधाई हो।

श्री बिक्रम सिंहः जो पैसा देहरा के लिए भेजना चाहिए था वह फतेहपुर के लिए भेज दिया?

मुख्य मंत्रीः वह पैसा विभाग ने गलती से भेजा होगा। जो चीफ इंजीनियर का ऑफिस है, वहां भेजा जाएगा। यह विभाग की गलती है। आपके हल्के में मैंने एक कॉलेज और दे दिया है और आपका एकमात्र हल्का होगा जिसमें तीन डिग्री कॉलेज होंगे।

श्री बिक्रम सिंहः सर, वह कॉलेज तो बन्द हो गया था।

मुख्य मंत्रीः वह तो आप कहते थे बन्द करने के लिए मगर आप लोगों की कोशिशों के बावजूद भी वह कॉलेज खुल गया है। (व्यवधान) आप लोगों ने वह कॉलेज नहीं खुलवाया है। आप लोगों ने कहा था कि यह कॉलेज यहां पर नहीं होना चाहिए। आपके क्षेत्र में यह

तीसरा कॉलेज भी खोल दिया गया है। आप लोगों को इस बारे में भी धन्यवाद करना नहीं आता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

06.03.2017/1455/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 3719

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो उत्तर यहां सभापटल पर रखा गया है इसमें लिखा है कि सड़क दोनों तरफ से 16 किलोमीटर एक और 10 किलोमीटर एक बन कर तैयार है लेकिन बीच में फॉरैस्ट एरिया है। अध्यक्ष महोदय, उतराला से गांव तर और तर से इलाका माता मंदिर की ओर नाले से अगर सड़क बनाई जाए तो कोई भी दरख्त बीच में नहीं आता है। यह सड़क बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना भी ऊपर का धौलाधार क्षेत्र है वहां जो लोग जीवन यापन करते हैं उनकी सारी रिश्तेदारी भरमौर क्षेत्र में है और उन्हें काफी समय बस में सफ़र करने के बाद चम्बा और होली जाना पड़ता है। इसलिए अगर यहां से सड़क बनाई जाए तो इसका फासला बहुत कम है और दोनों ज़िलों को आपस में जोड़ेगी। बैजनाथ-पपरोला का व्यापार बढ़ेगा और साथ में लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। यह बहुत पुरानी सड़क है और बड़ा पुराना मामला है। चार साल से मैं विधान सभा में इस मामले को उठाता रहा हूं। इससे पहले शायद सुधीर शर्मा जी दस साल उठाते रहे हैं तो कृपा करके इस सड़क को बनाया जाए। नया सर्वे करवाया जाए, इसमें कोई दरख्त नहीं आता है।

Chief Minister: Speaker Sir, total length of the Uttrala- Holi Road is 71 kilometers, out of which about 27 km road is completed and busable and balance 50km road is yet to be constructed. The area between Elaka Mandir and Bakhrud is dense forest and road could not be constructed. There was

a proposal to alternatively construct a Uttrala - Holi Tunnel, below Surahi Pass, but it has not been found economically viable. Therefore, now the department is preparing FCA case for the transfer of forest land so that balanced road work may start as soon as possible. **जहां तक आपका प्रश्न है कि इसका दूसरा अलाइनमैंट किया जाए तो उस पर भी सरकार विचार करेगी।**

प्रश्नकाल समाप्त

06.03.2017/1455/SS-DC/2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्षः अब सदन के नेता द्वारा वक्तव्य होगा। अब माननीय मुख्य मंत्री माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवायेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार से हैः-

सोमवार, 6 मार्च, 2017 - (1) शासकीय/विधायी कार्य।
(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - चर्चा।

मंगलवार, 7 मार्च, 2017 - (1) शासकीय/विधायी कार्य।
(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - चर्चा।

जारी श्रीमती के0एस0

06.03.2017/1500/केएस/एजी/1

बुधवार, 8 मार्च- (1) शासकीय/विधायी कार्य।
(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा

एवं पारण।

वीरवार, 9 मार्च- (1) शासकीय/विधायी कार्य।
(2) गैर सरकारी सदस्य दिवस।

शुक्रवार, 10 मार्च- (1) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2017-2018- प्रस्तुतीकरण।

06.03.2017/1500/केएस/एजी/2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब मुख्य मंत्री महोदय कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13(विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

06.03.2017/1500/केएस/एजी/3

सदन की समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर भी रखेंगें।

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17), का 32वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में संचालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

06.03.2017/1500/केएस/एजी/4

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

अध्यक्षः अब श्री रणधीर शर्मा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें तथा माननीय मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगें।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत मैं जनता से जुड़ा हुआ एक प्रमुख विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। लगभग पिछले तीन वर्षों से कीरतपुर से नेरचौक तक फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। उसके कारण जिन पंचायतों से वह फोरलेन सड़क गुज़र रही है, वहां के लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री नयनादेवी जी में यह फोरलेन री,स्वाहन, कुटैहला, टाली कल्लर इन पांच पंचायतों से होकर गुज़र रही है। और इन पांचों पंचायतों में वहां की स्थानीय जनता बहुत ही मुश्किल में है। अनेक तरह की दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही है और अभी 2 मार्च, 2017 को समाचार पत्र "अमर उजाला"ने जिस प्रमुखता से विषय उठाया है, मैंने पिछले सत्रों में भी इस पर चर्चा चाही थी लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया था। अभी नियम-62 के अंतर्गत आपने स्वीकृति दी इसके लिए अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। वहां जो ब्लास्टिंग हो रही है, जो भारी मशीनरी वहां पर काम कर रही है, उसके

कारण साथ लगते मकानों में दरारें पड़ गई है। कई बार मकान तक हिल जाते है और कम्पनी के अधिकारी उस तरफ ध्यान नहीं देते। सभी पंचायतों के गांव में यही स्थिति है। पिछले दिनों जब हालत काफी गम्भीर हुई थी तो कुटैहला पंचायत के थापना गांव में जाकर मैंने खुद स्थिति को देखा था। मैंने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया था और फोरलेन सड़क के निर्माण में लगी कम्पनी के अधिकारियों को भी बुलाया था। जिला का कोई प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं आया परन्तु फोरलेन कम्पनी के कुछ जुनियर अधिकारी आए थे। हमने घर-घर जाकर मौका किया, उनको दिखाया कि किस तरह से लोगों के मकानों में दरारें पड़ी है और उनको कहा भी कि उनकी मुरम्मत की जाए और जिन मकानों में ज्यादा दरारें आ गई है, रहने योग्य नहीं है, उनको एक्वायर किया जाए और उन मकान मालिकों को मुआवज़ा दिया जाए परन्तु अध्यक्ष महोदय फोरलेन निर्माण में लगी कम्पनी के अधिकारियों ने मुरम्मत शुरू भी की परन्तु दो दिन बाद ही वह मुरम्मत कार्य बन्द कर दिया गया। न तो उन मकानों की अब कोई रिपेयर की जा रही है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.3.2017/1505/av/ag/1

श्री रणधीर शर्मा ----**क्रमागत**

और न ही क्षतिग्रस्त हुए मकानों को मुआवजा देने या ऐक्वायर करने का प्रोसैस शुरू हुआ है। हालात ऐसे हैं कि जिन दिनों वहां पर ब्लास्टिंग होती है तो इन गांवों में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है और लोग घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहां जाकर रातें गुजारते हैं। ऐसी स्थिति उन गांवों / क्षेत्रों में ब्लास्टिंग होने पर पैदा होती है परंतु बार-बार बोलने के बाद और मीडिया में विषय उठाने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी तथा सरकार के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके कारण वहां पर और भी कई तरह की समस्याएं खड़ी हुई है। फोर-लेन सड़क का निर्माण होने से वहां पर धूल-मिट्टी उड़ती है। घरों में धूल-मिट्टी जाती है, यहां तक कि साथ के जो खेत और घासणियां इत्यादि हैं वहां घास-पत्तों पर धूल-मिट्टी होने की वजह से वह घास भी काम नहीं आता जिसके कारण किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके अतिरिक्त स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि शुरू में बैठक में यह प्रावधान किया गया था कि पानी

छिड़का जायेगा। मगर अब वहां पर कोई पानी नहीं छिड़काता है और जब स्कूल के बच्चे अपने घर से चलते हैं तो स्कूल तक पहुंचने में उनकी सफेद कमीजें काले रंग में तबदील हो जाती हैं। इसके कारण वहां के बच्चों को अनेक बीमारियां लग रही हैं। इसी तरह से वहां गांव घरा, मोढ़ू, वघेरी, सनण-सन्धेली, हरिजन बस्ती कुरला, स्वैहण गांव में करमाला-मैला कैंची मोड़, कुटेला में थापना नरली, टाली में टाली-भटैड़ गांव, कलर में तुन्नु और पट्टा गांव है। इन सभी गांव के रास्ते इस फोर लेन सड़क निर्माण से टूट गये हैं। छोटी-छोटी पालंगरियां हैं, कई जगह तो घर अलग-अलग है और उन घरों को रास्ते हैं। सारे रास्ते तहस-नहस हो गये हैं। बार-बार कहने के बाद भी उन रास्तों की मुरम्मत नहीं करवाई जा रही है। वहां के ग्रामीणों को रात को तो क्या दिन को जाना भी परेशानी का सबब बना हुआ है। अभी एक मीटिंग जिला स्तर पर हुई थी और हमने इस विषय को वहां पर भी उठाया था परंतु बावजूद उसके इस पर कोई अमल नहीं किया गया। यही नहीं, इसके अलावा पीने के पानी के स्त्रोत सूख गये हैं। कई जगह तो बावड़ियों और कुओं इत्यादि में मिट्टी

6.3.2017/1505/av/ag/2

भर दी गई है क्योंकि ठेकेदार अपनी मर्जी से हर कहीं मिट्टी फेंक देते हैं। कहीं पर भी डंपिंग साइट नहीं है जिसके कारण पीने के पानी के स्त्रोत सूख गये हैं और पानी की दिक्कत हो रही है। कई जगह पेयजल स्कीम की पाइप लाईन टूट गई है उसकी मुरम्मत नहीं होती। हैंड पम्प टूट गये हैं उनकी मुरम्मत नहीं होती। अभी सर्दियों में भी इन पांचों पंचायतों में पीने के पानी का गम्भीर संकट खड़ा हो गया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त जो कैंची मोड़ पर सुरंग बन रही है उसमें अगर हम या आप क्रोस करेंगे तो देख सकते हैं कि उस सुरंग से पानी निकल रहा है। उस पानी में कैमिकल मिले हुए हैं। वह पानी नीचे खड्ड में मिलता है। वहां नीचे जो गांव हैं उन गांव के लोगों के पशु वहीं पानी पीते हैं। वहां हमारी एक हरिजन बस्ती कुरला है जहां पिछले एक महीने में इस विषैले पानी के कारण 5 बैलों की मृत्यु हुई है। उसका प्रशासन या सरकार कोई समाधान नहीं निकाल रही है जिसके कारण वहां किसानों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़

रहा है। कई बार पीने का पानी स्कीम में नहीं आता और लोगों को मज़बूरन इस पानी को यूज़ में लाना पड़ता है जिसके कारण उनको बीमारियां लग रही हैं। इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वहां पर जो पीने के पानी का संकट खड़ा हुआ है उसका भी समाधान हो सके। इस फोर लेन के लिए वहां पर केवल 45 मीटर तक जमीन ऐक्वायर की है। वहां 45 मीटर एरिया तक की खुदाई की जा रही है परंतु कई जगह 45 मीटर के साथ लगते ही मकान है। वहां कोई रिटेनिंग वॉल नहीं लगाई जा रही है। मान लो पहाड़ी है कटिंग कर दी और ऊपर मकान है

श्री वर्मा द्वारा जारी

06/03/2017/1510/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्री रणधीर शर्मा - - - जारी

और न ही उन मकानों को एक्वॉयर किया जा रहा है। क्योंकि 20-20, 25-25 मीटर तक कटिंग कर दी गई है, इसलिए वह मकान कभी भी गिर सकते है। अब लोग इन मकानों में रह ही नहीं पा रहे हैं, परन्तु बार-बार कहने के पश्चात् भी इन मकानों को एक्वॉयर नहीं किया जा रहा है और न ही उनको मुआवज़ा दिया जा रहा है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इन मकानों को एक्वॉयर कर काम्पन्सेशन दिया जाए और साथ लगती ज़मीन, जिस पर फसल नहीं होती है, यदि उस ज़मीन को भी एक्वॉयर करेंगे, तो वहां के लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस फोरलेन सड़क निर्माण में जो रोजगार मिल रहा है, वह भी वहां के स्थानीय प्रभावित लोगों को नहीं मिल रहा है। कंपनी के लोगों ने आगे-से-आगे टैंडर दे रखे हैं, एक भाग की कटिंग का टैंडर किसी एक ठेकेदार को दे दिया और आगे 4 किलोमीटर तक कटिंग का टैंडर किसी और ठेकेदार को दे रखा है। इन ठेकेदारों के पास सारा काम बाहर के नौजवान कर रहे हैं, जबकि इन प्रभावित पंचायतों के बेरोज़गार में बी-टेक, आई0टी0आई0 और डिप्लोमा होल्डर भी वहां पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेलदार, सुरक्षागार्ड और सुपरवाइजर का काम करने के लिए भी स्थानीय नौजवान दक्ष हैं और वे इस काम को कर सकते हैं। परन्तु ये कंपनियां सारे लोगों को बाहर से लाकर उनको

रोजगार दे रहे हैं। हालांकि यह टैंपरेरी रोजगार होगा, परन्तु टैंपरेरी रोजगार भी अगर स्थानीय नौजवानों को मिलता है, तो भी उनकी किसी-न-किसी तरह से मद्द होगी। इतने संकट सहकर भी वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि वह फोरलेन में जो अधिकारी है, उनको निर्देश दें कि जो भी वहां रोजगार देना है, वह प्राथमिकता के आधार पर वहां की स्थानीय पंचायत के प्रभावित नौज़वानों को दिया जाये। अगर वहां पर कोई इंजीनियर उपलब्ध नहीं है, तो फिर बहार के लोगों को रोज़गार दिया जाये, अन्यथा वहां के स्थानीय लोगों को तरजीह दी जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बड़ी गलती हुई है, सरकार ने काम्पन्सेशन देने के लिए फैक्टर-॥ लागू नहीं किया। उसके कारण किसानों को मुआव़जा कम मिला। क्योंकि उनकी वही ज़मीन नहीं गई जिसमें सड़क बन रही है, उनकी तो साथ लगती कई-कई बिघा ज़मीन बरबाद हो रही है और

06/03/2017/1510/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगर सरकार फैक्टर-॥ लागू कर देती, तो उनको चार गुणा ज्यादा मुआव़जा मिलता। लेकिन सरकार ने फैक्टर-॥ लागू नहीं किया इसलिए न तो लोगों को उतना ज्यादा मुआवज़ा मिला और न ही उनको रोज़गार मिल रहा है। इसके साथ ही उनको कई अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये समस्याएं मेरे विधान सभा क्षेत्र की 5 पंचायतों में है। इसके अलावा श्री रिखि राम कौंडल जी (झण्डूता) का भी यही कहना है कि वहां पर भी लोगों को इसी प्रकार की समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। श्री बम्बर ठाकुर जरूर डरा-धमका कर कुछ काम करवा लेते होंगे, लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्र में तो हालात बहुत ही खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह फोरलेन कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दें और चुने हुए प्रतिनिधियों, पंचायत प्रधान, विधायक, और सांसद के साथ बैठक करवाई जाये। ताकि जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर किया जायें। हर महीने एक बैठक हो और जो समस्याएं हो उनका समाधान किया जाये। इसी प्रकार दूसरी बैठक में उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। ताकि जो डे-टू-डे समस्याएं आती है, उनका समाधान हो सकें

और जिन समस्याओं ने स्थाई रूप ले लिया है, उनका भी हम समाधान कर पायें। ये समस्याएं इसलिए खड़ी हुई है कि सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए तैयारी नहीं की थी, आने वाले समय में नेर-चौक से मनाली फोर-लेन का काम भी शुरू होने वाला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वहां पर फैक्टर-॥ लागू हों, ताकि वहां के किसानों को फ़ायदा हो सके।

श्रीमती एन0एस0 - - - द्वारा जारी।

06/03/2017/1515/ns/as/1

श्री रणधीर शर्मा ------जारी।

इसलिए मेरा आग्रह है कि वहां पर फैक्टर-टू लागू हो, वहां के किसानों को फायदा हो और वहां पर ये समस्यायें लोगों को न फेस करनी पड़ें। इसलिए पहले से ही तैयारी हो। विशेषकर हमारे विधान सभा क्षेत्र की पांचो पंचायतों के इन गांवों में लोगों को टूटे हुए रास्तों और पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मकानों में जो दरारें ब्लास्टिंग और भारी मशीनरी के चलने के कारण आ रही हैं (घण्टी) उनको मुआवज़ा दिया जाए और उनकी रिपेयर करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही आग्रह आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मैं आपकी अनुमति से दिनांक 2 मार्च, 2017 को अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "**फोरलेन की जद में मकान; ब्लास्टिंग से दरारें, दहशत में कट रहीं रातें**", से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

06/03/2017/1515/ns/as/2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाये गए मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-

निःसंदेह इन्होंने एक गम्भीर विषय की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मगर जो वस्तुस्थिति है उससे मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फोरलेन निर्माण का कार्य ।L&FS कंपनी को दिया गया है तथा यह कम्पनी देशहित व समरिक महत्व के इस प्रोजैक्ट (किरतपुर, पंजाब से नेर-चौक, हिमाचल प्रदेश तक) फोर लेने का काम कर रही है और जिसमें सुरंग निर्माण का कार्य भी शामिल है।

जहां तक फोरलेन निर्माण के जद में आए गांवों और गांवों के घरों को नुकसान पहुंचाने की बात है या कैंची मोड़ आदि बनाने का प्रश्न है तो वह निर्माण कार्य का एक हिस्सा है। माननीय सदस्य ने कहा है कि यहां पर बहुत नुकसान हो रहा है और इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। वहां पर कंपनी के ऑफिसर्ज़ आए थे वे भी देख कर चले गए। वहां पर घरों और खेतों को नुकसान हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि यह सड़क राष्ट्रीय स्तर की सड़क है और यह सड़क न केवल हिमाचल को जोड़ने के लिए बल्कि देश को जोड़ने के लिए समरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण सड़क है, इसलिए यह सड़क निर्बिघ्न बने। इसमें अगर हमें थोड़ी-बहुत तकलीफ़ होती है तो वह हमें सहनी चाहिए। मगर वहां पर खेतों को नुकसान हो रहा है, गांवों को नुकसान हो रहा है, जन-जीवन में इसकी वज़ह से एक कुण्ठा पैदा हुई है तो वह भी सही नहीं है। माननीय सदस्य ने इसके बारे में बहुत लम्बा ब्यान दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इनका कन्सर्न है वह हमारा भी कन्सर्न है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो किसान है या जहां से भी सड़कें बन रही हैं उसकी वज़ह से जो भी बेघर हुए हैं उनको ठीक से बसाने का इंतज़ाम हो। जिनकी जमीनें गई हैं उनको उचित मुआवज़ा मिले।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी।

06/03/2017/1520/RKS/DC/1

मुख्य मंत्री .....जारी

अगर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ख़लल पड़ा है, वह भी न हो। मैं जिलाधीश बिलासपुर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करुंगा जोकि आपके क्षेत्र का दौरा करेगी। कमेटी हर गांव और हर मौके पर जाएगी और आप उस कमेटी को जो भी कहना या बताना चाहते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनको मौका दिखा सकते हैं। दूसरे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद के लोग हैं वे भी आ सकते हैं ताकि मौके पर ही इस समस्या का समाधान हो सके। आपका हुल्लड़ सड़क बनाने के बारे में नहीं है, मगर जिस तरीके से काम हो रहा है और उस काम से जो नुकसान हो रहा है, उसके बारे में है। उस पर ध्यान दिया जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि इसका निराकरण शीघ्र हो ताकि सड़क भी बिना किसी रुकावट के बने और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई कष्ट न हो।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी, क्या आप कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहेंगे?

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने जनता की इन समस्याओं पर अपना कंसर्न व्यक्त किया है और उसके समाधान के लिए जो कमेटी जाएगी, क्या उनको माननीय मुख्य मंत्री जी यह निर्देश देंगे कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें पहले सूचित कर दें कि वे किस दिन जाएंगे ताकि उसमें संबंधित विधायक, जिला परिषद, बी.डी.सी. और पंचायतों के जो प्रधान हैं वे उस दिन वहां मौके पर उपस्थित रहें। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जिलाधीश महोदय को यह निर्देश करेंगे?

मुख्य मंत्रीः मैं यह आदेश करुंगा, तभी तो मैंने हाउस में यह बोला है। I have given commitment on the Floor of the House.

06/03/2017/1520/RKS/DC/2

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैंने यह भी कहा था कि जो स्थानीय नौजवान है उनको रोज़गार देने के लिए क्या कम्पनी के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे? जो छोटी-छोटी नौकरियां हैं वे भी बाहर के नौजवानों को दे दी जाती है। अगर उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी गार्ड, आई.टी.आई., क्लर्क और इंजीनियर लगना चाहता है तो क्या इस और भी कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त जो फैक्टर-2 है जिसके कारण किसानों को चार गुना ज्यादा मुआवज़ा मिलना है, क्या सरकार फैक्टर-2 को लागू करेगी ताकि किसानों को ज्यादा-से-ज्यादा मुआवज़ा मिल सके? इसमें प्रदेश सरकार को कुछ नहीं देना है, केन्द्र सरकार ने ही यह मुआवज़ा देना है तो ऐसे में क्या सरकार किसानों के हित के लिए फैक्टर-2 लागू करेगी?

मुख्य मंत्रीः यह आपने अपने वक्तव्य में नहीं कहा है। यह आपने नई बात उठाई है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवज़ा मिले।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, 3 वर्ष से कोशिश ही हो रही है।

मुख्य मंत्रीः हमने कहा हम इसके लिए आपसे भी ज्यादा कोशिश करेंगे। जहां तक स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है यह सिर्फ एक सड़क पर लागू नहीं है जितनी भी नेशनल हाईवेज़ बन रही हैं, जहां-जहां भी सड़कों का काम हो रहा है,

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

06.03.2017/1525/SLS-DC-1

माननीय मुख्य मंत्री...जारी

हम चाहेंगे कि ठेकेदार छोटे-छोटे कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को रोज़गार दें। यह मैं इससे पहले भी कहता आया हूं और अब भी कहूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि atleast I am not satisfied with the work they are doing till now. जहां तक रोज़गार का प्रश्न है, इसमें बड़े लोगों को तो उन्होंने अकमोडेट किया है मगर जो आम आदमी है या गरीब आदमी हैं जो छोटे काम करना चाहते हैं, छोटी ठेकेदारी करना चाहते हैं, सब-कंट्रैक्ट पर काम करना चाहते हैं या मज़दरी का काम करना चाहते हैं, टेक्निशियन का काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज्यादा मौक़े होने चाहिए।

समाप्त

06.03.2017/1525/SLS-DC-2

<u>सांविधिक इकाई हेतु मनोनयन</u>

अध्यक्ष : अब सांविधिक इकाई हेतु मनोनयन होगा।

अब माननीय मुख्य मंत्री महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, कालूझण्डा, जिला सोलन की सीनेट में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का मनोनयन करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section17(1) of First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District

Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities."

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section17(1) of First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities."

06.03.2017/1525/SLS-DC-3

तो प्रश्न यह है "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section17(1) of First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities."

(प्रस्ताव स्वीकार)

भारद्वाज जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव में दो मैंबर इलैक्ट करने का प्रोविजन है। इसमें कहीं भी यह शब्द नहीं लिखा है कि इन्हें नोमिनेट किया जाएगा या इनका इलैक्शन कैसे होना है। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। जब इलैक्शन होना है तो उसका प्रोसीजर हाऊस में आना चाहिए था। ...(व्यवधान)... अप्लाइड नहीं होता, नोमिनेट होता है। The Speaker is authorized, it is written always. It has not been written here that it is with the Speaker and

जारी .. श्री गर्ग जी

06/03/2017/1530/RG/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज की अंग्रेजी के पश्चात----क्रमागत

my second contention is कि इस सदन में 27 सदस्य भारतीय जनता पार्टी को बिलांग करते हैं, डायरैक्ट या इनडायरैक्ट तौर पर चुनाव होता है या अनुपातिक प्रपोरशन से होता है। जैसे राज्य सभा के लिए भी यदि एक से ज्यादा सीटें होती हैं, तो उसमें भी दूसरे पक्ष को सीट मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में इतने विश्वविद्यालय हैं कि इनके पास वहां पर भेजने के लिए सदस्य भी नहीं होते और कई जगह ये अपने सी.पी.एस. को भी भेज देते हैं। तो जो हमारे 27 सदस्य हैं और इधर निर्दलीय सदस्य हैं क्या आप इधर भी कभी अपनी नजरें इनायत करेंगे कि इनमें से भी कुछ लोग नॉमिनेट हो सकें?

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में इस विधान सभा में इस बात का कुछ-न-कुछ प्रावधान भी आपके कार्यकाल में होना चाहिए।

Speaker: There is no such provision.

संसदीय कार्य मंत्री : जब हम भी 30-31 सदस्य विपक्ष में होते थे, तो क्या आपके कार्यकाल में कभी ऐसा किया गया?

श्री सुरेश भारद्वाज : हमने नहीं किया, तो आप शुरू कर दें।

Speaker: Please look sharp. There is no such provision though this Assembly is authorized to go ahead to nominate two Members out of the Members or they can authorize the Speaker to nominate two Members. This is the procedure. There is no such procedure that the Opposition or the Ruling Party should get two Members. There is no provision. The Assembly as a whole can nominate two Members out of the Members.

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, हम तो आपको ही कह रहे हैं कि if the Speaker is authorized . . .

अध्यक्ष : प्रोसीजर ही यही है I have placed this Resolution at the disposal of the House. Now, the House has to decide.

06/03/2017/1530/RG/AG/2

श्री सुरेश भारद्वाज : इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि Speaker is authorised to nominate the Members, इसमें तो इलैक्शन लिखा है कि इलैक्शन हो, इलैक्शन का प्रोसीजर आप तय करें और इलैक्शन हो जाएगा।

Speaker: The House may authorize or may not authorize.

Shri Suresh Bhardwaj: It is written. जब तक सदन में यह नहीं होगा तब तक कैसे होगा? इसमें कहां लिखा हुआ है, इसमें तो लिखा हुआ है कि इलैक्शन होना है। इसलिए आप इलैक्शन कराइए और हम उसमें नाम भरेंगे।

अध्यक्ष : इलैक्शन नहीं है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर पढ़ा है, इसमें लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section17(1) of First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State

Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years" इसमें इलैक्शन लिखा है, नॉमिनेशन नहीं लिखा है। अध्यक्ष महोदय, यदि आपको प्राधिकृत किया है, तो आप बैलेंस बनाकर चलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा तो आपको यह सुझाव है और भविष्य के लिए भी सुझाव है कि हमारी जो स्ट्रैन्थ है या जब एक तिहाई से ऊपर सदस्य आते हैं, तो उसमें एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष से तथा इसके अलावा यहां चार निर्दलीय सदस्य भी बैठे हैं, इनमें से चुन लिए जाएं। हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है।

Speaker: There is no provision for making a balance.

संसदीय कार्य मंत्री : ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री रविन्द्र सिंह : यह तो आपको शुरू करना चाहिए था।

06/03/2017/1530/RG/AG/3

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह कह रहे हैं कि इसमें इलैक्शन लिखा हुआ है इसमें नॉमिनेट नहीं लिखा है या आपके अधिकारियों ने नहीं लिखा है, इसमें अथॉराईज कहां लिखा है?

Speaker: Either the House can elect two Members or they can authorize the Speaker to nominate two Members. There is no provision for compromising with other Members also. Out of any Member you may choose.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको अमण्ड करिए।

Health & Family Welfare Minister: Sir, this is implied. Every time this Resolution is moved by the Chief Minister or the respective Minister, it is

implied that the Hon'ble Speaker is authorized to make nomination. This is implied. This is a precedent, convention and tradition also.

एम.एस. द्वारा प्रो. प्रेम कुमार धूमल हिन्दी में शुरू

06/03/2017/1535/MS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः प्रोसैस सीधा होता है। It is never implied. It is superficially mentioned that the House may authorize the Hon'ble Speaker to nominate two Members. वह शब्दावली नहीं है। इसलिए इसको विड्रो किया जाए। अगर आपको ऑथोराइज करना है तो कल रेजोल्यूशन लाएं। फिर इसको करेंगे या फिर इस शब्दावली में तो इलैक्शन होगा।

Speaker: My view is . . .

Prof. Prem Kumar Dhumal: Your view is not required here. Resolution is moved already.

Speaker: I have to give my views.

Prof. Prem Kumar Dhumal: No, no. Your views are not invited, Sir.

Speaker: You have raised a question. I must give my view in that. You have raised a question.

Prof. Prem Kumar Dhumal: We will listen to your views and then explain to you.

Speaker: The language here is the Members to be elected by the House here or if they like they can authorize the Speaker to nominate. They can authorize. But if the House doesn't give me power, then you can do it right now. The House is authorized.

श्री रविन्द्र सिंहः ऐसा कहां लिखा है?

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी गलत नहीं है। आप क्यों फस रहे हैं?

अध्यक्षः मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रोसिजर की बात कर रहा हूं। I am talking about the procedure. This has been going on for at least half a century. धूमल जी बोलिए।

06/03/2017/1535/MS/AG/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव की शब्दावली यही होती है कि सदन चुनेगा या सदन ऑथोराइज करेगा माननीय अध्यक्ष महोदय को कि वे दो माननीय सदस्यों को मनोनीत कर दें। वह शब्दावली इसमें नहीं है। इस शब्दावली में अगर होगा तो इलैक्शन होगा। नहीं तो इसको विड्रो करे और कल को ले आएं। आपको नोमिनेट करने का अधिकार देना हो तो भी दिया जा सकता है लेकिन प्रौपर प्रोसैस तो अप्लाई कीजिए।

Speaker: It is upto the Government.

संसदीय कार्यमंत्रीः आपके समय में भी यही लिखा जाता था। -(व्यवधान)- एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने काफी युनिवर्सिटीज खोलीं और उसमें भी यही लिखा जाता था। अगर आपको इस पर एतराज है तो माननीय मुख्य मंत्री जी इसको संशोधित रूप से पारित करने के लिए कह देंगे। इसलिए मुख्य मंत्री जी आप ऐसा कर दें।

Chief Minister: Sir, in addition to what I have said earlier, I want to add that the House authorizes the Speaker to nominate two Members.

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ " That House do proceed to authorised the Hon'ble Speaker to nominate two members in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years

commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities."

जो इसके पक्ष में है हां कहें और जो इसके विरूद्ध हैं न कहें,
हां की, हां की, हां में रही,

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार।

There is an amendment from the Government. (व्यवधान)

06/03/2017/1535/MS/AG/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव दिया तो आपको वहां से उसको पुट करना होगा कि एज अमैंडिड, इस तरह से करो। उस पर फिर हां या न होगी। आपने एज अमेंडिड नहीं बोला।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार हमारी कमेटी का बिहार का टूर था और हम बिहार की असैम्बली को देखने के लिए चले गए। यहां आज का दृश्य देखकर मुझे उस समय का वह समय याद आ रहा है। वहां विधान सभा भवन की गैलरी में सत्र देखने हम भी वैसे ही बैठे थे जैसे अभी माननीय सांसद महोदय यहां गैलरी में बैठे हुए हैं। वहां सत्र चला हुआ था और वह असैम्बली भी बहुत बड़ी है। वहां पर एक मंत्री ने बिल इन्ट्रोड्यूस किया और कुछ नहीं बोला। हां की, हां में और न की, न में और बिल पास। वह स्थिति आज आपने पैदा कर दी है। वह जो इसमें लिखा है उसको अमैंडिड फोरम में मुख्य मंत्री जी लेकर तो आए। अध्यक्ष जी, हमें कोई एतराज नहीं है चाहे आप ही पढ़ दो कि अमेंडिड फोरम में इसको यहां पर इन्ट्रोड्यूस कर दिया।

अध्यक्षः वह अमेंड कर दिया है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, नहीं किया है।

अध्यक्षः गवर्नमैंट ने अमेंड कर दिया है। (व्यवधान) Then I speak the other way. अमेंडिड फोरम में,

(प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार)

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

06.03.2017/1540/जेके/एएस/1

<u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा</u>

अध्यक्षः अब महामहिम् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसमें हमारे पास 12 माननीय सदस्य बोलेंगे और 10 से 11 मिनट तक एक सदस्य को समय दिया गया है। इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष को 30 मिनट मिलेंगे और साथ में सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे 10 से 11 मिनट ज्यादा न बोलें ताकि धन्यवाद प्रस्ताव में जो लोग बोलना चाहें वे सभी के सभी बोल पाएं। अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आगे चर्चा होगी। सर्वप्रथम मैं, विपक्ष के नेता, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी को चर्चा आरम्भ करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम् राज्यपाल महोदय ने सत्र के पहले दिन ही विधान सभा को सम्बोधित करते हुए सरकार द्वारा प्रस्तुत भाषण को पढ़ा और सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव 3 मार्च को प्रस्तुत और अनुमोदित हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण पूरे वर्ष का ब्योरा होता है कि सरकार ने क्या-क्या किया और बजट अभिभाषण आने वाले वर्ष का प्लान प्रस्तुत करता है। जब राज्यपाल महोदय सम्बोधित करने के लिए आए तो हम सोच रहे थे कि ये क्या बोलेंगे? उन्होंने आते ही पीठ से कहा कि " **असतो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य,** मृत्योर्माअमृतं गमय" असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। चूंकि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वह तो इस सरकार ने लिखा और पढ़ने का जिम्मा उनका था इसलिए उन्होंने पहले ही ईश्वर से कह दिया कि इस असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, इसलिए वे यह भी कह गए कि अब आलोचना होगी तो उसे शांतिपूर्वक सुनना।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे ही पैराग्राफ में माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र जो हमारे लिए एक नीति दस्तावेज है इसमें सभी वायदों को पूरा कर दिया गया है। मैं वह चुनावी घोषणा पत्र लाया हूं। इसमें 317 के करीब बिन्दु आपने लिखे थे। वैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा था कि कुछ अनुभवहीन लोगों ने इस चुनावी घोषणा पत्र को बनाया है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

06.03.2017/1545/SS-AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

और वह बात सही थी। अध्यक्ष महोदय, जो इसके चेयरमैन थे उनके पास केन्द्र में उस समय कॉमर्स विभाग था। सेब के आयात पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होगी, यह वही विभाग तय करता है। वह 2012 में चुनाव घोषणा पत्र बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि इसको कम-से-कम तीन गुणा करवायेंगे। 50 प्रतिशत तो ड्यूटी है जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लगाई थी। मेरे पास एक पत्र पड़ा है जो उस समय के बागवानी मंत्री, श्री नरेन्द्र बरागटा ने उन मंत्री महोदय को लिखा था और कहा था कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए ताकि सेब को मार्किट में बचाया जा सके, ज्यादा कम्पीटिशन न हो। तो 2011 में वे मंत्री लिख रहे हैं कि it is the highest. प्रैजैंट रेजीम में 50 परसैंट से ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग सकती, वह लगा दी गई है और 2012 में वही मंत्री आ कर उस कमेटी का चेयरमैन बनता है जो आपका मैनिफैस्टो लिखती है और कहता है कि कम-से-कम तीन गुणा बढ़ायेंगे। लिखित तौर पर दिया है। तो सचमुच में मुख्य मंत्री महोदय का वह कमैंट बिल्कुल ठीक है कि लोग अनुभवहीन थे। अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में कुशल वित्तीय प्रबन्धन के बारे में लिखा है। फाइनैंशियल मैनेजमैंट का ज़िक्र किया गया है कि इसके माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से राजस्व में आय वृद्धि के लिए प्रयत्न किये जायेंगे।

हमारे चार साल के कार्यकाल में 4 हजार करोड़ के एडिशनल रेवेन्यू रिसीट्स हुए थे और इनके चार साल में 30 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो रेवेन्यू का फाइनैंशियल मैनेजमैंट जो इन्होंने बड़ा एफिशियंट किया, वह आपको बता दिया। अब तो मुख्य मंत्री पब्लिकली बोलते हैं कि जुगाड़ से सरकार चला रहे हैं। जुगाड़ू नहीं बल्कि जुझारू सरकार की आवश्यकता है। रिसोर्स मोबेलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए था, वह हुआ नहीं। दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए प्रयास किया जायेगा लेकिन दीर्घकालीन ऋण लिये गये। दीर्घकाल में तो वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो जायेगी जो हालात लग रहे हैं।

06.03.2017/1545/SS-AS/2

अध्यक्ष महोदय, अगला वायदा था कि हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु खाली पदों पर निष्पक्ष चयन लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा किया जायेगा। जो भर्तियां हो रही हैं वह सरकार बताए कि कितनी बैकडोर से हो रही हैं। पब्लिक सर्विस कमिशन से कितनी हुईं, सबोर्डिनेट सर्विसिज़ सिलैक्शन कमिशन से कितनी हुईं और डिपार्टमैंटल कितनी बैकडोर एंटरीज़ हो रही हैं। आप आउटसोर्स पर रखे गए लोगों को रेगुलर करने की बात कर रहे हैं और पुलिस के कॉंस्टेबल कॉंट्रैक्ट पर भर्ती कर रहे हैं। 8 साल के लिए कॉंट्रैक्ट पर बात कही गई, पिछले साल इसको एक साल कम करके 7 साल कर दिया और यही कारण है कि जिन सेवाओं में रेगुलैरिटी चाहिए वे सेवाएं लड़खड़ा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, बैंक की भर्ती का इंस्टिच्यूशन, मुम्बई में है जिसके माध्यम से निष्पक्ष भर्ती होती थी

श्रीमती के0एस0

06.03.2017/1550/केएस/डीसी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी----

वह छोड़कर ऐजुकेशन बोर्ड को काम दिया गया है जिनसे अपनी परीक्षाएं ही समय पर नहीं ली जाती। आपने पेज नं0-6 पर वायदा किया, प्रशासनिक कमिशन गठित करके प्रदेश की सभी तहसीलों, उप-तहसीलों, उप मण्डल तथा जिलों की सीमाओं को प्रशासनिक सुविधानुसार पुनः निर्धारित किया जाएगा। उस कमिशन का गठन कब हुआ? कौन उसका चेयरमैन बना, क्या यह वायदा पूरा हो गया है? एक बहुत बड़ा जो आश्वासन दिया गया था, वह था- राज्यस्तर पर सशक्त पब्लिक ग्रिवांस कमिशनर नियुक्त किए जाएंगें ताकि जनता की शिकायतें सरकारी लाल फीताशाही में महीनों और सालों दब न जाएं। हर शिकायत का निश्चित समय के भीतर जवाब न देने पर सरकारी मंत्रालय और ऑफिसर की पूर्ण जवाबदेही तय की जाएगी और ग्रिवांस कमीशनर को हक प्राप्त होगा कि दोषियों को सजा दे सकें। इस सदन के सभी माननीय सदस्य मुख्य मंत्री से लेकर प्रत्येक मंत्री को और अधिकारियों को पत्र लिखते हैं। मैं चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी उत्तर दें तो आंकड़े दिए जाएं कि कितने पत्रों के उत्तर दिए गए। हमें कभी-कभार किसी मंत्री का उत्तर तो आ जाता है लेकिन मुख्य मंत्री कार्यालय से उत्तर नहीं आते।,अन्य कार्यालयों से उत्तर नहीं आते। पब्लिक ग्रिवांसिज आम आदमी की कहां तय हो पाई, यह वायदा कहां पूरा हुआ?

इसी तरह से भय एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात की गई है। भ्रष्टाचार के ऊपर मैं बाद में बात करुंगा। अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण वायदा था कि नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से प्रत्येक कार्य को करने हेतु समयबद्ध एवं पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा। सिटिजन राइट्स चार्टर कहां है? किस सिटिजन को आपका , किसको अधिकार दिया? तो ये वायदे शत-प्रतिशत कहां पूरे हुए हैं? मैंने कहा 317 में से 200 वायदे ऐसे हैं जो टच ही नहीं किए गए।

कृषि के लिए समयबद्ध आधार पर शीघ्र सभी बकाया सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष बजट प्रदान किए जाएंगें। कितना स्पैशल बजट दिया? सिंचाई के लिए क्या नया बना? पांच वर्षों में 40 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम कर

06.03.2017/1550/केएस/डीसी/2

दिया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ाई जाएगी। कोई सुविधा नहीं बढ़ी। जो एच.पी.एम.सी. का परवाणू में कोल्ड स्टोरेज था, वहां बागवानों के सेब सड़ गए। उनको मुआवज़ा नहीं मिला। जो पुराने थे उनको आप मेंटेंन नहीं कर पाए तो नए कहां से देंगें? नकली बीजों, उर्वरक एवं कृषि दवाओं का व्यवसाय करने वालों को दंड देने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। इस सदन में तो ऐसा कोई बिल आया ही नहीं तो यह वायदा कब पूरा हो गया?

बिचौलियों और दलालों से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए मण्डियों का निर्माण किया जाएगा। ये कहां बनी? राज्य एग्रिकल्चर कमिशन का गठन किया जाएगा। हमने तो सुना नहीं कि हिमाचल में एग्रिकल्चर कमीशन बना हो।

बागवानों को बड़ी उम्मीद थी कि बागवानों की सरकार बनी है। आपने हेलनैट के बारे में जवाब दिया कि 729 किसानों को आपने हेलनैट लगाने के लिए पिछले साल तक सबसिडी दी थी। लाखों किसान/बागवान प्रदेश में हैं। अगर 729 को दी है तो कितनी दे पाए आप?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

6.3.2017/1555/av/dc/1

श्री प्रेम कुमार धूमल जारी

और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐंटी हेल गन स्थापित करना शुरू की थी। जिन तीन जगह हमने स्थापित की थी उसका अनुकरण करते हुए बागी आदि के क्षेत्रों में बागवानों ने अपना पैसा इकट्ठा करके वह ऐंटी हेल गन लगाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई थी। अब हर जगह से डिमाण्ड आ रही है कि वह लगनी चाहिए। आपने उसको केवल इस करके रिजैक्ट कर दिया क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लगी थी। फलों की नई किस्में विकसित करने के लिए

अनुसंधान केंद्र खोले जायेंगे, कितने केंद्र खोले? आप इटली से 10 करोड़ रुपये की राशि से सेब की नई पौध लाये हैं। उसकी टैस्ट रिपोर्ट यशंवत सिंह परमार युनिवर्सिटी से आई है कि उसको बीमारी लगी हुई है। मेरे पास उस रिपोर्ट की कॉपी है। बागवानों को आपने नये पौधे तो क्या देने उल्टे बाहर से एक बीमारी लाकर दे दी है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि शिक्षा पर बहुत महत्व दिया जायेगा और दिया गया। मैंने शिक्षा विभाग से कुछ आंकड़े लिये जिसके अनुसार 46 नये कॉलेज खोले गये हैं। मैं पिछले दिनों जिला कांगड़ा में गया था। लन्ज के पास जा रहा था तो वहां पर सड़क के राइट हैंड साइड एक प्राइमरी स्कूल आता है। वहां बोर्ड लगा हुआ है 'गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज'। मैंने कहा कि पिछले हफ्ते यहां से गया था तो प्राइमरी स्कूल था तो बताया गया कि परसों मुख्य मंत्री जी आए थे और अब प्राइमरी स्कूल की जगह गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज हो गया। आज आपने कह ही दिया कि रक्कड़ में आपने एक लाख रुपये दिया।

मुख्य मंत्री : एक लाख रुपये नहीं है 5 करोड़ रुपये दिया है। 5 crore rupees have been given to the college. 5 करोड़ लन्ज के लिए और 5 करोड़ डाडासिबा के लिए दिया है। इसके अतिरिक्त जो इनके हलके में नया कॉलेज खोला गया है उसके लिए 5 करोड़ रुपये की राशि दी है। This is start up with.

6.3.2017/1555/av/dc/2

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष जी, मेरे पास जवाब है और मैंने इसको खुद पढ़ा है। मैं इसको देखकर ही बोल रहा हूं और जो फतेहपुर एक लाख रुपये भेजा है वही है। (---व्यवधान---) 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं मगर कॉलेज के लिए पैसा एक लाख रुपये ही दिया गया। (---व्यवधान---) डाडासिबा में प्राइमरी स्कूल में कॉलेज और उसी चुनाव क्षेत्र जसवां-परागपुर में हमारे समय में भी एक कॉलेज खुला था।

Chief Minister: My request is speak on facts, not on fiction.

Prof. Prem Kumar Dhumal: My request is please listen silently, think over that and reply properly. जिसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं कि तीन कॉलेज दिए इसी चुनाव क्षेत्र में हमने कॉलेज दिया था। वहां पर क्लासिज शुरू हो गई थी और बच्चियां पढ़ती थी। आपने उस कॉलेज को डीनोटिफाई किया और जब कोर्ट में चैलेंज हुआ तो आपने कहा कि मापदण्डों के अनुसार नहीं था, कॉलेज मापदण्डों से बनता है। क्या वह मापदण्ड आपके समय में प्राइमरी स्कूल से डिग्री कॉलेज हो गये? इनके समय में पिछले साल केवल 1700 टीचर्स लगे हैं और कितने रिटायर हुए क्या आपने उनकी संख्या देखी है? जब कैबिनेट मीटिंग होती है तो खबर आती है 'खुला नौकरियों का पिटारा'।

श्री वर्मा द्वारा जारी

06/03/2017/1600/टी0सी0वी0/ए0जी0/1
प्रो0 प्रेम कुमार धूमल - - जारी

इस समय प्रदेश में एक लाख पांच हज़ार से ज्यादा पोस्टें कर्मचारियों की खाली हैं और सैंक्शंड पोस्टे 2,84,000 हजार खाली हैं, तो पोस्टों का पिटरा कहां खुल रहा है? एजुकेशनिस्ट का ऑपिनियन है - shortage of teaching faculty. Many Government colleges have not a single teacher in various subjects to teach. Nothing certain who will submit their internal assessment - जहां प्रोफेसर ही नहीं है, वहां इंटरनल एसैस्मेंट कौन देगा - and evaluate their project report consequently producing incompetent students. Situation is equally worse in Government schools, to be the large number of schools having negligible enrolment. अध्यक्ष महोदय ये सरकार केवल मात्र घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है। अभी जैसा मैंने कहा कि 2016-17 में केवल मात्र 1,700 पद भरे गये और 2,500 पदों की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर चल रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपके घोषणा पत्र में था कि बहुत ज्यादा पोस्टें नहीं भरी गई और वे खाली रह गई थी। लेकिन अब क्या स्थिति है? क्या आप उनको भर रहे हैं? आपने दिल्ली वॉक्-इन-इंटरव्यू रखा। मेरी जानकारी है कि उसमें कोई भी डॉक्टर नहीं आया। कुछ डॉक्टर्ज आ रहे हैं लेकिन कुछ छोड़कर जा भी रहे हैं, बहुत-सारे अच्छे

डॉक्टर्ज हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में भी विकेंसिज़ बहुत ज्यादा हैं। नेर-चौक (मण्डी) कॉलेज में क्लासिज़ शुरू करने के बारे में यहां पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। नाहन, हमीरपुर और चम्बा में नये मैडिकल कॉलेजों के लिए 115 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई। क्या ये राशि प्रदेश सरकार ने जारी की है? इसलिए आपको मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। ये सारा पैसा केन्द्र सरकार ने भेजा है। आप मैंशन करिए कि कितना पैसा केन्द्र सरकार ने दिया और उसमें आपने (प्रदेश सरकार) कितना शेयर दिया, वह इसमें लिखिए। लेकिन आपने इस तरह से लिखा है, जैसे यह सब आपने ही कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने तो वही पढ़ना, जो आपने लिखकर दिया और सरकार ने बनाया। प्रदेश में भांग की खेती के उन्मूलन के ऊपर आपने पैरा न0 24 में उनसे कहलवाया कि हमने 2,145.75 हेक्टेयर भूमि से भांग के पौधों को नष्ट किया। युवाओं विशेषकर विद्यार्थियों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का दूरूपयोग रोकने के लिए राज्य में खुली सीगरेट और बीड़ी की ब्रिकी पर तुरन्त प्रतिबन्ध

06/03/2017/1600/टी0सी0वी0/ए0जी0/12

लगा है। लेकिन लागू कितना कर रहे हो? क्या लोग सरेआम सीगरेट नहीं पी रहे हैं, क्या सब जगह नशे की दवाईयां बिक नहीं रही है? अध्यक्ष महोदय, चिन्ता की बात है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो आंकड़ा दिया गया, वह 26,821.875 बिघा है। लगभग 27,000 बिघा में भांग उखाड़ी गई और हमारे चीफ सेक्रेटरी और डी0जी0पी0 ने प्रैस कांफ्रेस की

श्रीमती एन0एस0 - - द्वारा जारी।

06/03/2017/1605/ns/ag/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ------जारी।

और उसमें जो आंकड़ा दिया गया है वह 17,627 बीघा है। 17,627 और 26,821 में लगभग 10,000 बीघा का अन्तर है। हम किस आंकड़े को कोरैक्ट माने? जो चीफ सैक्रेटरी और

डी.जी.पी. ने प्रैस कॉन्फरैंस में कहा वह सही था या जो माननीय राज्यपाल महोदय ने इस मान्य सदन में कहा वह सही था। सबसे बड़ी चिन्ता की बात तो यह है कि देव भूमि को लोग ड्रग्ज़ भूमि के नाम से जानने लग पड़े हैं। लगातार समाचार पत्रों में "सिन्थैटिक ड्रग्ज़ थरैडर", कुल्लू 19 फरवरी के ट्रिब्यून और 14 फरवरी में माफिया "पंपिंग ड्रग्ज़ इन मणिकर्ण", मलाणा के बारे में छपा था। अध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी, 2017 हिन्दुस्तान टाईम्ज़, चण्डीगढ़ के एस.एस.पी. ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ऐफिडेविट फाईल किया। तब हाईकोर्ट ने पूछा था कि ड्रग्ज़ या नशे की दवाईयां कहां से आ रही हैं? उनके जो एस.एस.पी मि0 सिंगल ने ऐफिडेविट दे करके लिखा है that these contrabands - non-synthetics - are mostly manufactured at the highest locations of Himachal Pradesh, especially Manali, Kullu, Manikaran and Mandi. Thereafter these contrabands are being supplied by them in Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, U.P. and other parts of the country. Report says.

Chief Minister: It is wrong report.

Prof. Prem Kumar Dhumal: It is an affidavit filed by the Police Officer in the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana.

Chief Minister: I challenge this affidavit.

Prof. Prem Kumar Dhumal: Stand up and challenge.

Chief Minister: You are standing and I am sitting. When I will get up, I will reply.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अच्छी बात है आपने यह तो स्वीकार कर लिया कि कोई दूसरा बोल रहा हो तो बैठे रहना चाहिए।

मुख्य मंत्री : यह गलत बात है। (व्यवधान)

06/03/2017/1605/ns/ag/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः पर बीच में ऐसे कोमैंट भी नहीं करना चाहिए।

मुख्य मंत्री : आप इस सदन में एस.एस.पी. चण्डीगढ़ की स्टेटमैंट कोट कर रहे हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः 17 फरवरी को प्रैस में रिपोर्ट हो गई और कोर्ट में भी आ गया तो क्या सरकार आज तक सोई हुई थी? उस समय इसका खंडन क्यों नहीं किया गया कि हिमाचल प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है। मेरा दर्द भी यही है कि देव भूमि को ड्रग्ज़ भूमि पेंट कर रहे हैं। अगर गलत किया है तो drag them into the court. इसके अलावा ओर भी बहुत कुछ है। इन्दौरा क्षेत्र में नशाखोरों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला और गाड़ी तोड़ी।

यह घटना तो मुख्य मंत्री महोदय आपके ही प्रदेश में हुई है। यह खबर 'अमर उजाला' में 28 फरवरी को छपी थी। जो पुलिस वाले नशाखोरों को पकड़ने गये थे उनकी भी पिटाई कर दी गई। मुख्य मंत्री महोदय, अगर आप हर चीज़ को इस तरह से कहेंगे कि गलत है तो अपराधियों के हौंसले बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय मंत्री जी का 16 सितम्बर, 2011 का पत्र कोट कर रहा था। जिसमें कहा गया है कि I have got the matter examined, as you are aware the present import tariff is 50 per cent which is also a bond rate of duty agreed in WTO. The scope of further increase in tariff rates without further negotiations under WTO regime therefore seems unlikely at the moment.

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी।

06/03/2017/1610/RKS/AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः .....जारी

और वही मंत्री चुनाव घोषणा पत्र में इसको तीन गुना करने का वायदा करता है अर्थात् they were never serious about their Manifesto लोगों को गुमराह करने के लिए कहा गया और अब भी सीरियस नहीं है। मैंने सुना है कि आपके मंत्रियों की कोई कमेटी बनी हुई है, वह कमेटी चैक करती है कि कितने प्वाईंट इम्प्लीमैंट हुए। क्या इस कमेटी ने देखा कि आपके कुल प्वाईंट कितने थे और आपने कितने पूरे किए? क्या केवल फॉर्मेलिटी के लिए कमेटी बनी हुई है? क्या फॉर्मेलिटी के लिए बैठक होती है और फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया जाता है कि पूरे कर दिए गए हैं? माननीय राज्यपाल महोदय को कह दिया गया कि हमने सारे लागू कर दिए। "अनुबन्ध आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को 5 वर्ष बाद नियमित कर दिया जाएगा।" क्या पांच वर्ष बाद ये कर्मचारी नियमित हो गए और कितने नियमित हुए हैं? "सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विभिन्न श्रेणी के रिक्त पड़े पदों को भर दिया जाएगा।" "हजारों बेरोज़गार नौजवानों को नौकरी का लाभ मिलेगा।" ये सारी खोखली घोषणाएं, झूठे वायदे हैं, जो पूरे नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वर्दियां नहीं मिली हैं जबकि चार वर्षों में आठ वर्दियां मिलनी चाहिए थी। इससे स्कूल के बच्चे नाराज़ हैं। कॉलेज गॉईंग स्टूडैंट्स पर बिना तैयारी के "रुसा" लागू कर दिया गया। छात्र छठे समैस्टर के पेपर दे रहे हैं और फस्ट समैस्टर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। छात्रों को यह पता नहीं कि उनका पहला समैस्टर क्लीयर हुआ है या नहीं। "बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ते का वायदा"। "कर्मचारियों को 4-9-14 दिनांक 01.01.2006 से देने का वायदा।" जो हमारे समय में वर्ष 2009 से दिया था उसे भी वर्ष 2012 से कर दिया और वह भी पूरी तरह से इम्प्लीमैंट नहीं हुआ। कर्मचारी हितैषी सरकार ने चार वर्ष के बाद जे.सी.सी. की बैठक की और चार वर्ष बाद 2 परसैंट डी.ए. दिया। पिछले कल पैंशनर्ज़ का बहुत बड़ा डैपुटेशन मिला। एच.आर.टी.सी. के पैंशनर्ज़ कहते हैं कि हमें छः महीनों से कोई पैंशन नहीं मिली। पैंशनर्ज़ को पैंशन नहीं मिल रही है। कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति नहीं हो रही है। मज़दूर की दिहाड़ी का 200 रुपये का वायदा पूरा नहीं हुआ। होम गार्ड वाले सुप्रीम कोर्ट गए, उनका जो निर्णय हुआ था उसे आपने लागू नहीं किया

और उस निर्णय को लागू करवाने के लिए उन्हें दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। पुलिस वाले, जिनसे आप अपेक्षा करते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण में एक पैराग्राफ में अढाई लाइन आपने लिखी है "कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं।" कुल्लू जिला के बंजार में आई.एस.आई.एस. का आतंकवादी पकड़ा जाए तो क्या स्थिति नॉर्मल है? सुबाथू में पुलिस आर्मी कंटौनमैंट में आतंकवादियों के पोस्टर लगे। काला-अम्ब में बारुद पकड़ा गया। नाहन में हथियार पकड़े गए, तो क्या कानून व्यवस्था की स्थिति नॉर्मल मानी जाए? जब पुलिस नशे वालों को पकड़ने जाती है तो मार खाकर आती है और उन पुलिस वालों को भी आपने कॉंट्रैक्ट में कर दिया। 7 साल के बाद, 8 साल के बाद उनको पूरा ग्रेड मिलेगा। वे बेचारे बिना छुट्टी के 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। जो एक महीने का वेतन उनको एक्सट्रा मिलता था, अब तो नया वेतन आने वाला है और बाकि स्टेटों में तो आ चुका है। लेकिन हमारी स्टेट में अभी नहीं आया है। यह भी पुराना ग्रेड हो गया, इससे भी पुराने ग्रेड में 12 महीने की तनख्वाह प्रैजेंट ग्रेड में और जो एक महीने की एक्सट्रा है वह उससे पुराने ग्रेड में। आपकी एजैंसिज़ क्या काम करेगी? राज्यपाल महोदय ने पढ़ दिया आपने लिख दिया मेरी सरकार ने घरेलू बिजली खपत में कमी लाने के उद्देश्य से 30 जनवरी, 2017 तक 71,47,428

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

06.03.2017/1615/SLS-AS-1

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल ...जारी

एल.ई.डी. बल्ब वितरित कर 11,59,788 उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, हमने 15 अप्रैल, 2008 को घोषणा की थी और 4-4 सी.एफ.एल. बल्ब हर परिवार को और हर कंज्यूमर को मुफ्त दिए थे। आपने उसको भी

चार्जशीट का इसू बनाया और विजिलैंस से जांच करवाई कि बड़ी गड़बड़ी हुई। एक व्यक्ति ने इसको हाई कोर्ट में भी चैलैंज किया। जो यह पैटिशनर था उसकी घरवाली लाइन में लगकर बल्ब ले रही थी। हमने कोर्ट में फोटो दिखाया कि इसकी घरवाली 4 बल्ब मुफ्त ले रही है जबकि वह पैटिशन कर रहा है कि बड़ी हेराफेरी हो गई। आपने इसे माननीय राज्यपाल महोदय से कहलवाया है जबकि 14 फरबरी, 2017 का अमर उजाला लिख रहा है - 'सस्ते एल.ई.डी. में करोड़ों का घपला'। यह मामला हमारे माननीय सदस्यों ने भी बार-बार सदन में उठाया। तब आपने कहा कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब आपकी सी.आई.डी. ने ही केस दर्ज़ किया है और संबंधित कंपनियों के रिकॉर्ड तलब किए जा रहे हैं। जो बल्ब 50-60 रुपये में मिलना था, वह आपने 100-105 रुपये में बेचा। करोड़ों रुपया इसमें कंपनियां खा गई। यह किसकी सह पर हुआ? कौन इसके पीछे था? क्या केवल कंपनियां अपने दम पर सब-कुछ कर रही थीं या कोई और इसके पीछे खेल खेल रहा था? अन्य प्रदेशों ने अपनी तरफ से मदद कर इसे सस्ता करके दिया जबकि आपने इसको और महंगा कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंकों के बारे में पैरा संख्या-96 में केवल डेढ़ लाइन है। "राज्य सहकारी बैंकों ने सितम्बर, 2016 तक 359.46 करोड़ रुपये के फ़सल ऋण वितरित किए।" क्या सहकारिता में हमारी केवल इतनी ही मूवमैंट है। वहां सैंकड़ों लोगों को चोर दरवाजे से नौकरियां दी जा रही हैं। टैस्ट लेकर कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड जलाने की इज़ाज़त दे दी जाए; संभालना मुश्किल हो गया है। वहां ऋण देने में कमिशन की चर्चाएं हैं। हार्टिकल्चर वालों की एक कौपरेटिव सोसाइटी बनी है। उसके ऊपर जो स्टेट कौपरेटिव बैंक का ऋण था, वह सितम्बर 2015 तक

06.03.2017/1615/SLS-AS-2

97,47,957 रुपये हो गया। यह रिकवरी क्यों नहीं हो रही? हार्टिकल्चर के तो कर्मचारी ही उसके मैंबर हैं। मैडम स्टोक्स जी, यह आपके डिपार्टमैंट की बात है। जब हार्टिकल्चर में

कौपरेटिव सोसाइटी बनी है तो ऋण कर्मचारी की तनखाह से डिडक्ट करो और जमा करवाओ। इस तरह बैंक को घाटा क्यों हो? इसमें वह एक करोड़ रुपये के घाटे तक पहुंच गए है। जिस कर्मचारी नेता ने यह मामला उठाया, उसको आपने ससपैंड कर दिया। जो भ्रष्टाचार की बात उठाता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है।

सैलानियों का आपने पैरा-98 में ज़िक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, पहले कहा गया था कि इतनी एयर सर्विसिज शुरू होने वाली है, फ्लां एक्ट्रैस हमारी ब्रांड ऐम्बैसडर होने वाली है जबकि आजकल आपको कोई ध्यान नहीं आ रहा। आपने फिगर दी है कि पर्यटकों की संख्या 1,84,50,000 हो गई है और बड़ा क्लेम किया है कि इसमें 5.24 परसैंट वृद्धि हुई है। लेकिन क्या यह फैक्ट नहीं है कि यह वृद्धि नैगेटिव है। पिछले साल 8.98 परसैंट वृद्धि हुई थी। सैलानी आएगा कैसे? दो साल पहले कुल्लू-मनाली में बर्फ पड़ी थी और आप संभाल नहीं सके। इसका ज़िक्र सुरेश भारद्वाज जी ने किया भी कि बिजली की सप्लाई शिमला में भी बंद हो जाती है और हफ्ता-हफ्ता बिजली नहीं मिलती। वहां पर आपके अधिकारी प्रैस कॉंफ्रैंस करते हैं कि टूरिस्ट न आएं, हम संभाल नहीं पाएंगे। फिर कौन टूरिस्ट होगा जो उसके बावजूद वहां आना चाहेगा? शिमला राजधानी है। आपने कहा कि सारे प्रदेश में शुद्ध पेयजल देंगे। 99.98 परसैंट स्कूलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। शिमला राजधानी में तो उपलब्ध नहीं है।

जारी .. श्री गर्ग जी

06/03/2017/1620/RG/DC/1
प्रो. प्रेम कुमार धूमल----क्रमागत

यह 'बाटा' कम्पनी का जो शू रेट होता था जैसे 599.98 पैसे, तो इसी प्रकार के आंकड़े इसमें लिखे गए हैं और इस प्रकार से आंकड़े बनाए गए हैं जैसे वे शुद्ध लगें। शुद्ध पेयजल एवं शौचालयों के इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं। शिमला में तो सीवरेज का पानी लोगों

को पिलाते रहे। उस बच्चे युग की लाश जिस पानी के टैंक में सड़ती रही। वह कितनी बार साफ हो गया और कितनी बार इसके लिए पेमेंट हो गई? वही पानी पीने के लिए वी.आई.पी. क्षेत्र में सप्लाई होता रहा। अगर शिमला शहर में शुद्ध पेयजल नहीं दे सकते हैं, तो सारे प्रदेश में आप कहां से और कैसे देंगे?

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन भी इसी बात पर निर्भर करता है। जब यहां काम ठीक नहीं होगा, तो पर्यटक यहां कैसे आएगा? लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं सीखा। जब बर्फ पड़ी, तो दस लोग मर गए। यहां भी एक-दो पर्यटक मरे। वे अपनी गाड़ियों में ही ठण्ड से ठिठुरते और उनके ठहरने का प्रबन्ध नहीं हो पाया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पुलिस भर्ती का जिक्र किया था, यह उसकी नोटिफिकेशन निकाली है, " Applications on the prescribed forms are invited for recruitment to the post of constables in Himachal Pradesh Police Department in the pay scale of 5910 -20200+ 1900 (GP) initial. Initial start 7800/- and after 8 years of regular service pay band will be 10300/-". तो जो नॉर्मल 10,300/-रुपये है, पहले आठ साल तक उसको यह नहीं मिलेगा और उसके बाद यह मिलेगा।
अध्यक्ष महोदय, एक वायदा पेन्शनर्ज के साथ था कि पेन्शनभोगियों को पंजाब की तर्ज पर 65-70-75 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 5%, 10% एवं 15% का अतिरिक्त पेन्शन हिस्सा दिया जाएगा। यह अभी तक लागू नहीं हुआ। वर्ष 2006 से पूर्व के पेन्शनभोगियों एवं पारिवारिक पेन्शनभोगियों के लिए पंजाब सरकार के पत्र दिनांक वर्ष 2010 के अनुसार 50% एवं 30% का पेन्शन एवं पारिवारिक पेन्शन में संशोधन करेंगे। लेकिन ये कोई भी संशोधन नहीं हुए और इनको कोई वृद्धि नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कहा गया 'प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में पेयजल, मल निकासी, अधोसंरचना विकास एवं सौन्दर्यकरण जैसी बेहतर नागरिक सुविधाओं का

06/03/2017/1620/RG/DC/2

विस्तार किया जाएगा।' जब शिमला शहर का ही विकास नहीं हो सका, तो बाकी जगहों का विकास क्या करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, नागरिक उडयन में एक बड़ा ही मजेदार वायदा था। 'हवाई अड्डा, शिमला का विस्तार' और वर्क शॉप सुन्दर नगर में। एरोप्लेन्ज की जो रिपेयर की वर्कशाप होगी वह सुन्दरनगर में होगी। लेकिन वहां हवाई अड्डा ही नहीं है। तो यह कौन सी टैक्नॉलॉजी है? शिमला में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा और एयरक्राफ्ट की मेन्टीनेंस, मरम्मत और कार्यशाला सुन्दरनगर में स्थापित की जाएगी। इसी चुनाव घोषणा-पत्र में दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे।

एम.एस. द्वारा जारी

06/03/2017/1625/MS/DC/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी---------

अब मैं देवस्थान की बात करूंगा। राज्य में मंदिरों को दी जाने वाली वार्षिक अनुदान राशि में दो गुणा वृद्धि की जाएगी। राजकीय मंदिरों की मुरम्मत/जीर्णोद्धार के कार्यों के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। ये कौन-कौन से मंदिर हैं जिनको अनुदान दिया गया? एक बात लगातार मुख्य मंत्री महोदय आपने शुक्रवार को भी बोली और भारतीय जनता पार्टी पर आप बड़ा आरोप लगाते हैं कि हम क्षेत्रवाद फैलाते हैं। अध्यक्ष जी, आज मैं मल्होत्रा कमीशन की रिपोर्ट यहां लाया हूं। यह ज्यूडिशियल कमीशन सन् 1990 में बना था। मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन रेलेवेन्ट चीजें पढ़ना चाहूंगा। जस्टिस मल्होत्रा ने आब्जर्व किया "As discussed above, under two of the references above, 22 shopkeepers, whose native places were in Kangra, Una ,Hamirpur and Mandi Districts, were threatened and forced by the agitators to leave the place where they were having the business. Their shops were looted, causing damage of lakhs of rupees to them. It is also in the evidence that during the

agitation the slogans "आलू, सेब खाएंगे, कांगड़ियों को भगाएंगे" were raised" . क्या ये हमने उठाए? क्या ये नारे हमने लगाए?

मुख्य मंत्रीः ये कहां की बात कर रहे हैं? कौन से कमीशन की बात कर रहे हैं?

Prof. Prem Kumar Dhumal: This is Judicial Commissioner's Report, "Malhotra Commission's Enquiry Report".

मुख्य मंत्रीः कैंथला तो आपका घर का आदमी था। हर दूसरा कमीशन कैंथला कमीशन, कैंथला कमीशन होता था।। reject his reports.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः और यह सारा कुछ जिस क्षेत्र से आप प्रतिनिधि थे, वहां हुआ। सारे पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बल्कि पर्टिकुलरली जहां से आप मुख्य मंत्री रहते हुए पांच बार विधायक बने, उसी चुनाव क्षेत्र में ऐसे नारे लगे। अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में इतना क्षेत्रवाद फैलाया कि और तो और जो वहां शू-मेकर थे उनको भी वहां से भागना पड़ा।

06/03/2017/1625/MS/DC/2

मुख्य मंत्रीः यह बिल्कुल गलत बात है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः यह मैंने आपकी लाइब्रेरी से लिया है।

मुख्य मंत्रीः यह फैब्रिकेटिड स्पीच है। I reject this allegation. This is figment of imagination.

Prof. Prem Kumar Dhumal: The accuse will always reject the allegation.

मुख्य मंत्रीः इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई होगी , I don't know, but there was no such movement against anybody.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अब मुझे थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको क्लीयर हो जाएगा।

मुख्य मंत्रीः आप लोगों ने कितना जहर फैला रखा है।

Prof. Prem Kumar Dhumal: "This shows that mischievous elements in the agitation tried to create 'ill will' between the two sections of society but their attempt did not succeed". ये उनके नाम है और साथ में एड्रैस भी दिए गए हैं। इसमें इंट्रस्टिंग पार्ट यह है कि सब एप्पल ग्रोईंग एरियाज में एजिटेशन नहीं हुआ। There was no incident in Kullu and Mandi, मण्डी के सरकाघाट के लोग तो खुद वहां से निकाले गए। इस करके मुख्य मंत्री महोदय जब-जब यह क्षेत्रवाद की आग लगी है वह आपने लगाई है और उसके लिए आप दूसरों को दोष देते रहते हैं।

मुख्य मंत्रीः क्षेत्रवार की आग किसने लगाई? आप लोगों ने क्षेत्रवाद को बढ़ाया।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आपने बढ़ाया। आपका तो प्रैक्टिकल ज्यूडिशियल इन्क्वायरी में साबित हुआ है।

मुख्य मंत्रीः कौन सी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी? कोई आपके घर की इन्क्वायरी होगी। Why didn't they call me as a witness? I would have gone.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी श्री जे0एस0 द्वारा-----

06.03.2017/1630/जेके/एजी/1

Prof. Prem Kumar Dhumal: You must have said that I have nothing to do with it.

Chief Minister: Please don't talk about "श्रेत्रवाद". श्रेत्रवाद,जातिवाद, पुराना हिमाचल और नया हिमाचल की बीमारी फैलाने वाले आप हैं। Mr. Dhumal, it is you who is responsible for this.

Prof. Prem Kumar Dhumal: Justice J.C. Malhotra says in his report on 4th September, 1990. In July, 1990 in your constituency this happened.

Chief Minister: I reject this report.

Prof. Prem Kumar Dhumal: You are nobody to reject. आपका ज्युडिशरी में कोई विश्वास नहीं है इसका यह मतलब है।

मुख्य मंत्री: आप लोग ऐसे आदमी को कमिशन का चेयरमैन बनाते थे जो कि आपकी बोली बोलेगा। You have set up so many Commissions. हर ज्युडिशरी इन्क्वायरी के लिए कैंथला।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: यह कैंथला नहीं मल्होत्रा है जो कि आपका अपना है।

मुख्य मंत्री: कैंथला, मल्होत्रा, ये आपके फेवरेट टारगेट हैं हर कमिशन के लिए। ये आपकी विचारधारा के लोग हैं। आपके समय जो गलत लोग कमिशन में बैठे उन्होंने प्रदेश के अन्दर फूट डालने की कोशिश की। श्रेत्रवाद और जातिवाद को बढ़ाया गया। नया हिमाचल, पुराना हिमाचल की बात की गई। निचला हिमाचल, बीच का हिमाचल और ऊपर का हिमाचल इस तरीके की बात की गई। This is your ideology, nor ours. We have always opposed this ideology.

06.03.2017/1630/जेके/एजी/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: आप इस बात पर टेबल थपथपा रहे हो कि ऊना वाले यहां से मारकर निकाले गए, हमीरपुर वाले निकाले गए, कांगड़ा वाले निकाले गए, सरकाघाट वाले निकाले गए और केवल एक व्यक्ति जो उस समय अपने आपको वहां का नेता बोलता था, वह एम0एल0ए0 था। इस सदन में बैठकर जब रिपोर्ट पेश हुई तब तो आप यहां पर एम0एल0ए0 थे। आप चुप बैठे रहे। उस समय की सरकार ने वह रिपोर्ट प्रेजैंट की। वर्ष 1998 में बाबू राम मंडियाल जी ने जब यहां से पढ़कर सुनाई तब आपने कहा कि इसको छोड़ो। आज आप बोल रहे हैं, आपने भेदभाव किया।

Chief Minister: You are the biggest regionalist and casteist.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः इसलिए आप सबसे बड़े regionalist हो। आपके दांत खाने के और दिखाने के और है।

Chief Minister: I charge you in this House of promoting casteism and regionalism.

Prof. Prem Kumar Dhumal: You cannot interrupt like this.

मुख्य मंत्रीः आपका नारा रहा है पुराना हिमाचल, नया हिमाचल, नीचे के पहाड़, ऊपर के पहाड़। You have tried to divide the people on the basis of caste and region. This is your politics.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः यह सेब वाला हिमाचल और नॉन सेब वाला हिमाचल का नारा आपने लगाया है। हमने यह खत्म किया। हमने आपके बगीचे में सड़कें पहुंचाई। आप लोगों के बगीचों तक सड़कें पहुंचाने वाले हम है। आपने तो केवल लूटा है। केवल इस सेंटिमैंट को आपने एक्सप्लॉयट किया है।

मुख्य मंत्रीः हमारे लिए हिमाचल एक है और एक रहेगा।

06.03.2017/1630/जेके/एजी/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः कहने के लिए तो एक है लेकिन काम करने के लिए एक नहीं है।

मुख्य मंत्रीः एक है और एक ही रहेगा। आप जितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे उसको हम रिजिस्ट करेंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः हम टूटने नहीं देंगे और आप तोड़ रहे हैं। करते हैं आप ऐसा करके। सबको पता है कि आप हमारे क्षेत्र के साथ क्या व्यवहार करते हैं?

मुख्य मंत्रीः क्या करते हैं हम? मैं इतना प्यार हमीरपुर से करता हूं जितना कि मैं शिमला से करता हूं और अन्य क्षेत्रों से भी करता हूं। आपने क्या किया?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः हमने बहुत कुछ किया।

मुख्य मंत्रीः आपने किया होगा लेकिन एक जगह पर किया होगा और कहीं पर नहीं किया।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आपके चुनाव क्षेत्र में किया। आपके चुनाव क्षेत्र में जितनी सड़कें आपने बनाई उससे ज्यादा सड़कें मैंने वहां पर बना करके दी है। डोडरा-क्वार को हमने जोड़ा।

मुख्य मंत्रीः इस पर हम बाद में डीबेट करेंगे। आपने कितनी सड़कें बनाई और हमने कितनी बनाई। आपने हमेशा क्षेत्रवाद, जातिवाद को बढ़ाया है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, जातिवाद तो ये लोग फैलाते हैं। आपको रामस्वरूप की जीत पर वहां जा कर कहना पड़ा, जब ये माननीय सांसद वहां से जीते कि सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए इसलिए ये जीत गए। यह जातिवाद आपने फैलाया।

मुख्य मंत्रीः ब्राह्मण मेरे सबसे ज्यादा स्पोटर्ज़ हैं। हर जाति के लोग हमें स्पोर्ट करते हैं। यह ब्राह्मणवाद की अब नई बात है। राजपूतवाद, ब्राह्णवाद, हरिजनवाद इसके ड्रामेबाज आप हैं। आप हर चीज़ के ऊपर हिमाचल प्रदेश को बांटते हैं। आप क्षेत्रों को भी बांटते हैं। This is your ideology. आपकी और आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी

Continued by SS in hindi. . .

06.03.2017/1635/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

क्षेत्रवाद और जातिवाद है। अब अगले इलैक्शन में आना, हम आपको देखेंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी गुस्से हो रहे हैं। यह दो बार मंडी में कंसाचौंक में रैली करने गए।

मुख्य मंत्रीः मैं गुस्सा नहीं हो रहा। आप जब भी बोलते हैं तो ज़हर फैलाते हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः जो सड़कें बनाने की बात करते हैं, इनके चुनाव घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि साढ़े 7 हजार किलोमीटर सड़कें बनायेंगे। टोटल लगाकर जवाब देना क्योंकि आप पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री हो कि आज आपकी कितनी किलोमीटर सड़कें बनी हैं। सवा चार साल में एक हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं।

मुख्य मंत्रीः आप शेम कह रहे हैं। उसके लिए मैं कहता हूं, shame on you. इस सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः यह मैं आंकड़ों से बोल रहा हूं, आपकी रिपोर्ट के अनुसार। आपने कहा कि बिजली 5 हजार मैगावाट बनायेंगे लेकिन आपने अभी तक भी एक हजार मैगावाट नहीं बनाई है जबकि आपके सवा चार साल बीत गए। आपका चुनाव घोषणा पत्र कह रहा है कि 5 हजार मैगावाट बिजली बनायेंगे। आप हर फ्रंट पर असफल रहे हो। इसलिए गुस्सा मत किया करिये, आप सबसे सीनियर लीडर हो।

मुख्य मंत्रीः हम गुस्सा नहीं करते। आप हमारा क्रिटीसिज्म फैक्टस पर जितना मर्जी करो, । don't mind. परन्तु जब आप क्षेत्रवाद, जातिवाद, इलाकावाद के बारे में बात करते हो तो उससे मेरा खून उबल जाता है। कैसे पाखंडी लोग इस हाउस में बैठे हुए हैं।

06.03.2017/1635/SS-AG/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः जातिवाद तो आप कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि जब ऐसी बातें होती हैं तो उनका खून उबलता है।

"रगों में दौड़ने-फिरने के हम नहीं कायल,

आंख से ही नहीं टपका तो खून क्या होगा।"

यह भी किसी दिन हो जाए। इसलिए मैंने आपको कहा, मुझे आज बड़ी खुशी हुई थी जब आप मेरे बोलने पर उठे नहीं। मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात हो गई। बिक्रम जी ने कहा कि सारी आदतें नहीं बदलतीं, बैठे-बैठे ये बोलते रहेंगे। मैंने कहा कि चलो बोलेंगे। लेकिन आप उठ गए। गुस्से में क्या होता है? आदमी अपनी वीकनैस जाहिर करता है। आपने गुस्से में जाति-पाति का नारा मेरे ऊपर लगा दिया। जाति-पाति का कंसाचौंक में दोनों बार आप कह कर आए। हमने तो तब भी उसको इश्यु नहीं बनाया था। रामस्वरूप जी के बारे में आपने क्या कमैंट किया, किसी सांसद के बारे में आप क्या बोल देते हैं, यह सारी बड़ी विचित्र बातें हैं। लोकतंत्र में चर्चाएं होंगी। जब आप पक्ष में होंगे तो हम विपक्ष के तौर पर आलोचना करेंगे। जब हम पक्ष में होंगे तो आप आलोचना करेंगे। लेकिन उसको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए और लास्ट चांस तो आपका है। You are to reply as the Hon'ble Chief Minister of the State. इसलिए हर बात पर गुस्सा नहीं हुआ करते। गुस्से में आप खूबसूरत नहीं लगते।

मुख्य मंत्रीः बात यह है, एक मिनट। देखिये, जो आप कहना चाहते हैं वह आपको कहने का हक है। मगर जब आप अपने आपको यह कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं, हम क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करते, जातिवाद नहीं करते जबकि आप हिमाचल प्रदेश में उसकी जड़ हैं। इतना झूठ मत बोलिये।

06.03.2017/1635/SS-AG/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः देखिये माननीय मुख्य मंत्री जी, हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम जातिवाद का भेद नहीं करते। हम आपके चुनाव क्षेत्र रोहड़ू से एक ब्राह्मण को जीता कर लाए थे। खुशी राम बालनाहटा जी थे। वह ब्राह्मण करके नहीं वे हमारे कार्यकर्त्ता थे और वर्षों से आपके खिलाफ लड़ रहे थे। हो सकता है कि उस चुनाव में आपका आशीर्वाद भी

उनको मिला हो? लेकिन वे चुनाव जीत कर आए। क्योंकि मुझे आज टैम्परेचर है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप आज प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर हैं। आप जब जूनियर लोगों से बार-बार उलझेंगे तो न आप उस कुर्सी का महत्व बढ़ाते हैं और न अपना महत्व बढ़ाते हैं।

मुख्य मंत्रीः ठीक बात है। मैं इनसे नहीं भिड़ रहा बल्कि आपसे भिड़ रहा हूं

जारी श्रीमती के0एस0

06.03.2017/1640/केएस/एएस/1

मुख्य मंत्री जारी-----

क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि मैं तो देवता स्वरूप हूं और काम उल्टा करते हैं। आप अपनी तुलना देवों से करते हैं लेकिन कहते कुछ है करते उल्टा है। इस पर मुझे गुस्सा आता है। अगर आपको क्षेत्रवाद करना है, करो। जातिवाद करना है, तो करो लेकिन डंका बजाकर करो। एक तरफ तो क्षेत्रवाद और जातिवाद दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं तो राष्ट्रवादी हूं, मेरे लिए सारा हिमाचल एक है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मुख्य मंत्री जी, क्षेत्रवाद के तौर पर आपने जो मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ किया, आई.आर.बी. की बटालियन आप जंगलबैरी से उठाकर ले गए। हिमुडा का दफ्तर हमीरपुर से ले गए। वहां बस स्टैंड बन रहा था, उसका कार्य आपने बन्द करवा दिया। (व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः हमने आपका कौन सा दफ्तर बन्द किया?

Prof. Prem Kumar Dhumal: I am not yielding. Please, be seated.

मुख्य मंत्रीः हमने आपका कौन सा दफ्तर बन्द किया? I love Hamirpur, as much as I love any other part of India -- (व्यवधान)

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, यह क्या है?

मुख्य मंत्रीः आप फैक्ट्स बताएं कि कौन सी चीज़ हमने हमीरपुर से उठाई?

Prof. Prem Kumar Dhumal . Please, be seated. आप बैठिए। आप बात ही नहीं सुनते तभी आपको पता नहीं लगता कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र के जंगलबैरी से आप रातोंरात आई.आर.बी. की बटालियन उठा कर ले गए। हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड अथॉरिटी की तरफ से हमने टैंडर आबंटित कर दिया था। बस स्टैंड का काम शुरू हो गया था लेकिन जब से आप सत्ता में आए, चार साल से उसका काम बन्द पड़ा है। हिमाचल टैक्निकल युनिवर्सिटी हमीरपुर वाली का काम बन्द पड़ा है। हिमुडा व फोरैस्ट का ऑफिस

आप वहां से ले गए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्री जी सरेआम ही असत्य बोलें तो क्या कर सकते हैं? ये कहते हैं कि मैं अपने आप को देवता स्वरूप मानता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर देवताओं में आपकी आस्था है तो आप मेरी बात मान लो लेकिन देवता भी आप सिलैक्टिव पसन्द करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि सरकार ने जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय को लिख कर दिया, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। राज्यपाल महोदय को भी गुमराह किया और उनके माध्यम से प्रदेश को गुमराह करने का प्रयास किया है। इसीलिए राज्यपाल महोदय जी ने कहा था कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। असतो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्यातिर्गम्य अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन नहीं कर सकता। राज्यपाल महोदय के प्रति हमारी पार्टी का व हमारा बहुत सम्मान है, उनका हम आदर और सम्मान करते हैं लेकिन जो भाषण उनसे पढ़वाया गया, जिसके बारे में उन्होंने स्वयं ही कह दिया था असतो मो सद्गम्य, उस बात को मानते हुए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

06.03.2017/1640/केएस/एएस/3

Speaker: So, I just call upon the next Hon'ble Member, I request every Hon'ble Member to be with the limits of the time and they should not repeat the things which have been spoken. Because that will take more time and other will be defied of speaking. Now, I request Shri Kuldeep Kumar.

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, एक मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिया गया अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव जो कि माननीय सदस्य जगजीवन पाल जी ने रखा है और माननीय श्री संजय रतन जी ने अनुमोदन किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

6.3.2017/1645/av/as/1

श्री कुलदीप कुमार जारी

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

मैं इस सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस सरकार ने पिछले चार सालों में जो 'सबका कल्याण और समग्र विकास', एक सिद्धान्त अपनाया था यह सरकार उस सिद्धान्त पर चली और उसके कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक विकास हुआ है। मैं उसके लिए सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी का अपने राजनैतिक जीवन का जो 55 साल का तजुर्बा है उस तजुर्बे का

फायदा हिमाचल प्रदेश को मिला। मैंने भी कई वर्षों से यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और अपनी पार्टी की सरकारें देखी हैं। मगर हिमाचल प्रदेश में जो इस कार्यकाल में विकास हुआ है वह पिछले कार्यकालों से एक अभूतपूर्व विकास हुआ है। हमारी सरकार सबका कल्याण और समग्र विकास सिद्धान्त पर चली। मैं तीन मार्च को देख रहा था कि विपक्ष के सभी माननीय सदस्य ऐसी बात के ऊपर विरोध करने उठे, मुझे विपक्ष की ऐसी दयनीय स्थिति पहली बार देखने को मिली कि इनको विरोध करने का कोई मुद्दा नहीं मिला। इन्होंने उस दिन हमारे अध्यक्ष के खिलाफ वॉकआउट किया। हालांकि माननीय जितने वरिष्ठ सदस्य हैं वे जानते हैं कि अध्यक्ष का फैसला सर्वमान्य होता है (---व्यवधान---) मैं प्रस्ताव पर आ रहा हूं, धीरे-धीरे आप पर भी आऊंगा। लेकिन कोई मुद्दा नहीं था, विपक्ष मुद्दाविहीन थी और जानबूझकर एक मुद्दा बनाकर वॉकआउट किया जिससे विपक्ष की एक बड़ी दयनीय स्थिति सामने आई। (---व्यवधान---) कर्नल साहब चुप करके बैठे रहिए। आप शरीफ आदमी है और यदि मैं बोला तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। अभी माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने बड़ा लम्बा भाषण दिया। मैं पूरे भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था लेकिन उस भाषण में केवल विरोध के लिए विरोध था। तथ्यों पर कोई बात नजर नहीं आई। इनका सारा भाषण कांग्रेस पार्टी के घोषणा

6.3.2017/1645/av/as/2

पत्र पर केंद्रित रहा। इस घोषणा पत्र को उतना हमारे लोग नहीं पढ़ते होंगे जितना कि आपने पढ़ा है। उसमें आपने एक बात कही कि चुनावी घोषणा पत्र में किए सभी वायदे पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदे पूरे किए जा चुके हैं। अगर कुछ रह गये हैं तो अभी एक साल का समय बचा हुआ है। इस बचे हुए वर्ष में बाकी बचे वायदे भी पूरे कर लिए जायेंगे। आपने केवलमात्र विरोध के लिए विरोध की बात की है। माननीय विपक्ष के नेता ने एक बात कही कि माननीय मुख्य मंत्री जी जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं।

श्री वर्मा द्वारा जारी

06/03/2017/1650/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
श्री कुलदीप कुमार- - जारी

लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जुगाड़ की सरकार नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वह जुगाड़ से सरकार चला रहा हैं। ये इसलिए कहा क्योंकि केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है और इस सौतेले व्यवहार की वज़ह से आज हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को सफ़र होना पड़ रहा है। लेकिन केन्द्र सरकार का रवैया सौहार्दपूर्ण न होने के बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के विकास को निरन्तर आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रो0 प्रेम कुमार जी का जो होम क्षेत्र रहा, उनके सुपुत्र अनुराग ठाकुर जी की होम कांस्टिचुवैंसी रही और माननीय सती जी आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप यह बताईये कि हमारे ऊना जिला का 922 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट जिससे किसानों को फायदा हो रहा था और वे कई प्रकार की फसलें उगा रहे थे। उसमें राज्य सरकार ने अपना सारा हिस्सा दे दिया, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो ऊना जिला का जो 922 करोड़ का उनका हिस्सा था, वह क्यों रोका गया? आप जाकर केन्द्र में इसके बारे में बात करें। आप केन्द्र सरकार को सही तरीके से इस समस्या को रिप्रेजेंट नहीं कर पाये हैं। ऊना में स्वां चेनेलाईजेशन प्रोजैक्ट हैं। आप जाईये और केन्द्र सरकार ने जो उसका पैसा रोका हुआ है, उसको वहां से रिलीज़ करवाईये। केन्द्र में आपके प्रधान मंत्री और मंत्री हैं। आप जाकर रिप्रेजेंट करिए। अगर आप जनता के सही मायने में हितैषी हैं तो आप भी चलिए और हम भी चलते हैं और पूछते हैं कि आपने हिमाचल का पैसा क्यों रोक रखा है। अगर आप सही मायने में जनता के हितैषी होते तो 922 करोड़ रूपये का जो प्रोजैक्ट है, आज उसका पैसा रूका नहीं होता। केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश का अभुतपूर्व विकास करवाया है। आपको यह विकास पच नहीं रहा है। आपको हिमाचल का यह विकास सहन नहीं हो रहा है, और आज पोज़ीशन यह हो गई है कि आपके पास सरकार का विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इसलिए आप अध्यक्ष का विरोध करते हैं। सरकार का विरोध करने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। केन्द्र सरकार ने स्वां चेनेलाईजेशन की जो राशि रोकी है, उसके लिए ऊना के लोग आपसे पूछेगें। आपको आने वाले चुनावों में

06/03/2017/1650/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

जवाब देना पड़ेगा और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी (प्रो0 धूमल जी) ने एक बात अवश्य मानी है कि माननीय मुख्य मंत्री (वीरभद्र सिंह) जी ने प्रदेश में 46 नये डिग्री कॉलेज खोले हैं, चलो कम-से-कम इन्होंने इतनी बात तो मानी। लेकिन 46 डिग्री कॉलेज खोलने के बावजूद आप विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा 5-5 करोड़ रूपया इन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए दिया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज चौकी-मंजार में खोला गया। आज वहां पर क्लासें चली हुई हैं। आपका भी पुराना क्षेत्र रहा है, आप यह कॉलेज क्यों नहीं खोल पायें? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इस डिग्री कॉलेज खोलने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस इनटिरियर डिग्री कॉलेज में 80 प्रतिशत लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही है।

श्रीमती एन0एस0 - - - द्वारा जारी।

06/03/2017/1655/ns/dc/1

श्री कुलदीप कुमार------जारी।

जब में वहां पर एक दिन गया तो मुझे वहां के प्रिसिंपल ने बताया कि वहां से कम-से-कम पांच या छः लड़कियां जमा दो की कक्षा पास करके दो या तीन सालों से घर में बैठी हुई थी आज उन्होंने उस नये कॉलेज में दाखिला लिया। वहां के बच्चों को इस कालेज़ के खुलने से सहूलियत हुई है। (व्यवधान)

Deputy Speaker: Please be quite. Let him speak. आपने बहुत बोल लिया। इनको बोलने दो।

श्री कुलदीप कुमारः आज 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' को माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगे बढ़ाते हुए इन्टीरियर इलाके में 46 नये कॉलेज़ खोले हैं और इन कॉलेजों के भवनों के लिए पांच-पांच करोड़ रूपया दिया है। मेरे क्षेत्र के नये कॉलेज़ के लिए पांच करोड़ रूपये की राशि पहुंच गई है। इस कॉलेज के खुलने से लड़कियों को फायदा हुआ है। इसके अलावा कई ऐजुकेशनल इंस्टीच्यूट खोले गए हैं। 154 मिडल स्कूल, 109 राजकीय उच्च पाठशालाओं को खोला गया है। नये कॉलेज के भवनों के निर्माण के लिए 40 करोड़ रूपये की धनराशि दे दी गई है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 1 लाख 41 हजार 724 पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है। जहां तक हमारे माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने शिक्षकों की बात की है तो वर्ष 2016-17 में 1770 पद शिक्षकों के भरे जा चुके हैं और 2500 अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया अन्तिम चरण पर है। इसके अलावा 959 पी0जी0टी0, 207 कॉलेज सहायक प्रवक्ता, 1150 टी0जी0टी0, 342 जे0बी0टी0, 21 सी0 एंड वी0 और 117 अनुबन्ध क्लर्कों के पद भरे गए हैं और रेग्युलराईज़ किए गए हैं। इसके साथ-साथ टैक्नीकल ऐजुकेशन में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। दो इंजीनियरिंग कालेज, एक फार्मेसी, पांच पॉलीटैक्निक और 10 मॉडर्न आई0टी0आई0 खोले गए। टैक्नीकल ऐजुकेशन में भी बहुत विकास हुआ है। नाहन, हमीरपुर और चंबा में नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 115 करोड़ रूपये की

06/03/2017/1655/ns/dc/2

धनराशि जारी की गई है। अगर आप विपक्ष वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए बोल रहे हैं कि हमने लिए हैं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र स्वां का भी मेडिकल कॉलेज आप ले कर आईए। उसको क्यों आपने रोक कर रखा हुआ है? इसके अलावा 732 विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित किए गए हैं। जब बात आयुर्वेदिक क्षेत्र की आती है तो उसमें 38 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं और 10 बिस्तरों को एक आयुर्वेद अस्पताल भी

खोला गया है और 115 विभिन्न श्रेणियों के नए पदों को क्रिएट किया गया है। 40 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पद भरे गए हैं।

जहां तक कृषि की बात है किसानों की फसलों का जो नुकसान बन्दरों और अवारा पशुओं की वजह से होता था तो उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना चलाई। उससे काफी लोगों को फायदा हुआ और जिसमें 60 प्रतिशत सबसिडी देने का प्रावधान किया गया है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी।

06/03/2017/1700/RKS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का आज ही प्रश्न लगा था। उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक भी किसान को फायदा नहीं हुआ है, अभी वह स्कीम लागू ही नहीं हुई है। लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इससे बहुत सारे किसानों को लाभ हो गया। इस तरह का गुमराह आप सदन को मत करिए।

श्री कुलदीप कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, स्कीम चालू है और यह पिछले साल चालू की गई है। आने वाले दिनों में किसानों को इसका फायदा होगा और कई लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। किसान व कृषि कामगार के लिए 'किसान कल्याण व खेतीहर मजदूर जीवन संरक्षण योजना' चालू की गई है। आप अपने आप को बड़े गऊ भक्त बताते हैं। जहां भी जाते हैं गऊ माता की बातें करते हैं। आपके समय में गऊ माता सड़कों पर घुम रही थी, कई ऐक्सिडैंट में मर रही थी परन्तु आपने गऊ के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 'गऊ वंश संरक्षण व गऊ वंश कल्याण संबर्द्धन बोर्ड बनाया'। जो गऊ माताएं बाहर आवारा घुमती रहती हैं उनके लिए गऊवंश संबर्द्धन बोर्ड बनाया गया है। कई गौशालाएं बनाई गई। हर पंचायत में गौशालाएं बनाने का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त जो पी.डब्ल्यू.डी. की बात है, पी.डब्ल्यू.डी. में काफी पुलों, सड़कों का निर्माण हुआ है। हर पंचायत को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष 40 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। 245 किलोमीटर रोड़ बनाई गई, हवाई पुलों का निर्माण किया गया। नाबार्ड के अंतर्गत जितनी भी एम.एल.एज. प्रायोरटीज़ स्कीम्ज हैं, 1166 स्कीम्ज़ में जिसकी धनराशि 2,894 करोड़ रुपये बनती है की डी.पी.आर. नाबार्ड को भेजी गई है। इसके अलावा जो 3138 पंचायतें हैं उनके पंचायत हैड क्वार्टर्ज़ को सड़कों से जोड़ा गया है। जहां तक आई.पी.एच. की बात है वर्ष 2016-17 में 330 करोड़ रुपये पेयजल योजनाओं के लिए रखे गए और इसमें डेढ़ हजार के करीब हैंडपम्प लगाए गए। मेरे चुनाव क्षेत्र में ही जहां पर पीने के पानी की

06/03/2017/1700/RKS/AG/1

समस्या थी वहां पर लगभग तीन-चार सौ हैंडपम्प लगाए गए। 'प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना' के अंतर्गत 3644 पात्र लोगों को मकान दिए गए। 'मुख्य मंत्री आवास योजना' के अंतर्गत 1923 आवास पात्र लोगों को दिए गए। 'राजीव गांधी आवास योजना' के अंतर्गत 846 पात्र लोगों को मकान दिए गए। जब सामाजिक सुरक्षा पैंशन की बात आती है तो बुजुर्ग लोग जिनका कोई सहारा नहीं था, जिनको खर्चा चलाने में मुश्किल आती थी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि 80 साल के ऊपर जितने बुजुर्ग थे

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

06.03.2017/1705/SLS-AG-1

श्री कुलदीप कुमार ...जारीउनको इनकम सर्टिफिकेट देने से बिल्कुल छूट दे दी। आज यह बुढ़ापा पैंशन हजारों बुजुर्गों का सहारा बनी है क्योंकि उनको 1200 रुपया पैंशन मिल रही है। आपको इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि यह एक बहुत अच्छी स्कीम दी गई है।

आप तो जो एम.एल.एज. के लिए राशि दी गई है उसके लिए भी धन्यवाद नहीं करते। आप थैंकलैस लोग हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत जो राशि पहले 75 लाख रुपये होती थी उसे एक करोड़ कर दिया गया है। ...(व्यवधान)...वह भी मिल सकता है, लेकिन आप थैंकलैस लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, डिसक्रिशनरी राशि को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है जिसके लिए आपको माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन आप इसके लिए भी धन्यवाद नहीं कर सकते। आप किसी अच्छे काम के लिए भी आभार प्रकट नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)...उपाध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में यह टोकाटोकी ठीक नहीं है। अगर मैंने कोई बात कह दी तो फिर इनको तकलीफ़ होगी।

उपाध्यक्ष : आप भी कृपया कन्कलूड कीजिए।

श्री कुलदीप कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले भारतीय झूठी पार्टी होता था और अब इसका नाम भारतीय जुमला पार्टी हिंदुस्तान में चल पड़ा है। ...(व्यवधान)...कांग्रेस पार्टी काम करती है।...(व्यवधान)...रिजल्ट आने पर 11 तारीख को आपका सफाया हो जाएगा, आप देखते रहना। ...(व्यवधान)...कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा है कि काम किया, काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। लोकसभा के चुनाव में आपने झूठे वायदे करके लोगों को गुमराह किया। बाद में एक बात कह दी कि यह सारे तो जुमले थे। अब आपसे जनता इन जुमलों के बारे में पूछेगी। आपने जो 15 लाख रुपये देने का वायदा किया था वह कहां गया? वह आपने जुमला बता दिया, इसलिए आप पर कौन विश्वास करेगा। 11 तारीख को रिजल्ट आने पर आप सबको पता लग जाएगा और सबको जवाब मिलेगा। यहां पर भी आपने

जुमलों की बात शुरू कर दी है। जब आपका कोई वश नहीं चलता। ...(व्यवधान)...भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही पार्टी है।

पिछले 4 वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास किया है जिसके कारण आपके पास बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। अब हैल्पलैस होकर आप 1990 की बात कर रहे हैं और गढ़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जब आपका कोई वश नहीं चलाता तो आप क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात करते हैं। आप हताश हो गए हैं। हताश होने पर आपका आखिरी हथियार यह होता है कि क्षेत्रवाद और जातिवाद फैलाओ। अब लोग क्षेत्रवाद को भी समझ गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने धर्मशाला में दूसरी राजधानी देकर क्षेत्रवाद समाप्त किया है जिससे ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चम्बा सहित 5 जिलों की जनता को लाभ हुआ है और ऐसा करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल को एक सूत्र में पिरोया है। आज इनके प्रति आस्था बढ़ी है और सारे हिमाचल की जनता चाह रही है कि आने वाले मुख्य मंत्री भी राजा वीरभद्र सिंह ही हों। पिछले 4 सालों में यहां बहुत विकास हुआ है और बचे एक साल में भी बाकी वायदे पूरे किए जाएंगे। आपकी हताशा दिखाती है कि इस विकास को देखकर हिमाचल की जनता दोबारा कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। हम डंके की चोट पर दोबारा सरकार बनाएंगे।

Deputy Speaker: Please wind-up now.

श्री कुलदीप कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

जय हिंद।

जारी .. श्री गर्ग जी

06/03/2017/1710/RG/AS/1

उपाध्यक्ष : अब डॉ. राजीव बिन्दल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ. राजीव बिन्दल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार द्वारा लिखा हुआ जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत किया, उस पर चल रही धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु मैं खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय से जो कुछ यहां बुलवाया गया, वह वास्तव में चिन्तनीय है और इसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए। वैसे माननीय प्रति पक्ष के नेता पूर्व मुख्य मंत्री ने बहुत विस्तार से थोड़े-थोड़े प्वाइंट्स लेकर यहां अपनी बात कही है, मैं केवल कुछ बिन्दु ओं को छूकर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान यहां आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव घोषणा-पत्र में वायदों की बात की गई। क्या वायदे पूरे किए? सबसे बड़ा वायदा उसमें किया गया था कि हम जंगली जानवरों से सूअरों और बन्दरों से प्रदेश में किसान की रक्षा करेंगे। हालत क्या है? हमने वर्ष 2016 में एक प्रश्न संख्या 2669 यहां पर लगाया। उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जिन स्थानों का जिक्र किया है कि हमने यहां से बन्दरों को उठाकर उनकी नसबन्दी की है, मैं सीधा-सीधा इस सदन में आरोप लगा रहा हूं कि उन स्थानों पर कभी बन्दर इकट्ठे करने के लिए कोई व्यक्ति गया ही नहीं। इसमें गांव का नाम लिखा है 'रामा', उत्तरवाला, टीब, गाडा, बंकला, जाबल का बाग, बासवाला, आमवाला, पौढ़ीवाला, सुकेती, ठसका, टोडरपुर इत्यादि। मैंने इन गांवों का दौरा किया, लोगों से पता किया, तो किसी गांव के अन्दर एक बार भी पिंजरा नहीं लगा और एक भी बंदर यहां से नहीं पकड़ा गया। मैं यहां आरोप लगा रहा हूं कि यह जो बन्दर पकड़ने के पैसे हैं, ये किसकी जेब में गए और आपने कहा कि हमने किसानों को राहत दिलाई।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्होंने बागवानों की बात की, तो इटली से लाए गए पौधों की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। उपाध्यक्ष जी, आज हालत क्या है? इन पौधों में वायरस है। ऐसे पौधे मंगाकर आने वाले बीस और पचास साल तक बागवानों को उजाड़ने का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, किसानों और बागवानों से तो धोखा किया ही और घोषणा-पत्र में बेरोजगारों की भी बात की। मैं बेरोजगारी भत्ते पर बाद में आऊंगा। लेकिन इन्होंने बेरोजगारों की हालत क्या कर दी? जो भर्ती के नाम पर ठगी की गई, मैं यह आर.टी.आई. के माध्यम से मांगी गई सूचनाएं यहां दिखा रहा हूं और इनको यहां सदन में ले भी करूंगा।

06/03/2017/1710/RG/AS/2

आर.टी.आई. की सूचना से एस.एम.सी. के माध्यम से की गई भर्ती के बारे में मालूम हुआ। मैं भर्ती के आंकड़े यहां सदन में रख रहा हूं। सिंगल व्यक्ति-इन्टरव्यू, सिंगल व्यक्ति-इन्टरव्यू-सलैक्शन-सिंगल। अब मैं सिंगल से आगे चलता हूं। ये मेरे पास 75 नाम हैं। इसके बाद 26.69 जिसके नंबर थे उसको आपने इन्टरव्यू में 9 नंबर दिए और जिसके नंबर 30 थे, उसको दो नंबर दिए। 26 वाला सलैक्ट किया और 30 नंबर वाला फेल किया। मैं यहां आंकड़े दे रहा हूं। यह आर.टी.आई. के माध्यम से मांगी गई सूचना है। एस.एम.सी. के माध्यम से हुई भर्ती में जो बेरोजगारों के पेट पर लात मारी है, यह वही है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आंकड़े दे रहा हूं जिसको चेलेन्ज करना होगा, मैं इसको यहां ले कर रहा हूं। 15 नंबर वाले को इन्टरव्यू में 9 नंबर दिए, 22 नंबर वाले को 2 नंबर दिए और इस प्रकार 15 नंबर वाला पास और 22 नंबर वाला फेल। मैं यह एक भर्ती की बात नहीं कर रहा, अलग-अलग एस.एम.सी. के माध्यम से हुई भर्तियों की बात कर रहा हूं।

एम.एस. द्वारा जारी

06/03/2017/1715/MS/AS/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी---------

मुख्य मंत्रीः मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस भर्ती की बात कर रहे हैं?

डॉ0 राजीव बिन्दलः एस0एम0सी0 भर्ती की बात कर रहा हूं और एस0एम0सी0 भर्ती एस0डी0एम0 की चैयरमैनशिप में होती है।

मुख्य मंत्रीः यह कहां की बात है?

डॉ0 राजीव बिन्दलः यह सिरमौर जिला की बात है। मैं सिरमौर जिला के एस0एम0सी0 भर्ती के ये सारे कागज यहां ले कर रहा हूं।

श्री जगजीवन पालः आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः इस बात में खुशी होनी चाहिए? माननीय उपाध्यक्ष जी, 17 नम्बर वाले को साढ़े नौ नम्बर, 24 नम्बर वाले को 1 नम्बर; 17 नम्बर वाला पास और 24 नम्बर वाला फेल। अगला सुनिए। 28 नम्बर वाले को 3 नम्बर और 25 नम्बर वाले को 9 नम्बर; इसमें भी 25 नम्बर वाला पास। 29 नम्बर वाले को 9 नम्बर और 34 नम्बर वाले को एक नम्बर दिया। 22 नम्बर वाले को 2 नम्बर और 14 नम्बर वाले को 9 नम्बर;14 नम्बर वाला पास बाकी फेल। ये जो आपने लिखा कि हमने रोजगार दिया ये रोजगार किसको मिला? इसका हिसाब-किताब आपसे जनता पूछेगी। मैं और आगे चलता हूं। उपाध्यक्ष जी, हालत यहां पर नहीं रूकी बल्कि और गम्भीर होती गई जब उच्च न्यायालय का फैसला आता है और उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, वह मैं यहां ले करता हूं। उच्च न्यायालय का ऑर्डर हुआ कि यह भर्ती कैंसल की जाती है और दूसरे को सलैक्ट किया जाता है। यह सन्तोष वर्सिज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस है जोकि 20 अक्तूबर, 2016 का है। इसमें सरकार को फटकार लगी जिसके अंदर जिसको सलैक्ट नहीं करना था उसको इंटरव्यु में नम्बर दिए 0.8 और जिसको सलैक्ट किया उसको 9.8 नम्बर दिए। उच्च न्यायालय ने इसको निरस्त किया।

06/03/2017/1715/MS/AS/2

इसी तरह से उपाध्यक्ष जी, "एल0टी0 भर्ती में भाई-भतीजावाद"। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह हमारा मीडिया कह रहा है। (अखबार की कटिंग्स दिखाते हुए)। इसी तरह से एच0आर0टी0सी0 भर्ती; मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर में आप घण्टी बजा देंगे। मेरे पास पूरी डिटेल है। "एच0आर0टी0सी0 भर्ती" और भर्ती कहां की होगी, कांगड़ा की, सिरमौर वालों की नहीं होगी। फिर इसके बाद हालत यहां नहीं रूकी बल्कि और आगे चलती है।

मैं केवल एक विषय के बाद आगे बढ़ता हूं। मैं एच0ए0एस0 के टॉपर की बात करूंगा। उपाध्यक्ष जी, जिसने एच0ए0एस0 की परीक्षा में हिमाचल प्रदेश में टॉप किया, वह

फेल और जिसके सबसे कम नम्बर थे वह पास। मैंने कॉलिंग अटैंशन का नोटिस दिया था परन्तु लगा नहीं। मैं ये कागज भी यहां पर ले कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष जी, बेरोजगारी भत्ते के ऊपर बड़ी-भारी चर्चाएं हुईं। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन एक बात जरूर है। ऐसी सरकार जिस सरकार के अंदर एक मंत्री बोलता है कि बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए और मुख्य मंत्री बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता देना सरकार के वश में नहीं है। कहते हैं कि बेतुजुर्बेकार नेताओं ने यह घोषणा पत्र बनाया है। ये कागज भी मैं यहां पर ले कर रहा हूं। बेतुजुर्बेकार नेताओं ने बनाया घोषणा पत्र और आपने उस घोषणा पत्र को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से पढ़वा दिया? फिर उसके बाद अभी यहां वह घोषणा पत्र माननीय पूर्व मुख्य मंत्री ने पढ़ा और यहां पर मुख्य मंत्री का बयान है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि "कौशल विकास भत्ता" देने का वायदा किया था। इन्होंने यहां तक कहा कि बेरोजगारी भत्ता वृद्धावस्था पैंशन नहीं है । यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह मुख्य मंत्री जी का बयान हैं। जी0एस0 बाली जी कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता और हमारा घोषणा पत्र अक्षरशः लागू होगा।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

06.03.2017/1720/जेके/डीसी/1

डा0 राजीव बिन्दलः----**जारी**---------

माननीय उपाध्यक्ष जी फिर उसके बाद बाली जी और मुख्य मंत्री जी आमने-सामने। ये दोनों क्या बोलते हैं। बेरोजगारी भत्ते पर सरकार और संगठन आमने-सामने। मैं इसको छोड़ देता हूं यह बहुत लम्बी कहानी है। माननीय उपाध्यक्ष जी कौल सिंह जी हमसे राय जानना चाहते हैं। आपने कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा सकता है। जबकि आप उसके मेम्बर थे जिसके अन्दर यह घोषणा पत्र बना और आप उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे जब यह घोषणा पत्र बना। एक बात मैं कौल सिंह जी बता देता दूं कि आपकी नीयत भी समझ आ रही है। चुनाव आने को चार महीने है। अब दो महीने का कुछ लोगों को

बेरोजगारी भत्ता दे करके नाखून कटा करके शहीद होने की तैयारी कर रहे हैं। यह सब दिखाई दे रहा है और सारा हिमाचल जानता है। पांच साल का बेराजगारी भत्ता देने की बात कही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने यह बात कही कि भर्तियों में बेरोजगारों के साथ ठगी हुई। वन विभाग में चौकीदारों की भर्ती, 14 पोस्टें सिरमौर में निकली और 14 पोस्टों के लिए बड़े-बड़े कागजात मंगवाए गए। 2200 बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हुए और इंटरव्यू के बाद लिस्ट आई वह लिस्ट माननीय मंत्री जी के कार्यालय में आई। लोग देखते रहे गए। खाना बनाने वाले, दफ्तरी, सब्जी वाले भर्ती, पटवारियों के हेल्पर और सारी की सारी बैकडोर एन्ट्री। बैंक में भर्तियों के अन्दर जो घोटाला हुआ, हमने पूरी चार्जशीट के अन्दर डीटेल से लगाया है। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने उसको देखा। जब एक एजैंसी पूरे भारत में बैंक के एग्जाम लेने के लिए बनी हुई है हिमाचल प्रदेश का शिक्षा बोर्ड जिससे स्कूल के एग्जाम नहीं लिए जाते है उसके माध्यम से भर्तियां करके इस प्रकार की हालत पैदा की है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, गुणात्मक शिक्षा की बात की गई है। अगर ये बोलते क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एजुकेशन तब भी समझ में आता। यहां पर पैरा-4 में लिखा है कि गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाई गई। शिक्षण संस्थानों को बढ़ाने से तो गुणात्मक विस्तार नहीं होता है। जिला सिरमौर

06.03.2017/1720/जेके/डीसी/2

के बारे में मैं प्रश्न संख्या और उसका उत्तर यहीं से कैल्कुलेट करके दे रहा हूं। 2,340 पद शिक्षा विभाग में अकेले जिला सिरमौर में खाली है और ये बोलते हैं हम गुणात्मक शिक्षा दे रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3408 है और 12वें महीने का प्रश्न है। इसका सम टोटल करके मैंने बताया कि 2,340 पद अकेले जिला सिरमौर में खाली है और ये गुणात्मक शिक्षा की बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर और नहीं ले पा रहे ए,बी ग्रेड, ई और डी ग्रेड के ऊपर सरकारी स्कूल के बच्चे टिके हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एक सर्वेक्षण हुआ। नेशनल एजैंसी ने हिमाचल का सर्वेक्षण किया।

हिमाचल की अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा। इसके बाद एक बहुत अच्छी खबर- सिरमौर के गांवों में न सड़क न स्कूल, घर-बार छोड़ कर चले गए लोग। आप बोल रहे हैं कि हमने गुणात्मक शिक्षा दी है। आपने शिक्षा की गुणात्मकता की बात कह करके और माननीय महामहिम् के माध्यम से कहलवा करके बहुत बड़ा झूठ बोलने का प्रयास किया। मैं अखबार की खबरों से हट करके एक बहुत बड़ा सम्पादकीय हमारी शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर दिनांक 8.8.2016 को छपा और इसके अन्दर लिखा है राष्ट्रीय स्तर पर एक्सिलैंस के आधार पर परखे गए कॉलेजों की सूची में इस बार भी हिमाचली संस्थानों का शामिल न होना प्रदेश की काबलियत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

06.03.2017/1725/SS-DC/1

डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागतः

ये हिमाचल प्रदेश के नामी अखबार के सम्पादक ने आपको एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया और आप इसके विपरीत बोलते हैं कि हम गुणात्मक शिक्षा ला रहे हैं। आपने रूसा लगाया। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर रूसा के विरोध में लगातार आंदोलन चला हुआ है। मैं नहीं बोल रहा लेकिन अखबार लिख रहे हैं - "एक कमरे में चल रहे सूबे के सैंकड़ों स्कूल" और जो बिना कमरे के चल रहे हैं उसकी भी बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब शिक्षा में ही एक और बड़ी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल महोदय से यहां पढ़वाई। बहुत कष्टदायक है। इसमें लिखा है 99.98 परसैंट स्कूलों में पेयजल है। 99.79 परसैंट स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय हैं। इसमें लिखा है कि 96 परसैंट स्कूलों में बिजली है और 98 परसैंट में पुस्तकालय हैं। अरे, स्कूलों में कमरे नहीं हैं, बिल्डिंग नहीं है, यह 98 और 99 परसैंट बिजली कहां से आ गई और कहां से आ गए शौचालय? इतना बड़ा झूठ इसके अंदर लिखकर दिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन 13 और 14 बिन्दु पर किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं और मैं इनके सामने एक कॉंटैक्स्ट रख रहा हूं। आपने लिखा कि आई0जी0एम0सी0 की इमरजैंसी सेवाएं सुधारने के लिए अलग से विंग बनाया। आापने 29.10.2015 को नोटिफिकेशन की। "The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the creation of Emergency Medical Department in Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr, Rajendra Prasad Medical College, Tanda", और उसके माध्यम से हम ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी सुविधाएं देंगे और आपने इसमें पढ़वा दिया कि हमने ये फैसिलिटीज़ दे दी। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज तक इस इमरजैंसी मेडिकल डिपार्टमैंट के अंदर एक भी पोस्ट का सृजन नहीं हुआ और आपने यहां पर लिखवा दिया। --(व्यवधान)-- सर, मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक भी डॉक्टर और एक भी पोस्ट इसके लिए क्रियेट नहीं की गई। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक भी पोस्ट

06.03.2017/1725/SS-DC/2

क्रियेट न करके यह ऐसा इमरजैंसी डिपार्टमैंट बनाया जिसमें न कुछ आगे है और न पीछे है। आप बनाते या न बनाते परन्तु महामहिम से क्यों बुलवा रहे

हो? आपने कहा कि 56 औषधियां मिल रही हैं। मेरा कहना है कि 56 औषधियों की व्यवस्था का नोटिफिकेशन है। कुछ अस्पतालों के अंदर पहुंची भी हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं चैक करें कि प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज़ के अंदर ये औषधियां उपलब्ध हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो आप उसकी जांच करवाएं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी-अभी यहां बड़ी जोर से बोला गया कि केन्द्र सरकार की सहायता नहीं मिल रही। केवल हैल्थ की बात कर रहा हूं। हैल्थ डिपार्टमैंट में तीन मेडिकल कॉलेज दिये गए। आपने कहा 105, 115 करोड़, 190, 190, 190 करोड़ की सैंक्शन सैंटर्ल गवर्नमैंट की हुई। सी0डी0एस0सी0ओ0 (National Centre for Disease Control) 10 करोड़ रुपया, मैंटल हैल्थ 32 करोड़, ड्रग्ज़ रेगुलेटरी अथोरिटी 15 करोड़, अमृत शॉप्स 15,

डायलेसिज़ के लिए कहा कि सब जिलों में मिलेगा। ट्रॉमा सैंटर्ज़ को सुदृढ़ करने के लिए टांडा, रामपुर, हमीरपुर, मंडी, चम्बा, शिमला ट्रॉमा सैंटर के लिए पैसे, कैंसर अस्पताल शिमला के लिए 45 करोड़, कैंसर अस्पताल मंडी के लिए 45 करोड़, बर्न सैंटर के लिए 7 करोड़, नेशनल हैल्थ मिशन के 310 करोड़ और चिन्ता की बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारी राशियां ऐसी हैं

जारी श्रीमती के0एस0

06.03.2017/1730/केएस/एजी/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----

जिनका इस्तेमाल प्रदेश की सरकार नहीं कर रही और सुपर स्पैशियलिटी विंग शिमला की जो बात कही है, उसकी लैंड की फाइनेलाइजेशन के बारे में तीन दिन पहले मुझे मालूम हुआ जबकि पिछले साल की पैसे की सेंक्शन हमारे पास दी है और माननीय मंत्री जी की फोटो के साथ दिल्ली से खबर छपी है कि नेशनल हैल्थ मिशन का 310 करोड़।

उपाध्यक्ष महोदय, कुलदीप जी क्या कह गए कि केन्द्र सरकार नहीं दे रही है? कितने साल तक आप लोग भी बोलते रहे कि हमको विशेष दर्जे का सहयोग मिलना चाहिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंदर 90% और 10% की सहायता दे कर हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया है।

उपाध्यक्ष जी, 14वें वित्तायोग में, 13वें वित्तायोग में आपकी कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश को 50 %की बढ़ौत्तरी मिली। 14वें वित्तायोग में केन्द्र में मोदी जी की, बी0जे0पी0 की सरकार थी। हिमाचल प्रदेश को 252% की और हर पंचायत को 80-80 लाख रुपये आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश को टैक्स रेवन्यू शेयर 32% मिलता था और अब मोदी जी की सरकार है तो टैक्स रेवन्यू शेयर 42% मिलता है। अरे, इतना पैसा मिल रहा है और मेरा तो कहना है कि आप उनकी सहायता राशियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सिंचाई योजना की बात करें, आपने इस सम्बन्ध में प्रश्न का जो उत्तर दिया, आपने कहा

कि 1857 योजनाएं आपने मिनी माइक्रो भेजी और 187 योजनाओं की डी0पी0आर0 भेजी और डी0पी0आर0 2016 में भेजी। 2015 का खाता शून्य, 2016 का खाता शून्य। पैसा आएगा 2018 में तो हिमाचल का नुकसान किसने किया? आप लोगों ने किया।

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार का करिश्मा देखिए। रामपुर भरतपुर में प्राईमरी हैल्थ सैंटर बना हुआ है। 80 लाख की बिल्डिंग बनी हुई है । उसमें ताले लगा रखे हैं। एक टूटी हुई बिल्डिंग में वह प्राईमरी हैल्थ सैंटर डाल दिया और ताला लगा है पी0एच0सी0 में। मैंने अनेकों

06.03.2017/1730/केएस/एजी/2

पत्र लिखे। आपने जवाब भी दिया लेकिन आज तक उस पी0एच0सी0 को पी0एच0सी0 के अंदर वापिस नहीं किया है।

उपाध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहां सदन में भी कहा था कि मैं इस प्राईमरी हैल्थ सैंटर को प्राईमरी हैल्थ सैंटर बना दूंगा जिसको आपने ई0एस0आई0 नोटिफाई किया। न वहां पर दवाई है, एक्सपायर्ड दवाइयों का ढेर, मैंने मिडिया को चैक करवाया। आपने मेरे विधान सभा के प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज़ के पैसे निकालकर दूसरी जगह उठा लिए। तीन बार आपने सदन में आश्वस्त कर दिया। चिट्ठी भी मुझे लिख दी लेकिन यह 3 करोड़ रुपया गांव से निकाला हुआ, आज तक वापिस नहीं आया। मैंने यहीं पर कहा था कि आप वार्ड ब्वॉय को पी0एच0सी0 में रखे हुए हैं। नाहन का वार्ड ब्वॉय गांव में है। तीन बार आपने चिट्ठी लिख दी लेकिन या तो विभाग आपकी नहीं सुनता या फिर आप करना नहीं चाहते।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों की हड़ताल हुई। मैं हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में कहना बन्द करने जा रहा था परन्तु शिलाई में डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही आयुर्वेद की बात करता हूं। 40 या 38 आयुर्वेदिक हैल्थ सैंटर्ज़ खोले। 40 डॉक्टर भर्ती किए 38 हैल्थ सैंटर्ज़ खोले और 150 खाली है। खोलने का क्या फायदा? फिर यहां लिखा है राजगढ़ का अस्पताल बेहतरीन

अस्पताल है। वहां पर दो डॉक्टर हैं जबकि वहां पर आठ पोस्टें सेंक्शन है। शिलाई में चार पोस्टें सेंक्शन है, दो है। ददाहू में आठ की सेंक्शन है, सी0पी0एस0 साहब तो बेचारे बोलते नहीं होंगें परन्तु मरीजों की हालत खराब है। यह जो डॉक्टरों की हड़ताल हुई, यह दादागिरी किस बात की है? क्या डॉक्टरों के ऊपर भी दादागिरी चलेगी?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

6.3.2017/1735/av/ag/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी

डॉक्टर को बोला कि 50 प्रतिशत डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाए। वह पढ़ा-लिखा डॉक्टर है कैसे एम0बी0बी0एस0 बनता है, कैसे एम0एस0 या एम0डी0 बनता है। उसकी टीम बैठती है। उसके कारण प्रदेश में हड़ताल हुई और कितने मरीजों का नुकसान हुआ। ट्यूबरकुलोसिस की जो इस बार रिपोर्ट पब्लिश हुई है वह हमारे लिए चिन्ताजनक है। मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं कि प्रदेश के ऐक्सचैकर का नुकसान नहीं होना चाहिए। कण्डाघाट में आपका एक शानदार हॉस्पिटल है और वह चार मंजिला हॉस्पिटल है। अभी-अभी आपने उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और राजनैतिक आधार पर नई बिल्डिंग का शिलान्यास कर दिया। वहां पर दो डॉक्टर हैं। दो की सैंक्शन है, एक पोस्टिड है और तीस पेशैंट की ओ0पी0डी0 है। वहां 3.50 करोड़ रुपये की नई बिल्डिंग बनी है लेकिन आपने 16 करोड़ रुपये का नया शिलान्यास कर दिया। पुरानी बिल्डिंग का क्या करेंगे; यह समझ से बाहर है।

कानून-व्यवस्था, विधायक का दबदबा; क्या हालत है? सुबाथु के अंदर आई0एस0 के पोस्टर, सुबाथ में आई0एस0 के नारे, सुरक्षा एजैंसियों की नींद हटी, विधायक के घर में घुसकर के गाड़ियां तोड़ी, विधायक के घर के ऊपर हमला; यह सारी डिटेल मैं यहां पर *ले* कर दूंगा। दून के विधायक के घर के ऊपर हमला; ये सारी अखबारों की कटिंग हैं और मैं इनको *ले* कर रहा हूं। शिलाई में गरीब के घर पर टूटा खाक़ी का कहर, पुलिस की दरिन्दगी-पूछताछ के लिए नोच लिए युवक के बाल; यह मैं नहीं बोल रहा हूं। अब पुलिस

की वर्दी देखकर लगता है डर; इन सबकी जांच होनी चाहिए। रिलायन्स के 'जियो' के दफ्तर को उड़ाने का षड़यन्त्र, पांवटा में दिन-दिहाड़े लूट, बेटी के विवाह को रखा सामान चोरी, माज़रा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं चोरियां; हमारी हालत कहां पहुंच गई है?

6.3.2017/1735/av/ag/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुए 27 मिनट से ज्यादा समय हो गया है।

डॉ0 राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, हमें राजनीतिक आधार से हटकर प्रदेश की चिन्ता करनी होगी। माननीय नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में आये और यहां पर 61 नेशनल हाई वे देकर चले गये। लेकिन हम डी0पी0आर0 नहीं भेज रहे हैं, आप लोग कौन सा लाभ लेकर जाना चाहते हैं? यहां पर राजनीति की पराकाष्ठा लगातार हो रही है। ये लोग क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं। यहां पर अभी सुधीर जी भी बैठे हैं। अगर स्मार्ट सिटी मिलेगा तो धर्मशाला को, अगर कॉर्पोरेशन मिलेगी तो धर्मशाला को, अगर राजधानी मिलेगी तो धर्मशाला को; हमारे मंत्री जी का यह कौन सा जादू मुख्य मंत्री जी के सर चढ़कर बोल रहा है जो शिमला के इलाके को उजाड़ने का षड़यन्त्र चला है? सुधीर जी और मुख्य मंत्री जी की फोटो लगी हुई है, स्मार्ट सिटी दिया है मोदी जी ने, स्मार्ट सिटी दिया है केंद्र सरकार ने लेकिन पूरे हिमाचल में इनकी फोटो के बोर्ड लगे हुए हैं। हमारे सिरमौर में बोर्ड लगाकर हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं। स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए आप आमन्त्रित हैं। क्यों, क्या नाहन स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता? धर्मशाला से ज्यादा आबादी नाहन की है। 22,000 की आबादी पर आपने धर्मशाला को कॉर्पोरेशन बना दिया, 50,000 की आबादी पर आपने सोलन को कॉर्पोरेशन नहीं बनाया, 23,000 की आबादी पर नाहन को कॉर्पोरेशन नहीं बनाया; आप क्षेत्रवाद की बात करते हैं? आपने हर विभाग के मन्त्रालय को अपने तक सीमित कर दिया है। हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र थे वहां से उद्योग उजाड़ दिए और उद्योग मंत्री ने अपने क्षेत्र में लगा दिए। तीन-तीन हजार लेबरर्ज को काम देने वाले उद्योग हमारे यहां से बंद कर दिए

श्री वर्मा द्वारा जारी

06/03/2017/1740/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
डा0 राजीव बिंदल - - - जारी

और वहां लग रहे हैं, जहां के उद्योग मंत्री है। इस तरह से आप इलाकावाद फैला रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिरमौर और प्लॉनिंग डिर्पाटमेंट की मीटिंग में माना कि सिरमौर के ठेकेदार काम नहीं करते हैं और वे भ्रष्टाचारी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन ठेकेदारों के सरगना कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और नेता बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालत क्या है, ये हमें जुमले वाली पार्टी बोलते-(व्यवधान)-

Speaker: Shri Rajeev Bindal Ji, I will not allow you now. You have already taken half an hour. अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं। लेकिन आपका यह खत्म ही नहीं हो रहा है। आपने जितने अख़बार इक्ट्ठे कर लिए हैं। ये दो घण्टे में भी खत्म नहीं हो सकते हैं।

डॉ0 राजीव बिंदल: सर, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि ये म्युनिसिपल कमेटी में गंदगी उठाने के काबिल हैं और ये जुमले वाली पार्टी है। मुख्य मंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी को कहते हैं- आपके कहने से मैं कुएं में छलांग नहीं मार सकता। मुख्य मंत्री जी अपनी पार्टी के नेताओं को कहते हैं- मेरे रास्ते में रोडा अटकाने वाले नहीं बचेंगे। इतना ही नहीं अपनी पार्टियों के लोगों को कहते हैं - कईयों को हर काम में खुज़ली होती है, मेरे पास खुज़ली मिटाने की दवा है। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर सी0एम0 की तलख टिप्पणी- 24 घण्टों में 24 बार बदलती है, बाली की सोच। सुक्खू अपने हलके से चुनाव लड़ने की तैयारी करें, ये मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं। फिर ये कहते हैं- कागजी नेता खड़ा न करें, सुक्खू जी। क्या ये सरकार चल रही है? सरकार संगठन से बनती है, अपमान से नहीं, ये सुक्खू जी कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार ने आपस में लड़ते-भिड़ते साढ़े चार साल बिता दिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी ये दूसरी राजधानी का शगुफ़ा छोड़ते हैं,

कभी बेरोज़गारी के ऊपर आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। मैं अतं में नाहन में एक कवि द्वारा रची कविता की दो लाईनें कहना चाहता हूंः-

" थोड़ी-सी तू लिफ्ट करवा दे, मेरे इलाके में एक गांव है- जमटा,
वहां सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं चाहिए, स्कूल और
अस्पताल भी नहीं चाहिए, मुझे एक अद्द राजधानी दिलवा दे"।

06/03/2017/1740/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जिस तरह चल रही है और महामहिम महोदय से इन्होंने जो बातें लिखवाकर प्रस्तुत की है, वे उचित नहीं हैं, इनको देखते हुए हम इसका समर्थन करने में असमर्थ हैं। धन्यवाद।

06/03/2017/1740/टी0सी0वी0/ए0एस0/3

स्वास्थ्य एवं परिवार एंव कल्याण मंत्रीः मैंने माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिंदल जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना। इन्होंने अपना भाषण सिर्फ अखबारों तक ही सीमित रखा। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बात की है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने प्रदेश में केवल 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले और एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं की। अब हम उस प्रोसैस से गुजर रहे हैं। इनके समय में मेरे चुनाव क्षेत्र में 6 प्राइमरी हैल्थ सेंटर बिना डॉक्टरों के रहे हैं और एक सुधार में डॉक्टर लगाया, उसको भी डैपूटेशन में पालमपुर भेज दिया। चार साल तक मैं प्रश्न पूछता रहा।

श्रीमती एन0एस0 - - - द्वारा जारी।

06/03/2017/1745/ns/as/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री------जारी।

प्रश्न पूछना, डेप्यूटेशन खत्म करना और प्रश्न खत्म हुआ तो डेप्यूटेशन फिर पालमपुर या मण्डी में चला जाता था। मैं माननीय अध्यक्ष जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो डॉक्टर्ज़ के पद हैं इन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर की पोस्ट क्रिएट नहीं की और हमने चार सालों में 500 डॉक्टर्ज़ के नये पद क्रिएट किए हैं। इसमें एक्सपैन्शन बहुत हुई है। लगभग 185 नये स्वास्थ्य संस्था खोली गई हैं। अभी भी हमें 550 और डॉक्टर्ज़ की जरूरत है। फिर भी रेशनेलाईजेशन के आधार पर जहां-जहां पर जितना वर्कलोड है उसके मुताबिक हम डाक्टर्ज़ भेजने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन माननीय बिन्दल जी शायद अपना वक्त भूल गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग में उस समय स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गईं थी लेकिन आज स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। हम मानते हैं कि डाक्टर्ज़ की कमी है। हमने लगभग 1200 स्टॉफ नर्सों की पोस्टें क्रिएट की हैं। हमने ओ0टी0ए0, फार्मासिस्टों की पोस्टें क्रिएट की हैं और हमारी यही कोशिश है कि हम स्वास्थ्य विभाग में ओर ज्यादा सुधार करें। हर मंगलवार को डाक्टरों की वाक-इन-इंटरव्यू हो रही है। पंजाब और हरियाणा से डाक्टर्ज़ आ रहे हैं, हम उनको भर्ती करके लगा रहे हैं। अगर आप हमें 550 डॉक्टर्ज़ दे देंगे तो मैं उनको कल अप्वाईटमैंट देने के लिए तैयार हूं।

06/03/2017/1745/ns/as/2

अध्यक्ष : अब श्री राकेश कालिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पर जो अभिभाषण दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव माननीय श्री जगजीवन पाल और उसका अनुसमर्थन माननीय श्री संजय रतन जी ने किया है। उसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की चार साल की जो गाथा महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ी है,

उसके लिए हम राजा वीरभद्र सिंह जी के आभारी हैं और उनके लिए कुछ पक्तियां एक कवि की लिखी हुई मैं कहना चाहता हूं।

"राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है

जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर सवेरे उगता है"

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने दर्जनों कॉलेज, सैंकड़ों स्कूल खुलवाये हैं। स्टूडैंटस के लिए फ्री यात्रा, फ्री लैपटॉप, फ्री बर्दी की सुविधा भी दी है। इसके अतिरिक्त 80 साल के ऊपर के वृद्धों को 1200 रूपये पैंशन देने की योजना भी माननीय मुख्य मंत्री जी लाए हैं। इसी तरह हाउसिंग सबसिडी की राशि पहले 50,000 रूपये मिलती थी उसको अब इन्होंने 75,000 रूपया कर दिया है। इसी तरह से विधवा पैंशन और अपंग पैंशन को बढ़ाया गया है। हजारों लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था की गई है। ऊना जिले में राशन की योजना पिछले टैन्योर में माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने शुरू की थी तो मैं इसके लिए इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस टैन्योर में भी वही राशन की व्यवस्था जिसमें हमारे जैसे लोग, इनकम टैक्स पेयर भी उस योजना का आज भी लाभ उठा रहे हैं। गरीब-से-गरीब व्यक्ति और ईम्लायीज़ भी उसका लाभ ले रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश की जनता राजा वीरभद्र जी का धन्यवाद करना चाहती है। मुख्य मंत्री कन्यादान योजना की राशि भी बढ़ाई गई है। इसी तरह एम0एल0ए0 फंडज़ की राशि जो कि 50,000 रूपया होती थी उसको आपने बढ़ा करके एक करोड़ रूपया कर दिया है। उसके लिए हम मुख्य मंत्री जी

06/03/2017/1745/ns/as/3

का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हम विशेषतौर पर इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें डिस्क्रीशनरी ग्रांट पांच लाख रूपया देकर मंत्रियों के बराबर खड़ा कर दिया है। जो हमारी सोशल ओबलीगेशन्ज़ होती थी जैसे कि हम किसी टूर्नामैंट या स्पोर्टस फंकशन में जा करके अपनी जेब से पैसे देते थे उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय ने डिस्क्रीशनरी ग्रांट दे करके हमें मंत्रियों के लैवल पर खड़ा किया है। इसके लिए हमारे अन्य

एम0एल0एज0 भी इनका धन्यवाद कर चुके हैं और अब भी धन्यवाद की भावना इनके चेहरों पर नज़र आ रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो जनरल कास्ट के गरीब लोग थे उनके लिए भी इन्होंने साल का एक मकान देने की व्यवस्था की है। उसके लिए हम इनके आभारी हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी।

06/03/2017/1750/RKS/DC/1

श्री राकेश कालिया .....जारी

मेरे जो विपक्ष के साथी हैं वे यह कह रहे थे कि खनन बहुत हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि खनन का सीधा संबंध विकास के साथ है। अगर रेता, बजरी या सीमेंट आएगा तभी गांव के रास्ते,सड़कें या भवन बनेंगे। अगर व्यवस्थित रूप से नियमों के आधार पर खनन हो तो तभी विकास हो सकता है। यहां पर कोई बड़े लैवल पर खनन नहीं हो रहा है। परन्तु यहां पर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि खनन बड़े लोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी नदियां हैं यदि उनकी सील्ट निकाली न जाए तो ये नदियां ऑवर फ्लो हो जाएगी। हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमारे लोग बीच-बीच से डिसिल्टिंग करते रहते हैं, रेता/बजरी निकालते रहते हैं उससे नदियों का डैप्थ लैवल बना रहता है। बेशर्त जे.सी.बी. से ज्यादा गड्ढे न किए जाएं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे चुनाव क्षेत्र में एक तहसील खोली है और एक कॉलेज का सरकारीकरण भी किया है जोकि पिछली सरकार नहीं कर पाई थी। जब भी देश या प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तो इन्होंने एक काम कॉमन किया है और वह है मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी के ऊपर मुकद्दमें बनाना। भाजपा वाले चार वर्षों से कह रहे हैं कि आज सरकार गई, कल गई, परसों गई, टूटने वाली है, हम आने वाले हैं और जब लोक सभा का चुनाव आया तो इसी दहशत के

माहौल में चुनाव निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बड़ी दृढ़ता के साथ चल रही है और यह सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी हुई थी तो हिन्दुस्तान में आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे। उस समय यहां आर्थिक मंदी नहीं आई। लेकिन जब पूरे विश्व में खुशहाली थी, तो खुशहाली के दिनों में नोटबंदी करके आपने लोगों को कष्ट में डाल दिया। इसके लिए लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। विकास दर दिन-प्रति-दिन गिरती जा रही है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, हमारी स्वां नदी का पैसा आपने रुकवा दिया है। यह सत्य सबके सामने आ गया है कि पैसे को रोकने के पीछे किसका हाथ है। कौन पैसे को रुकवा रहा है। विपक्ष के नेता भी यहां पर बैठे हुए हैं। आप दिल्ली जाकर पैसा रुकवाइए। जो झूठे पेपर आप उठा-उठा के दिखा रहे हैं,

06/03/2017/1750/RKS/DC/2

खबरे दिखा रहे हैं इसे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। हिमाचल से जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए आप केंद्र से पैसा लाइए तब जाकर आपका कल्याण होने वाला है नहीं तो इस समय जो यहां पर आप 23-24 सदस्य बैठे हैं वे 17-18 ही रह जाएंगे। जो आप ट्रीपल आई.टी. व सैन्ट्रल युनिवर्सिटी का मुद्दा उठा रहे हैं उसका आप दिल्ली से हल नहीं करवा रहे हैं। तेल के डिपू के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। एक बात हमारे साथी कह रहे थे कि मुख्य मंत्री महोदय घोषणाएं कर रहे हैं जोकि पूरी नहीं हो रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब मुख्य मंत्री महोदय किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के एम.एल.ए. के ऊपर लोगों का स्ट्रैस होता है कि वे ज्यादा-से-ज्यादा घोषणा करवाने की कोशिश करें। लेकिन यह एम.एल.ए. और मुख्य मंत्री दोनों को पता होता है कि 3-4 घोषणाएं ही इम्प्लीमैंट होनी है। बाकियों में यह कहा जाता है कि देखा जाएगा। लेकिन जो भाजपा के मुनीम बैठे हैं, वे लिख देते हैं कि जो देखा जाएगा वे भी घोषणाएं कर दी । इनका खाता/ खाना खराब है। इसलिए इन्होंने अपन अकाउन्ट गलत बनाया है। सारी घोषणाएं पूरी हो रही हैं। आपके प्रधान मंत्री ने पूरे विश्व में हिन्दुस्तान का नाम नीचे गिरा दिया है। पंचायत तक व मुख्य

मंत्री लैवल के लोगों के ऊपर प्रधान मंत्री महोदय एलिगेशन लगा रहे हैं। पहले प्रधान मंत्री ऐसा नहीं बोला करते थे। उन्होंने कहा था कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे। जब प्रधान मंत्री जी की पहली ओथ थी तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बर्थ डे था तो उन्हें बर्थ डे विश करने के लिए प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान चले गए। उसके तुरन्त बाद हिन्दुस्तान के ऊपर कितने हमले हुए यह आप सब जानते हैं। आई.एस.आई.एस. जो हिन्दुस्तान में हमले करवाती हैं उनके ऑफिसर्ज को हिन्दुस्तान में पठानकोट के अंदर एयरबेस देखने की इज़ाज़त दे दी गई। जब हमारे लोगों ने कहा

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

06.03.2017/1755/SLS-DC-1

श्री राकेश कालिया...जारी

कि हम भी यह देखने के लिए अपने अधिकारी वहां भेजना चाहते हैं कि टैरोरिस्ट कैंप कहां-कहां हैं। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन देश को अपने क्षेत्र में आने की इज़ाज़त नहीं देते।

आप बेअमनी की बात कर रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ? आपने पूरा हरियाणा, जिसमें आजतक कभी भी हिंसा नहीं हुई थी, जलाकर रख दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से आप दिल्ली में आए हैं, आपकी पार्टी का शासन पूरी तरह से फेल हुआ है, जिसके लिए आपको हिंदुसतान के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे।

ज्यादा न कहता हुआ, जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां पेश किया गया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री महेश्वर सिंह जी अपनी बात रखेंगे। Please be brief.

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहली मार्च को जो इस माननीय सदन में राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है, उस पर यहां चर्चा हो रही है और मैं भी उस चर्चा में भाग लेने के लिए आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं।

महोदय, निःसंदेह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार के कारनामों का एक दर्पण होता है कि कौन-सी नीतियों का अनुसरण किया गया और भविष्य में सरकार किस प्रकार से काम करेगी; कौन-सी नीतियां रहेगी।

प्रथम पैरा में ही राज्यपाल महोदय से एक बात कहलवाई गई है कि "अच्छे कार्यों का साक्षी है।" न जाने कौन-कौन से अच्छे कार्य किए होंगे। उनका अभी-अभी एक ट्रेलर

देखने को मिला। आपके माध्यम से राकेश कालिया जी को इस बात के लिए, सत्य बात कहने के लिए बधाई दूंगा। इन्होंने कहा कि घोषणाएं तो बहुत होती है लेकिन पहली चार ही कार्यान्वित होती हैं, बाकी तो लोगों का मन बहलाने के लिए कही जाती हैं। आपने यह स्वीकारा, इसलिए मैं यह कह रहा हूं। यह बहुत अच्छी बात है। ...(व्यवधान)... मैंने इसके लिए आपका धन्यवाद किया। आपने सत्यता कही है जिसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आपका आदर कर रहा हूं।

हमारे एक वरिष्ठ सदस्य और हमारी हाऊस कमेटी के अध्यक्ष महोदय जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने एक बात पर बड़ा बल दिया और सबका कल्याण तथा समग्र विकास की बात कही। बार-बार कहा कि जो घोषणाएं की गई हैं वह सारी पूरी हो गई हैं। वह तो राज्यपाल महोदय के माध्यम से कहलवाया गया है कि चुनाव घोषणा-पत्र में जितनी

घोषणाएं की थीं वह सारी पूरी कर दी गई हैं। लेकिन आपने कहा कि कुछ छूट गईं, वह भी

06.03.2017/1755/SLS-DC-3

पूरी हो जाएंगी और बाकी की आपने तारीफ़ की। जब आप तारीफ़ कर रहे थे तो मैं देख रहा था। आपने यहां तक कह दिया कि जो घोषणा-पत्र में बात थी कि जितने भी जंगली जानवर हैं, बंदर हैं, विशेषकर जो पालतू पशु हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए सरकार काम करेगी और सरकार कृत-संकल्प है। यह चुनाव घोषणा-पत्र में था। आपने कहा कि गौसदन बन गए। आपके क्षेत्र में बने होंगे। शायद लोगों को इन आवारा पशुओं से निजात मिली होगी। लेकिन आपके ही जिला के कुछ लोग कह रहे थे कि साँड का आतंक इतना है कि साँड लोगों को मार रहे हैं। दो दिन पहले संभवतः परवाणु में एक लंगूर 3 साल के बच्चे को उसकी मां से छीनकर पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से बच्चा फैंक दिया। यही था आपके चुनाव घोषणा-पत्र में जो आपने पूरा किया। ...(व्यवधान)... मित्र होना अलग बात है लेकिन स्पष्टवादी होना अलग बात है। जब आप इतनी बातें कह रहे थे तो मुझे लगा कि एक कहावत है - रागों भूली रागणी, गाए आल-बताल। जो चीज नहीं भी हुई वह भी आपने कह दी।

जहां तक बेरोज़गारी भत्ते की बात है, यह स्पष्ट रूप से कही गई थी। हैरानी की बात है कि आज मुख्य मंत्री जी उस बात को लेकर क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह घोषणा-पत्र

तो अनुभवहीन लोगों ने बनाया, मैं तो इसका मैंबर ही नहीं था। अरे, वाह-वाह। वित्त मंत्री आप, मुख्य मंत्री आप। आप बिना पढ़े ही यह कह रहे हैं और यही गवर्नर महोदय से भी बुला दिया कि शत्-प्रतिशत् इसका अनुसरण हो गया है।

कुछ बातों को लेकर जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहां खड़े हुए तो मैं मन-ही-मन सोच रहा था और इनकी बॉडी लैंगुएज से भी लग रहा था कि ये सच्ची बात नहीं कह रहे हैं। आपको तो विश्वास में ही नहीं लिया जाता। जब अपग्रेडेशन हो जाती है,

जारी .. श्री गर्ग जी

06/03/2017/1800/RG/AG/1

श्री महेश्वर सिंह----क्रमागत

और इनकी बॉडी लैंगुएज से भी लग रहा था कि ये सच्ची बात नहीं कर रहे हैं। आपको तो विश्वास में ही नहीं लिया जाता। जब घोषणा हो जाती है, तो आपको विश्वास में नहीं लिया जाता। आपका एक काम है कि जो पद खाली होते हैं उनको भरते हैं और मुख्य मंत्री जी दूसरे दिन और घोषणाएं करते हैं और फिर पद खाली हो जाते हैं। आपने वकालत तो की और आप एक बहुत निपुण वकील हैं, लेकिन यह केस बहुत घटिया है और इसके लिए आपकी वकालत काम नहीं आएगी।

अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग में ऐसी स्थिति है। आपने कहा कि 27 कॉलेज बन गए। तो क्या हुआ? यह वैसी ही घोषणा है जैसा कालिया जी ने कहा। घोषणा तो कर दी, लेकिन जो चलते हुए इन्स्टीटियूट्स थे उन सबका सर्वनाश हो गया। यहां से पूछा गया था, लेकिन आपने यह नहीं बतलाया कि आखिर कॉलेज में स्टाफ की हालत क्या है? कितने टीचर्ज और प्रोफैसर्ज हैं? सिर्फ घोषणा पर घोषणा की गई, सच पूछो तो शिक्षा विभाग का आपकी सरकार ने बंटाधार कर दिया। प्राथमिक स्कूल ऐसी जगह खुले हैं जहां बच्चे ही नहीं हैं और आप यहां क्लेम कर रहे हैं कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की पाठशाला में नामांकित होने की दर 99.9 % है। क्या यह सत्यता नहीं है कि जो आज रिमोट एरियाज़ में प्राथमिक स्कूल हैं वे टीचर की सुविधानुसार चल रहे हैं न कि बच्चों की संख्या पर? अगर ऐसी स्थिति होती, तो आज यह हालत न होती। आज सिरमौर के पहाड़ों में, रोहड़ू और रामपुर के पहाड़ों में और हमारे क्षेत्रों में ये टीचर अपनी स्वार्थसिद्धी के लिए वहां रहने के लिए गोरखा लेबर और बिहारी लेबर के बच्चे दाखिल करते हैं। उनके सिर पर ये स्कूल चल रहे हैं। क्योंकि उन टीचर्ज को वहां रहना है, भले ही वे अपने बच्चे भी स्कूल में नहीं पढ़ाते। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहां लग वैली है। लग वैली में एक स्कूल है।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे ऊपर ही सारा कटाक्ष कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा स्पष्टीकरण का मौका दिया जाए।

06/03/2017/1800/RG/AG/2

श्री महेश्वर सिह : मैंने आपको कोई व्यक्तिगत बात नहीं कही, मैंने आपको कुछ व्यक्तिगत बुरा नहीं कहा, आपकी बात नहीं की।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन यह इनकी मजबूरी है। पहले इधर टोपी कुछ और थी, लेकिन अब टोपी का रंग रोज बदल रहा है। लेकिन मैंने इस सदन में जो कुछ बोला है वह सब तथ्यों के आधार पर बोला था।

श्री महेश्वर सिंह : अब बहुत हो गया, अब छोड़िए भी। अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक प्राथमिक पाठशाला है और वह खोपड़ी गांव में है। ताज्जुब की बात है कि वहां दो अध्यापक हैं और एक विद्यार्थी है। वहां बहुत बढ़िया खिचड़ी पक रही है। एक बच्चे के ऊपर चार-चार लोग बैठे हैं, तो उसकी बुद्धि का विकास कहां होगा, मुझे समझ नहीं आता। ऐसी स्थिति है, फिर आप कहते हैं कि हमने स्कूलों की संख्या बढ़ा दी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्वालिटी पर जाते हैं या क्वांटिटी पर जाते हैं?
अध्यक्ष महोदय, यही नहीं कुल्लू कॉलेज है। मैंने कुल्लू कॉलेज के बारे में पहले भी कहा था। दो वर्ष पहले एक कॉलेज था उसमें बच्चों की संख्या 5,000 थी और 92 प्रोफेसर्ज एवं असिसटैंट प्रोफेसर्ज थे। आज उसकी क्या दुर्गति हुई कि एक कॉलेज के 6 हिस्से हो गए। कुल्लू कॉलेज में छात्रों की संख्या आज भी 4,500 है, सिर्फ 500 घटी है और केवल 30 प्रोफैसर्ज रह गए और उनको भी प्रतिनियुक्ति पर कब इधर-उधर भेज देंगे, यह भगवान के हाथ में हैं या फिर सरकार के हाथ में है। क्या यही और इसी प्रकार से शिक्षा संस्थान चलेंगे? प्लस टू स्कूल बना दिए, एक प्रिंसीपल है और एक वहां ग्रेजुएट टीचर है और प्लस टू स्कूल है। कहीं पर तो ऐसी स्थिति है कि प्रिंसीपल भी नहीं है। केवल संख्या में वृद्धि हुई

है, यह बात मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जो शिक्षा का स्तर गिरा है उसको भी आपको स्वीकारना होगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ बातें डॉ. बिन्दल जी ने भी कहीं। अभिभाषण में कहा गया कि 99 % स्कूलों में शौचालय है और छात्राओं के लिए अलग से शौचालय है। पुस्तकालय है। जब आपके पास स्कूल के भवन ही नहीं हैं, तो ये चीजें कहां रखी हैं? यह कैसे कहा जा रहा है। स्कूलों में पानी तक नहीं है। अनेकों स्कूलों में पानी बहुत दूर है। यहां तक की मेरे

06/03/2017/1800/RG/AG/3

चुनाव क्षेत्र में एक खलाणा गांव आता है। वहां स्कूल है और सारे कुल्लू शहर को खलाणा से पानी की सप्लाई आती है, लेकिन उसी स्कूल में आज बच्चों को पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, स्कूल के नलके में पानी नहीं है। ये कौन सी बात कह रहे हैं कि हमारे यहां बहुत कुछ काम हो गया। यह मेरी समझ में नहीं आता।

एम.एस. द्वारा जारी

06/03/2017/1805/MS/AS/1

श्री महेश्वर सिंह जारी---------

और छोड़िए। आपके भवनों का निर्माण उसके लिए कैसा प्रावधान किया गया है। जब विभाग यहां से पैसे का प्रावधान करता है तो यह भी नहीं पूछता कि तुम्हारे पास जमीन है या नहीं। जिस स्कूल के पास जमीन नहीं है उस स्कूल के लिए पैसा और जिस स्कूल के पास जमीन है उसके लिए पैसा नहीं देते। पहले तो दो डायरेक्टोरेट थे। एक को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कहते थे और दूसरे को हायर एजुकेशन निदेशालय कहते थे। अब एक तीसरे की उत्पत्ति कर दी और वह है प्रोजैक्ट डायरेक्टोरेट सर्वशिक्षा अभियान और रमसा। उसका काम क्या है? यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है फिर भी स्टाफ डैपुटेशन पर रख दिया। अभी भी कल मैंने एक प्रश्न पूछा था तो 18 लोग डैपुटेशन पर इस प्रोजैक्ट

डायरेक्टोरेट में हैं। महोदय, ये ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और ट्रेनिंग कब देंगे जब फील्ड में स्कूल खुले हैं और अध्यापक वहां से आकर यहां डेपुटेशन अलाऊंस भी लेगा और टी0ए0डी0ए0 भी लेगा। छुटिट्यों के दिनों में ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? उपाध्यक्ष जी, वहां पर कुछ नहीं होता केवल इटिंग, मीटिंग, चिटिंग और सीटिंग और घर को जाओ। ऐसा कार्यालय ये लोग चला रहे हैं और कहते हैं कि शिक्षा में हमने बड़ा विस्तार किया? कहां किया समझ में नहीं आता?

मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इसको अन्यथा नहीं लेंगे। आपने निश्चित रूप से प्रयास किए और एक समय ऐसा आया कि कुल्लू अस्पताल में सब डॉक्टर्ज थे, स्पैशलिस्ट्स थे और मैंने आपका आभार व्यक्त किया। केन्द्रीय सरकार की कृपा में बैठे हुए हमारे नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी कृपा से डायलेसिज सेंटर भी बन गया लेकिन आज क्या स्थिति है? आज फिर अच्छे डॉक्टर्ज का अभाव है क्योंकि जितने वहां स्पैशलिस्ट्स थे, आपने वहां ऑर्थो का डॉक्टर लाया था जोकि स्पैशलिस्ट था लेकिन वह वहां से चला गया क्योंकि कॉलेजिज और दूसरी जगहों पर आप अच्छे डॉक्टर्ज की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। दूसरा एक निर्णय आपने लिया कि जो डॉक्टर ट्राइबल एरिया में जाएगा और एक साल तक वहां काम करेगा उसको पी0जी0 या जो रजिस्ट्रार के इम्तिहान होते हैं उसमें बैठने की अनुमति मिल जाएगी। एक बात तो इस निर्णय से निश्चित रूप से हुई कि ट्राइबल में हर जगह डॉक्टर्ज की भरमार हो गई।

06/03/2017/1805/MS/AS/2

लेकिन एक साल के बाद जो आपकी पॉलिसी है उसके मुताबिक कोई रजिस्ट्रार बन रहे हैं कोई पी0जी0 कर रहे हैं। हिमाचल में आप जानते हैं कि ट्राइबल एरिया से ज्यादा कठिन क्षेत्र भी हैं। आपका चौहार है, बदार है, सनौर में पीछे गांव है, हमारे यहां मलाणा है और इधर डोडरा-क्वार है। क्या वहां पर भी कोई डॉक्टर गया है? वे सिर्फ स्वार्थ के लिए गए क्योंकि आपकी घोषणा थी कि एक साल के बाद पी0जी0 के लिए भेजेंगे। यह घोषणा किसने की? मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी आपको नहीं पूछा होगा। आप ऐसा काम न करते। अगर आपने किया है तो फिर ये दोष आप पर भी लगता है कि ये आपने कैसे भेजे?

क्यों किया ऐसा निर्णय? अभी भी इस पर पुनर्विचार करें नहीं तो हमारे अस्पताल फिर खाली हो जाएंगे, डॉक्टर रहित हो जाएंगे। यह भी सच्चाई है कि आपने इतने स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए है कि जैसे ही आप कहीं स्टाफ पूरा करते हैं उसके चौथे ही दिन एक और स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणा हो जाती है और एक-एक क्षेत्र में छः-छः पी0एच0सीज0 खुल रहे हैं। तो पता नहीं वे कैसे खुलेंगे और कैसे काम चलेगा, यह तो आप जानें? लेकिन इस वक्त जो हालत है वह अच्छी नहीं है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी तब यह स्टाफ पूरा होगा।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आपके अस्पतालों और जिला अस्पतालों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कोई वेटिंग हॉल नहीं है। वे महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और फिर लोगों के घरों में किराया देकर रहती हैं। वहां कोई ऐसी अच्छी हाइजनिक कण्डीशन नहीं होती है और ऐसी कण्डीशन में अगर गर्भवती महिला जाएगी तो उसका क्या हाल होगा? इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि ढालपुर मैदान में ही जो आपका हणोगी माता ट्रस्ट है उनको वह निःशुल्क जगह दी गई है और उन्होंने वहां पर एक धर्मशाला बनाई है तो हमने एक प्रस्ताव दिया था कि उस धर्मशाला का कन्ट्रोल आप डी0सी0 कुल्लू को दे दें क्योंकि अभी उसका कन्ट्रोल डी0सी0 मण्डी के पास है। यह सत्यतता है और आपके द्रंग के सारे मरीज और चच्योट ये जो सराज क्षेत्र कहलाता है और बालीचौकी के लोग भी कुल्लू में इलाज के लिए आते हैं। ऐसी महिलाओं और माताओं को रहने के लिए कोई स्थान नहीं है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

06.03.2017/1810/जेके/एएस/1

श्री महेश्वर सिंहः------**जारी**-------

यह आप करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। दूसरे, आई0जी0एम0सी0 में पहले एक ग्रीन हाऊस था। वहां पर जब मरीज व उनके साथ तीमारदार आते हैं तो उनको बैठने के लिए जगह तक नहीं है। आज उस जगह को बन्द कर दिया गया है और लागों को जगह-जगह भटकना पड़ता है। यहां पर भी एक सरांय का निर्माण होना चाहिए। कौल सिंह जी

आपने ठीक किया यहां पर पी0जी0आई0 की बात की। पी0 जी0आई0 में क्या हालत है वहां पर हिमाचल सरांय हैं लेकिन संचालन कौन करता है आपका मंत्रालय का भी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है वह कैसी हिमाचल सरांय है? वह क्यों बनाई है, किसके लिए बनाई है और वहां पर कितने पैसे देने पड़ते हैं, मुश्किल से वहां अन्दर एडमिशन मिलती है? तीमारदार कहां रहें? मरीज को जब आऊट डोर करते हैं तो वह कहां रहें? उनको घर वापिस जाना पड़ता है या मकान किराये पर लेना पड़ता है। मैं केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्री का आभारी हूं जिन्होंने वहां पर एक ओ0एस0डी0 की व्यवस्था की है। हिमाचल सरकार ने भी वहां पर एक एच0ए0एस0 ऑफिसर रखा था, लेकिन उनका काम डिफाईन नहीं किया। अच्छा होता कि उनका ऑफिस उसी पी0जी0आई0 क्षेत्र में होता। जो यहां से मरीज जाते हैं वे उनकी मदद करते ताकि जल्दी से जल्दी डॉक्टर्ज से अप्वाइंटमैंट मिलती। उनकी देख-रेख में हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। एक तरफ तो ओ0एस0डी0 केन्द्रीय मंत्री के हैं और एक तरफ आपके कोई अधिकारी हो। केवल इस काम के लिए तैनात हो और वह सुनिश्चित करे कि हिमाचल सरांय में तीमारदारों को भी जगह मिले और मरीजों को भी मिले, इससे लोग आपकी तारीफ करेंगे।

पैरा-24 में भांग उखाड़ने की बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान में भी यह बात लाना चाहूंगा कि इनका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र इन्हीं बातों के लिए बदनाम है कि यहां पर भांग की खेती होती है, लेकिन उनके कष्ट को कभी देखा है? वे ऐसे पहाड़ों व कंदराओं में बसे हुए लोग है जहां पर उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। वे कहां जाए? केन्द्र सरकार ने एक दफा प्रावधान किया था कि इनके रिहेब्लिटेशन के लिए प्रोग्राम बनें और इनको कैश क्रॉप पैदा करने के लिए मदद की जाए जो उन क्षेत्रों में होगी, लेकिन उस तरफ कार्य शून्य है। इसके लिए भी सरकार ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया कि भांग के रेशे से भी कोई चीज़ बनती है।

06.03.2017/1810/जेके/एएस/2

कुल्लू में एक बार सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में कुछ ऐसे लोग आए जो इस नशाबन्दी से सम्बन्धित थे। मादक वस्तुओं के व्यापार के विरूद्ध आए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि

मुम्बई में कोई कम्पनी है और उन्होंने खोज की है कि जो भांग का रेशा है उससे ऐरोप्लेन की बॉडी बनती है और सबसे अच्छा रॉ मटिरियल उसके लिए है। उसके लिए सरकार क्यों नहीं प्रयास करती है? सरकार उनसे सम्पर्क करे और यदि हमारी भांग का रेशा मंहगा बिक जाए तो कौन फिर यह अवैध धन्धा करेगा? इसको निश्चित रूप से छोड़ देंगे। इसलिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें तब तो भांग के पौधे उखाड़े नहीं तो हमारा जो स्थानीय उद्योग था रस्सी पशुधन को बांधने के लिए और जो हमारे लिए मंगोलू मिलते थे जो खान-पान की व्यवस्था थी उसमें नशा नहीं होता वह सब तो आपने बन्द कर दिया और पाँव में पुलें लगाते थे। आज उन पुलों की जगह वी-शेप चप्पल खरीदने के लिए लोग मजबूर है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से खास करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को जानते हैं इसलिए अपने क्षेत्र का भी उद्धार करिए और हमारे क्षेत्र का भी उद्धार करें। जहां पर भांग नहीं होती वहां की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त भांग वालों की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, बागवानी को लेकर बहुत सी बातें कही गई है, लेकिन बागवानी में एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये इटालियन पौधे आए ये कैसे पौधे आए? उसको तो कन्फर्म करने की बात है, लेकिन उसके लिए फिर ऐसी व्यवस्था की कि जिसको एरिया में बांटा गया कि इन्हीं लोगों को बांटे जाएंगे, जिनके पास

सिंचाई व्यवस्था है। विभाग ने पता नहीं किससे सर्वे करवाया। न तो किसी फ्रूट एसोसिएशन को पूछा और न ही किसी प्रोग्रैसिव फार्मर को पूछा। मनमाने ढंग से जहां पर सिंचाई व्यवस्था भी नहीं है वहां पर भी वे पौधे बांटे जा रहे हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी .....

06.03.2017/1815/SS-AS/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

और जिनके सिंचाई और कूहलें लगी हैं उनको पौधे नहीं मिल रहे। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी छानबीन करें।

अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग को लेकर बजट के समय भी चर्चा होगी लेकिन एक अत्याचार जो वर्तमान सरकार ने कुछ लोगों के कहने पर किया है आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कुल्लू में लोक निर्माण डिवीजन-I 1956 से लेकर वहां स्थापित थी। मंत्री जी वाकिफ़ हैं, 1956 की डिवीजन जिसके अन्तर्गत कुल्लू बैरियर तक का एरिया, कोठी मराज़ा का एरिया, मणिकर्ण घाटी, गड़सा घाटी, बजौरा का क्षेत्र, ये सारा-का-सारा क्षेत्र आता था और इसको उठाकर बंजार पहुंचाने की घोषणा की। --(व्यवधान)-- अभी दोनों के लिए बात कहूंगा। भाईवाद अलग होता है। अंदर की बात कहने का हमारे को अधिकार है। ये तो इसमें मुख्य व्यक्ति बने, उस सारी चीज़ को उठाने के लिए। मैं भी बंजार क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। अच्छा होता अगर आप चौथी डिवीजन मांगते और इस पुरानी डिवीजन को न उठाते। हमारी थाली में पड़ी हुई रोटी को न उठाते, मुंह का निवाला न छीनते तो हम ऐसा न कहते। अब आपने जो किया है, अब भी मैंने कहा कि इस पर पुनर्विचार करें। --(व्यवधान)-- महोदय, मैं दो मिनट में बात खत्म करूंगा। 31 पंचायतें आज ऐसी हैं जिनको केवल उस डिवीजन के हैडक्वार्टर पर जाने के लिए 45 किलोमीटर से लेकर 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। जो यह बात हुई है इसकी घोषणा सितम्बर मास में हुई है। मैंने विरोध स्वरूप बड़ा पत्र लिखा। सारे सुझाव दिये। विभाग को भेजा। उसके बाद प्लानिंग की मीटिंग आती है। प्लानिंग की मीटिंग में मैंने 30 तारीख को फिर विरोध किया और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि महेश्वर सिंह जी लिखित रूप में दें मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा। प्लानिंग की मीटिंग में सम्भवतः आप भी थे। यह कहा गया, हम इंतजार में रहे लेकिन स्थानीय मंत्री महोदय को उकसाया गया और इन्होंने

06.03.2017/1815/SS-AS/2

तुरंत 1 फरवरी से उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया और 20 फरवरी को लोकार्पण कर दिया। हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर यहां न्याय नहीं मिलेगा तो अदालत में भी जायेंगे। सर, पहले मैं अपनी बात पूरी करूं फिर मंत्री जी जवाब दें। यह सब किया गया और यह किनका कारनामा हुआ है, जिनको मुख्य मंत्री जी बड़े प्रेम से मकड़झंडू कहते हैं। पहले तो मैं चक्कराता था कि यह मकड़झंडू शब्द कहां से आया। फिर कहा गया कि मंदिर के ऊपर जो मगरमच्छ बनता है उसमें जो झंडा लगता है वह मकड़झंडू होता है। फिर मैंने सोचा और उसका मतलब निकाला। मकड़ मतलब जो जाल बुने मकड़ी का और यह जो मकड़झंडू है इस कान में भी बोलते रहते हैं, उधर को भी बोलते रहते हैं और हर स्टेज पर मुख्य मंत्री को घेरा डाले रखते हैं और जब कहा जाता है कि मेरे प्यारे मकड़झंडू, they are happy. वे बड़े ऑनर फील करते हैं लेकिन ये मकड़झंडू जो कान में बात करके मकड़जाल बुनते हैं और मुख्य मंत्री से ऐसा निर्णय करवा देते हैं जिससे उनकी झंड होती रहे, इसलिए मकड़झंडू कहते हैं और यह मकड़झंडू ही इस सरकार का बंटाधार करेंगे। यह मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं और मंत्री महोदय को एक बात कहना चाहूंगा कि आपको राजनीतिक जन्म देने वाला और महेश्वर सिंह जी को राजनीतिक जन्म देने वाला वही बंजार क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत बहुमत हमको हमेशा पार्वती घाटी, गड़सा घाटी, बजौरा एरिया और खोखर बजौरा से मिलता है। आज आपने उनकी अनदेखी की है। आपको भगवान् भी माफ नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

06.03.2017/1815/SS-AS/3

अध्यक्षः आप (आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री) बोलना चाहेंगे। Please be brief.

आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्रीः मैं बड़े आदर के साथ माननीय सदस्य को कहूंगा, यह विधान सभा है, ठीक है लेकिन परिवार की बात अलग है। जो बात लेकर आए, बंजार क्षेत्र

की बात कर रहे हैं कि आपका पी0डब्ल्यू0डी0 डिवीजन शिफ्ट क्यों हुआ। It was required. आज तक कोई एम0एल0ए0 कर नहीं पाया जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने करके दिया। जहां तक पार्वती की बात है वहां पर सब-डिवीजन है एस0डी0ओ0 बैठा है। साढ़े तीन साल में समर्थन किया, आप क्यों नहीं नया लेकर आए?

जारी श्रीमती के0एस0

06.03.2017/1820/केएस/डीसी/1

आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री जारी-----

मैं ले कर आया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जनता खुश है। कृपया राजनीति न करें। परिवार अलग चीज़ है। मैं तो मालरोड़ से होलीलॉज नाचता हुआ नहीं गया था । ये ही गए थे और आज ये ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं। क्षमा कीजिए, ये मेरे बड़े भाई है, वह बाहर की बात है लेकिन अगर ये राजनीति की बात करें तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाएं कि यह क्यों किया?

अध्यक्षः इस माननीय सदन में कोई भी पर्सनल बात नहीं की जानी चाहिए।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, तथ्यों पर आधारित बात नहीं कही गई। इन्होंने कहा कि उस सब डिविज़न का हैड क्वार्टर आज भी वहीं है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। भुन्तर सब डिविज़न को वहां से उठाकर बंजार के साथ जोड़ा गया और क्षेत्र को भी डिविज़न बंजार के अंदर कर दिया गया है।

आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। जो सब डिविज़न भुन्तर का है, वह भुन्तर में ही है। सिर्फ एक्सिअन शिफ्ट हुआ है। नोटिफिकेशन को पढ़ तो लो।

Speaker: Please don't start personal fight. माननीय सदन में राजनीतिक बात होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री सोहन लाल जी चर्चा में भाग लेंगें।

06.03.2017/1820/केएस/डीसी/12

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे ही आज इस माननीय सदन में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा चर्चा शुरू की गई तो उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर कोई भी आंकड़ों पर नज़र नहीं डाली, कोई चर्चा नहीं की और केवल मात्र एक घण्टा अपने भाषण में ये कांग्रेस के घोषणापत्र को ही पढ़ते रहे और उसी पर चर्चा करते रहे। अभिभाषण पर उन्होंने यह कहा कि यह सारा सफेद झूठ है और इसमें सभी गलत आंकड़े दिए गए है लेकिन प्रदेश में जो इस समय विकास हुआ है, नए संस्थान खुले हैं, चाहे वह स्वास्थ्य संस्थान है या शिक्षा संस्थान हैं या दूसरे कार्यालय है, उनके आंकड़े जो दिए गए हैं वह तो जनता के समक्ष है। इन्होंने कहा कि यह सारा अभिभाषण झूठ का पुलिन्दा है। दूसरे, आदरणीय बिन्दल जी ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने केवल मात्र अखबार की जो पिछले दो-तीन महीनों की खबरें होंगी उन्हें हमें पढ़कर सुनाया इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। अभिभाषण पर और सरकार के जो दूसरे काम हुए हैं उनके ऊपर कोई भी अच्छे कामों के लिए तारीफ करते, उनके बारे में बोलते परन्तु इन्होंने भी उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। अभी मुझसे पहले आदरणीय महेश्वर सिंह जी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हम इनकी इज्ज़त भी करते हैं। पिछले तीन साल इसी सदन में इसी सरकार के तारीफों के पुल भी आप बांधते रहे हैं। इस साल जरूर आपने आलोचना की लेकिन वह भी तथ्यों पर करते तो ठीक था। हमारा यह मानना है कि वर्तमान सरकार जो प्रदेश में विकास के कार्य कर रही है वह पूरे उपलब्धियों से भरे हैं और मैं तो यह कहूंगा कि वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.3.2017/1825/av/dc/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल) जारी

यदि इसकी तुलना पिछली सरकारों से की जाए तो उस तुलना में वर्तमान सरकार की उपलब्धियां बहुत ज्यादा है और कोई भी आने वाली सरकार शायद इन उपलब्धियों के बराबर काम कर सके। किसी भी सरकार ने प्रदेश में अपने कार्यकाल में पहले 45 से ज्यादा डिग्री कॉलेज नहीं खोले हैं। (---व्यवधान---) जो कॉलेज चुनाव से एक महीना पहले घोषित किए थे उनको डीनोटिफाई किया था। जिसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं था, जिसके लिए कोई सैंक्शन्ड पोस्टें नहीं थी, वह डीनोटिफाई किए थे। मैं तो इस चीज को इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ऐसा एक कॉलेज मेरे चुनाव क्षेत्र में भी खोला गया था। युनिवर्सिटी में अगस्त महीने में ऐडमिशन्ज बंद हो जाती है जबकि आपके कॉलेज की अधिसूचना और ऐडमिशन अक्तूबर महीने में हुई। उस कॉलेज में केवल 6 विद्यार्थी थे, एक लैक्चरर था और एक चपड़ासी था। ऐसे कॉलेज की अधिसूचना को डीनोटिफाइड करना ही उचित था। लेकिन हमारी सरकार ने जब कॉलेजों की घोषणा की तो उनके लिए बजट का प्रावधान किया, पोस्टें सैंक्शन की और उनके लिए 5-5 करोड़ रुपये की राशि भी दी। आज उन कॉलेजों के भवनों का निर्माण हो रहा है तथा वे विधिवत चले भी हैं। 45 कॉलेज अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उसके साथ 1329 स्कूलों को प्रदेश में अपग्रेड किया गया है। हालांकि आप उस वक्त से बोलते हैं कि स्कूल अपग्रेड करना कोई विकास नहीं है, इसकी जरुरत नहीं है। लेकिन आज भी जब हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे दूर-दराज के क्षेत्र के लोग अब भी हमसे अपने स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग करते हैं। हम उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निरन्तर आवेदन करते हैं कि हमारे चुनाव क्षेत्र के इस-इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए। प्रदेश में जब-जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है। आज इसी का नतीजा है और मैं तो मुख्य मंत्री जी को

बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जब-जब प्रदेश की सत्ता सम्भाली है तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। यह इन्हीं की नीतिगत सोच और फैसला था जो वर्ष 1993 से 1998 तक इन्होंने प्रदेश में 1000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोले जिसके चलते आज हमारा प्रदेश पूरे देश में शिक्षा के

6.3.2017/1825/av/dc/2

क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी हमारी सरकार ने पिछले चार वर्ष के कार्यकाल में काफी काम किए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो हमारी प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 170 से ज्यादा नये स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं। (---व्यवधान---) विनोद जी, आपकी बारी आयेगी तो आप बोल लेना, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। हम आंकड़ों पर बोल रहे हैं। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में 170 से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं। आज डॉक्टर्ज की कमी की बात की जा रही है। आप अपने पिछले कार्यकाल की पूरी अवधि में देखें कि आपने कितने डॉक्टरों की नियुक्तियां की थी। हमारी सरकार बधाई की पात्र है जिसने 550 डॉक्टरों की नियुक्तियां की है। जिसमें 60 स्पैशेलिस्ट्स की नियुक्तियां की है। इसके अतिरिक्त 600 विभिन्न केटेगरी के पद भी भरे गये हैं और

श्री वर्मा द्वारा जारी

06/03/2017/1830/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल) - - जारी

571 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इन संस्थानों में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ हों, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में 7625 'आशा वर्करों' की भर्ती की है। 502 पैरामैडिकल के पद वर्तमान सरकार ने भरे हैं। ये इसीलिए भरे हैं, ताकि हमारे स्वास्थ्य संस्थान अच्छा काम करें। आज आपने शिक्षा की बात की थी और कहा था कि शिक्षकों का अभाव है। हमारी सरकार ने 10,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति कर ली है और अभी प्रक्रिया निरन्तर जारी है। अभी दो दिन पहले 207 टी0जी0टी0 टीचरों की नियुक्तियां हुई हैं और उसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। यदि आपको इसे नकारना ही है, तो आप बोलते रहिए। इसके अलावा आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए भी प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है, प्रदेश सरकार ने 9 एस0डी0एम0 कार्यालय विभिन्न स्थानों में खोले हैं। इसके साथ ही 12 तहसीलें और 29 सब-तहसीलें प्रदेश में खोली गई हैं। ये सारी कार्यरत हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तहसीलें और सब-तहसीलें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी खुली हैं। एक सब-तहसील 'नेरी' का दर्जा बढ़ाकर तहसील का किया गया है और एक नई सब-तहसील डहैर में खोली है। आपने 2007 के इलैक्शन में जनता के बीच घोषणा की थी कि यदि हम सत्ता में आये, तो हम डहैर में तहसील खोलेंगे। लेकिन 5 साल तहसील नहीं खोल सकें। आपकी सरकार तो जिले भी बनाती रही। जिलों के लिए डी0सी0 भी बैठा दिए गये थे, लेकिन न तो उनकी अधिसूचना जारी हुई और न ही वे जिले यर्थात् रूप में कामयाब हुए। हमारी सरकार ने ये काम प्रदेश में किए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ पहुंच रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार व्यावहारिक रूप से जो लोगों की जरूरतें हैं, उसके ऊपर काम कर रही है। आपकी सरकार के व़क्त कितने पटवारियों के पद खाली थे? आपके व़क्त में चार-चार पटवार सर्कलों में एक-एक पटवारी था। हमारी सरकार ने 778 पटवारी नियुक्त किए हैं और वे अपना काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1120 पटवारियों की ट्रेनिंग चल रही है और वे भी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अपनी सर्विसिज़ प्रदेश की जनता को देंगे। मैं प्रदेश की वर्तमान सरकार और यहां बैठे राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक और अच्छा व्यावहारिक फैसला जनता के हित में लिया है। पहले एक-एक कानूनगो सर्कल में 20-20 पटवार सर्कल आते थे, इन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और 154 नये फील्ड कानूनगो

06/03/2017/1830/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

वृत्त प्रदेश में खोले गये हैं। वे आज कार्यरत भी हो गये हैं। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र हैं। इन वृत्तों के न बनने से हजारों लोगों के आपसी बंटवारे के केसिज़ निलम्बित पड़े हुए थे, अब इन कानूनगो वृत्त बनने से लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। यहां पर विपक्ष द्वारा बात की गई की सड़कों के निर्माण कार्य नहीं हुए। वर्तमान सरकार ने इन चार वर्षों में 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण कार्य किया है और 180 पुल प्रदेश में बन कर तैयार हो गये हैं और

श्रीमती एन0एस0 - - द्वारा जारी।

06/03/2017/1835/ns/ag/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल) ------जारी।

इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि इन सड़कों के निर्माण से हमारे 500 से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़े हैं। शिक्षा , स्वास्थ्य और सड़क हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। यदि हमें प्रदेश का विकास करना है तो ये विकास इन तीनों बिन्दुओं के द्वारा होगा। हमारी सरकार इन तीनों बिन्दुओं के ऊपर काम कर रही है। सरकार इन उपलब्धियों के लिए बधाई की पात्र है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लोग कृषि और पशुधन के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी हमारी सरकार ने प्रदेश में 36 वैटरिनरी हॉस्पिटल खोले हैं। 48 वैटरिनरी डिस्पैंसरीज, 2 नये पॉलीक्लीनिक प्रेदश में खोले गये हैं। क्या इसका विकास के साथ संबंध नहीं है? यहां पर कहा गया कि सरकार ने पिछले चार सालों से कुछ नहीं किया है। कोई काम ही नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से ही प्रदेश का भला होना है। प्रदेश की जनता को इसका फायदा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके वक्त में कितने लोगों को पैन्शन लगी? आपने जो मापदंड और आय सीमा निर्धारित की थी वो 18,000 थी और उसमें 10,000 मनरेगा की इनकम आती थी। बहुत ज्यादा पात्र व्यक्ति उस सीमा के तहत नहीं आते थे। हमारी सरकार ने इस बात को देखते हुए बहुत अच्छा फैसला लिया था उन्होंने इस आय सीमा को बढ़ा कर 35,000 कर दिया था। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। प्रदेश में इस नीति के तहत 50,000 नये लोगों को पैन्शन

लगी है। (व्यवधान) आपके समय में तो यह भी नीति थी कि अगर कोई आदमी मरेगा तो नये व्यक्ति को पैन्शन लगेगी। लेकिन जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो यह फैसला बदला गया । उस वक्त एक ही वर्ष में जितने पैंडिंग केसिज़ थे उनको उस समय एकमुश्त पैन्शन लगाई गई थी। This is on the record of the House. यह उस समय की प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। हमने सामाजिक पैन्शन 450 रूपये से बढ़ा करके 650 रूपये की है और 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों की पैन्शन 1200 की है। मैडम आप इस सच्चाई को झूठला नहीं सकती हैं क्योंकि आपके समय में आय सीमा 18,000 थी इसकी वजह से

06/03/2017/1835/ns/ag/2

पात्र व्यक्तियों को पैन्शन नहीं लग रही थी। अभी यहां पर माननीय श्री महेश्वर सिंह जी ने बात की है। उन्होंने प्रदेश में भांग की बात की है। भांग से संबंधित जो प्रदेश में नशाखोरी और नशा तस्करी की समस्यायें हो रही हैं तो मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश में इन्होंने तीन नार्कोटिक सैल स्थापित किए हैं इससे निश्चित तौर पर नशाखोरी की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, तस्करी हो रही है उसमें लगाम लगेगी। हमारा प्रदेश एक आदर्श राज्य है, इसे देव भूमि के नाम से जाना जाता है। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो नशाखोरी की बीमारी फैली है वह हमारे प्रदेश में न फैले इसके लिए यह एक बहुत अहम कदम है। (घण्टी

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी।

06/03/2017/1840/RKS/AS/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री सोहन लाल)...जारी

जो राज्यपाल महोदय ने यहां अपना अभिभाषण दिया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पैंशन पर बड़ा प्रकाश डाला। क्या यह सत्य है कि छः महीने में न तो किसी को विधवा पैंशन मिली और न ही ऑल्ड ऐज पैंशन मिली है।

अध्यक्षः आदरणीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी क्लैरिफिकेशन मंत्री जी से ली जाती है।

06/03/2017/1840/RKS/AS/2

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आदरणीय जगजीवन पाल जी इस सदन में लाए हैं, जिसका समर्थन श्री संजय रतन जी ने किया है। मैं उस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण सरकार द्वारा लिखा गया है। इसमें राज्यपाल की सहमति या उनकी सोच बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इस अभिभाषण को केवल पढ़ा है। यह सरकार ने लिखा है और सरकार ने अपनी पीठ दबादब थपथपाई है। इससे ज्यादा इस अभिभाषण की कोई अहमियत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे दीवार पर अशोक चक्र लगा हुआ है और उसमें 'सत्यमेव जयते' लिखा है। मैं समझता हूं कि इससे हमें सच बोलने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि सच बोलना पक्ष के नसीब में नहीं है। घोषणा पत्र के पैरा तीन में लिखा है "सबका कल्याण, समग्र विकास।" बहुत अच्छा जुमला है। मैं इस पर एक ही बात करूंगा। सरकार के पास दो आंखें हैं, एक पक्ष को देखने के लिए और दूसरी विपक्ष को देखने के लिए। बदकिस्मती से जो विपक्ष को आंख देखती है वह काणी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस सरकार के पहले तीन वर्षों में नाबार्ड से प्रांत की सड़कों के लिए 886 करोड़ रुपये आए। यह पैसा कहां लगा? जहां-जहां से डी.पी.आर्ज. बनी वहां-वहां लगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन सालों में केवल एक ही डी.पी.आर बनी। कई चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक भी डी.पी.आर. नहीं बनी। लेकिन रोहडू में 8, शिमला ग्रामीण में 18 और जुब्बल-कोटखाई में 19 डी.पी.आर्ज. बनी। हमारी

इसलिए नहीं बनी क्योंकि एफ.सी.ए. बीच में आ गया और आपके एफ.सी.ए. बीच में नहीं आया। आपके वहां जंगल नहीं हैं और मेरे चुनाव क्षेत्र में ज्यादा जंगल हैं। आप कहते हैं कि भेदभाव नहीं होता, इससे बड़ा भेदभाव और क्या हो सकता है? आपको समग्र विकास की जगह लिखना चाहिए 'कुछ का कल्याण, कुछ का विकास।' यह जुमला आपके लिए बिल्कुल फिट होता है। शिक्षा क्षेत्र की बात हुई। राज्यपाल अभिभाषण में लिखा गया है "गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है।" What a joke. It is a big joke. By thinning out your resources, how can you have quality education?

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

06.03.2017/1845/SLS-AS-1

श्री इन्द्र सिंह ...जारी

यहां टीचर डैपुटेशन पर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है। सोहन लाल जी कह गए कि बहुत से संस्थान खोले गए हैं। संस्थान खोलना एक बात है, उनको चलाना दूसरी बात। आप संस्थान खोल रहे हैं, चला नहीं रहे हैं। आपके स्कूलों में एक-एक बच्चा है। एक बच्चे के लिए आपने 4 इंप्लाइज रखे हैं और उस बच्चे पर आप 80-80 हजार रुपया ख़र्च कर रहे हैं। आप मुझे यह बताएं कि जिस स्कूल में एक बच्चा है, वह किससे इंटरैक्ट करेगा। वह कबड्डी खेलना चाहता है। क्या वह मास्टर से कबड्डी खेलेगा। वह शरारत करना चाहता है, क्या वह पानी पिलाने वाली से शरारत करेगा। आपने तो उस बच्चे को 6 घंटे के लिए कैपिटिविटी में डाल दिया। Listen to me. उस बच्चे की कोई भी फैकल्टी डवलप नहीं होगी। वह दब्बू बनकर बाहर निकलेगा, इसके कोई शक नहीं है। You have over stressed the system and this is a complete failure of the system. शिक्षा विभाग की व्यवस्था का जितना ह्रास आपके 3-4 सालों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। यह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इसमें कोई दोराय नहीं है।

मैं धूमल साहब का धन्यवाद करता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में इन्होंने 90-90 लाख रुपये की 7 साईंस लैब खोलीं ताकि विद्यार्थियों को क्वैलिटी ऐजुकेशन मिले। आपके 4 सालों में एक भी लैब नहीं खुली। ये अगर भेदभाव नहीं है तो क्या है।

अभी यहां पर ठाकुर कौल सिंह जी नहीं है। मुझे अभी उनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। ठाकुर कौल सिंह जी, आपने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। मेरे सरकाघाट रैफरल हॉस्पिटल में 15 डॉक्टर होने चाहिए, जबकि वहां 6 डॉक्टर हैं। मैं बार-बार कहता हूं कि उस बैल्ट में कोई प्राईवेट हॉस्पिटल भी नहीं है जिसके ऊपर हमारी डिपैंडैंसी हो। We are totally dependent on Government hospital. उस हॉस्पिटल में न तो गाइनेकोलोजिस्ट है, न मैडिकल स्पैसलिस्ट है, न ईएनटी स्पैसलिस्ट है और न कोई ऐनेस्थिसिया देने वाला है। यह कैसा हॉस्पिटल है जबकि यह वहां एकमात्र हॉस्पिटल है। बीएमओ के अंडर 18

06.03.2017/1845/SLS-AS-2

डॉक्टर होने चाहिए जबकि 7 डॉक्टर हैं। फिर आप कहते हैं कि आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं। it's a total failure.

आपने अभिभाषण के पैरा-20 में फर्टिलिटी रेट के बारे में कहा है। आपने कहा कि देश का प्रजनन दर 2.3 है और आप प्रदेश की दर 1.7 तक ले आए हैं। You have done a commendable job. लेकिन सर, एक स्टडी के मुताबिक अगर फर्टिलिटी रेट 1.8 से कम हो तो वह कौम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहती। You have to think over it. और आप कोशिश कर रहे हैं इस रेट को एक पर लाने की। अगर इसे एक पर ले आए तो 20-25 सालों में हिमाचल प्रदेश में बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी और यंग लोग गिनती में मिलेंगे। You have to think over it. It is not a joke...(interruption)... Population control should also be within the limits. Don't bring it to that level.

आपने इंस्टिच्यूशनल डिलीवरी की बात की। अच्छी बात है। You have reached the mark of 85%, very good. You should have to reach hundred percent that

should be your aim. लेकिन यह कितनी सरकारी अस्पतालों में होती है और कितनी प्राईवेट में होती है, कितनी नेचुरल डिलीवरी होती हैं और कितनी सिजेरियन डिलीवरी होती हैं, यह बात आपने इसमें मैंशन नहीं की है। आपको हैरानी होगी, एक समाचार-पत्र के मुताबिक 31 परसैंट सिजेरियन डिलीवरी प्राईवेट हॉस्पिटल्ज में हो रही हैं जबकि यह 10-15 परसैंट के बीच में होनी चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी से जच्चा-बच्चा दोनों का बड़ा नुकसान होता है। आप कृपा करके इसको चैक कीजिए। इसका आपने रिफरैंस नहीं दिया है। आपको चाहिए कि आप हॉस्पिटल के बीच में एक बोर्ड लगाएं और उसमें मैंशन हो कि वहां कितनी सिजेरियन डिलीवरी होती हैं और कितनी नार्मल होती हैं। उसकी फिगर्ज वहां मंथवाईज लगनी चाहिए ताकि आप उसको चैक कर सकें। यह एक धंधा बन गया है। कोई डाक्टर रिस्क नहीं लेता और झट से सिजेरियन कर देता है। माननीय मंत्री जी, इस विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा। Sir, it is a very serious matter. प्रदेश में डायबिटी, कैंसर, टी.बी. आदि रोगों के पेशैंट्स लगातार बढ़ रहे हैं।

जारी .. श्री गर्ग जी

06/03/2017/1850/RG/DC/1
श्री इन्द्र सिंह----क्रमागत

You should have balance of preventive measures and curative measures taken. आप क्योरिटी पर जोर देते हैं और प्रिवेंशन का कोई हिसाब-किताब नहीं है। That balance you have to maintain if you want to have good health in Himachal Pradesh. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की बात करूं। किसानों की हालत तो बहुत खराब है। About 40% of farmers want to leave their profession इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कृषि में हर साल इन पुट कॉस्ट बढ़ रही है और ऑऊट पुट मिल नहीं रही। क्योंकि यहां जंगली जानवर एवं आवारा पशु घूम रहे हैं। सूअर, बंदर, नील गाय इत्यादि फसलों को खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त मौसम की बेरूखी, यह सब कुछ किसानों के लिए नुकसान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सौर ऊर्जा और बिजली की बाड़बंदी की बात कही जिसके बारे में आज सुबह ही प्रश्नकाल में बात हो रही थी। तो सरकार इसमें 60 % उपदान देने जा रही है और 40 % पैसा किसान अपने आप लगाएगा। लेकिन आपने जो बाड़बंदी करनी है उसमें नाईन स्टेन्डर्ड, सैवन या फाइव स्टैन्डर्ड की लगानी है या कितनी लगानी है और उसकी प्रति मीटर कितनी कॉस्ट है आपको पता ही नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी को पता ही नहीं है और उसकी प्रति मीटर कॉस्ट लाखों में जा रही है। मैंने उन कम्पनीज से पता किया, तो it is more than a lakh per meter, which is too exorbitant .कौन किसान उसको अफॉर्ड कर सकता है? कुलदीप कुमार जी कह गए कि इसका फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पेयजल की बात करना चाहूंगा। अगर प्रदेश में सबसे ज्यादा तकलीफ जो हो रही है, तो पीने-के-पानी की समस्या को लेकर हो रही है। अगर हमें दस फोन आते हैं, तो 90% फोन पानी से संबंधित होते हैं और पानी की कमी के कारण समाज में टेंशन पैदा हो रहा है। मेरे ख्याल में यह विभाग टोटली फेल हो गया है, यह विभाग टोटली असमर्थ, असहाय और बीमार है। मैं समझता हूं कि इस विभाग का कोई इलाज नहीं कर सकता। It is a system failure. इस विभाग की कोई पॉलिसी या प्लानिंग नहीं है, इस विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। पंपिंग मशीनरी की बार-बार रिपेयर होती है and the cost of pumping machineries repair is more than the original cost of pumping

06/03/2017/1850/RG/DC/2

machines. इसकी कोई मॉनीटरिंग नहीं हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आता कि यह विभाग काम कर रहा है या क्या कर रहा है? ग्राउन्ड स्टाफ इसके पास नहीं है, टॉप हैवी सिस्टम है। सिस्टम में कोई वर्क करना है, तो pyramidal system होना चाहिए। टॉप पर बॉस बैठा है और नीचे बेस में बहुत से वर्किंग हैण्ड्ज हैं। लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा है। वर्किंग हैण्ड्ज जीरो और ऊपर से टॉव हैवी। It is bad planning on the part of this Government. ऐसा मैं समझता हूं और ऊपर से फिर आप डिवीजन, सब-डिवीजन, सेक्शन इत्यादि फटाफट खोले जा रहे हैं और काम करने वाले आदमी आपके पास नहीं हैं। पानी छोड़ने वाला आदमी आपके पास नहीं हैं। जल रक्षक के लिए पंचायतें अधिशाषी अभियन्ता के पास प्रस्ताव भेजती हैं और अधिशाषी अभियन्ता उसको डम्प कर देता है

क्योंकि सरकार परमीशन ही नहीं देती। सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। उसके पश्चात आपने पीने-के-पानी की लगभग 600 स्कीम्ज ऑऊटसोर्स कर दी हैं और ऑऊटसोर्स भी ऐक्सीयन लेवल पर की हैं। Open to corruption और कितने सालों के लिए की हैं? एक या दो साल के लिए की हैं। जो पीने-के-पानी की स्कीम आपने एक साल के लिए ऑउटसोर्स की है, ठेकेदार तो पंपिंग मशीनरी का सत्यानाश करके भाग जाएगा। आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं क्योंकि there is no planning at all. It is adhocism जिस पर यह चल रहा है। आपने सिंचाई की 63 स्कीम्ज ऑऊटसोर्स कर दी हैं और वे भी 6-6 महीनों के लिए की हैं। आप किसी की जेब में जाकर ऐसे ही पैसे डाल दो, तो यह क्या है? सरकार को इस पर कोई नीति बनानी चाहिए ताकि पीने-के-पानी और सिंचाई के पानी पर सही ढंग से खर्चा किया जाए। ऐसा मेरा मानना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो. प्रेम कुमार धूमल साहब का धन्यवाद करता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में कण्डापतन से तीन उठाऊ पानी की स्कीम्ज मंजूर हुईं। काम शुरू हुआ। एक 40 करोड़ रुपये, दूसरी 29 करोड़ रुपये और तीसरी 15 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी स्कीम्ज थीं। उन पर काम शुरू हुआ। सरकार बदली। उन तीनों स्कीम्ज का 70% काम हो गया था। इस सरकार ने अपने चार सालों में इनका 15-20% काम भी पूरा नहीं किया, सारा काम बन्द कर दिया और सिस्टम ही स्लो कर दिया। जब मैंने रिपोर्ट मांगी, तो मुझे पहले कहा गया यह स्कीम अक्तूबर, 2014 में जनता को हैण्ड ओवर कर दी जाएंगी, लेकिन आज वर्ष 2017 चल रहा है। यह क्या तमाशा है? अभी कहते हैं कि मार्च, 2017 में यह जनता को हैण्ड ओवर कर दी जाएंगी।। hope, it is done that way.

06/03/2017/1850/RG/DC/3

कोई 22-23 करोड़ रुपये की एक स्कीम हमने डैहर से मांगी है। उस स्कीम का पैसा बहुत पहले आया हुआ था और अढ़ाई साल के बाद उस स्कीम का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम्ज हैं,

एम.एस. द्वारा जारी

06/03/2017/1855/MS/DC/1

श्री इन्द्र सिंह जारी--------

सब-की-सब बन्द पड़ी हैं। उन पर जो काम हुआ है वह काम वहीं रूक गया है जहां पिछली सरकार के समय में था। वे स्कीमें 90-90 लाख रुपये की हैं और एक-एक करोड़ रुपये की लिफ्ट इरीगेशन स्कीमें हैं लेकिन काम बन्द पड़ा है। मुझे एक चीज का डर है कि जो एक-एक लाख रुपये के टैंक बने हुए हैं और दो-दो साल उन टैंकों को बने हुए हो गए हैं जब उनमें पानी डालेंगे तो पता नहीं वे पानी सस्टेन करेंगे या पानी लीक हो जाएगा। इसका कोई पता नहीं है।

यहां स्वां नदी चेनेलाइजेशन के बारे में बड़ी-बड़ी बातें हुई कि सारा पैसा स्वां नदी चेनेलाइजेशन में जाना चाहिए। सीर खड्ड बीच में खड़ी-खड़ी ऐसे ही रह गई। हमारा तो आप लोगों ने कुंडा कर दिया। पिछले 15-20 साल से सीर खड्ड के चेनेलाइजेशन की बात चली हुई है और इस सरकार को तो मैं बार-बार बोल रहा हूं। हमने उसका शिलान्यास भी रख दिया। उसका ए0ए0 एण्ड ई0एस0 भी 62 करोड़ रुपये का मंजूर हो गया लेकिन टैक्निकल सैंक्शन इस सरकार ने चार साल में जान-बूझकर नहीं ली। यह सरकार डिले कर रही है और आप कहते हैं कि भेद-भाव नहीं होता है। आप टोटली भेदभाव कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास रि-मॉडलिंग के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। 15-20 साल में स्कीमें रि-मॉडल होनी चाहिए लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। फिल्टर लगाने की कोई पॉलिसी नहीं है। जितनी ग्रेविटी की स्कीमें हैं सब बिना फिल्टर के चल रही हैं। कितना स्वच्छ पानी आप लोगों दे रहे हैं? सड़कों की हालत बहुत खराब है और it is a case of corruption, growth and corruption cannot go together. इसमें कोई शक नहीं है you have to stop corruption. अगर ग्रोथ चाहिए तो आप करप्शन समाप्त कीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक ठेकेदार को आपने पूरे साल में उस डिवीजन में 89 ठेकों में से 34 ठेके दिए। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में मुख्य मंत्री जी को उस व्यक्ति का नाम भी बताया था लेकिन कोई ऐक्शन नहीं हुआ। 34 ठेके दिए और साल में वर्किंग सीजन कितना होता है? साल में केवल चार महीने का वर्किंग सीजन होता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने एक महीने में

06/03/2017/1855/MS/DC/2

6-7 ठेके किए होंगे। Can he do it? Has he got that much of labour and manpower? Has he got enough machinery? बिल्कुल नहीं। ये सारे-के-सारे ठेके कागजों पर हुए हैं और पेमैंट 100 प्रतिशत नगद मिली है। करप्शन कैसे रूकेगा? वह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष है और मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था कि मैं उसके खिलाफ ऐक्शन लूंगा लेकिन कोई ऐक्शन नहीं हुआ। उसने या तो ठेकों की स्पलिटिंग की है या सब-लेटिंग की है। बिल्कुल खराब काम हो रहा है। मैं सरकार को यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि जो आपके टारिंग के मानक हैं उनको इम्प्रूव कीजिए क्योंकि अभी रोड पर थम्पिंग बहुत ज्यादा होती है, वेट बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक डेन्सिटी भी बहुत ज्यादा है इसलिए आपके जो सदियों पुराने मानक हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा संख्याः 126 में लिखा है कि "भ्रष्टाचार के लिए जीरो टोलरेंस"। बहुत अच्छा। पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है लेकिन मैं आपका चिट्ठा बताता हूं। एन0ए0सी0 सरकाघाट में सारे एम्प्लाईज के अंगेस्ट एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, they were transferred. एफ0आई0आर0 दर्ज हुए तीन साल हो गए हैं लेकिन विजीलैंस चालान पेश नहीं कर रही है। आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस? 26 चोरी की गाड़ियां मण्डी जिला में पकड़ी गई, क्या हुआ और आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस? ठेकों की बात तो मैं छोड़ रहा हूं। एक सड़क जो केवल 14 किलोमीटर लम्बी है, वह अढ़ाई साल में, One minute, Sir.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट बैठिए। अभी 7.00 बजे का समय हो गया है और अभी कुछ अन्य भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिए अब इस मान्य सदन की बैठक एक घण्टे के लिए बढ़ाई जाती है।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष जी, जिन्होंने आज बोलना है उन्हें आज ही बोलने दीजिए। क्योंकि हमारा पहले भी एक दिन खराब हुआ है। अगर जल्दी हो जाता है तो ठीक है।

अध्यक्षः ठीक है। सभी वक्ता निर्धारित समय में रहकर अपना भाषण समाप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री इन्द्र सिंह श्री जे0एस0 द्वारा जारी----

06.03.2017/1900/जेके/एजी/1

श्री इन्द्र सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बलद्वाड़ा में एक सड़क की लम्बाई 14 किलोमीटर है और उस सड़क में ढाई सालों में 70 लाख 90 हजार 829 रूपये की रिपेयर का काम हुआ। आप उस सड़क को तो देखिए उसकी क्या हालत है। ? वह पैसा कहां गया? बार-बार बोलने के बावजूद भी क्यों आप इन्क्वायरी नहीं करवाते ? यह सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार को उत्साह देती है। बलद्वाड़ा स्कूल के केम्पस में एन्क्रोचमैंट हुई। वह भी सरकारी अधिकारी ने की। एन्क्रोचमैंट करने के उपरान्त उसको दण्डित किया जाना चाहिए लेकिन आपने उसको एक्सटैंक्शन दे दी। आप क्रप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आप जाने आपके भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? आखिर में बहुत से सदस्य यहां पर कह गए कि अच्छे दिन कब आएगें? अब मैं बताता हूं अच्छे दिन कब आएंगे? केन्द्र सरकार ने प्रदेश को 61 नेशनल हाई वेज़ दिए। 3 फोर लेन दिए, 6 ओवर हैड ब्रिज दिए। मिलेंगे if not today, tomorrow. आप नहीं ले सकते हम उनको लेंगे। ये क्या अच्छे दिन नहीं है? आपने एडमिट किया। आपके टाईम में केन्द्र से 70:30 की रेशो से पैसा मिलता था और अब 90:10 में पैसा मिलता है। क्या ये अच्छे दिन नहीं है? पहले केन्द्र के टैक्सिज का प्रदेश को 32 परसेंट मिलता था और अब 42 परसेंट मिलता है। क्या ये अच्छे दिन नहीं है? हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाईन के लिए पैसा दिया गया। ये क्या अच्छे दिन नहीं है? हिमाचल प्रदेश के लिए केन्द्र से एक एम्ज हॉस्पिटल मिला है। वह मिलेगा और हम लाएंगे। आप नहीं लाएंगे हम लाएंगे। तीन मेडिकल कॉलेज मिले। ये क्या अच्छे दिन नहीं है? आपको हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। ये क्या अच्छे दिन नहीं है? धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दिया क्या ये अच्छे दिन नहीं है? आपको कौन से अच्छे दिन चाहिए? 15 लाख रूपया आप लोगों की जेबों में मुफ्त में नहीं मिलेगा। You have to

work for it. माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में बिल्कुल असमर्थ हूं। धन्यवाद।

06.03.2017/1900/जेके/एजी/2

अध्यक्षः अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च, 2017 को महामहिम् राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश द्वारा विधान सभा में दिया गया अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव श्री जगजीवन पाल जी , माननीय मुख्य संसदीय सचिव जी ने प्रस्तुत किया तथा श्री संजय रतन, माननीय सदस्य जी ने उसका अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम् राज्यपाल महोदय द्वारा एक घंटे का अभिभाषण प्रदेश सरकार द्वारा चार वर्षों की उपलब्धियां अर्जित करना है, उस सम्बन्ध में मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी को जिनके

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

06.03.2017/1905/SS-AG/1

श्री किशोरी लाल क्रमागतः

जिनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में इन चार वर्षों में विकास के कई काम हुए। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूल अपग्रेड हुए। जिनमें से बैजनाथ विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 5 मिडल स्कूल हाई स्कूल हुए। चार जो हाई स्कूल थे वे +2 हुए। लेकिन जो चार वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गवर्नमैंट मिडल स्कूल, गुनेट कांग्रेस के शासनकाल में अपग्रेड हुआ लेकिन ज्यों ही सरकार बदली, बी0जे0पी0 की सरकार सत्तासीन हुई तो उस स्कूल को फिर मिडल स्कूल कर दिया गया। हाल ही में जब चार वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई तो उस स्कूल को दोबारा हाई स्कूल

किया गया। यह उस सरकार के समय की बात है। उस समय को आप लोग क्यों भूल जाते हो? आप लोग तो शिक्षा के विरोधी हैं। विरोध में बातें करते हैं। प्रदेश सरकार ने और कांग्रेस सरकारों ने शिक्षा का महत्व समझा, तब हम जैसे गरीब लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। कहां थी पहले पढ़ाई? कहां थी शिक्षा? उस वक्त को याद करिये, लोग दर-दर की ठोकरें खाते थे। उस वक्त को याद करिये जब शिक्षा नहीं थी। कांग्रेस सरकार की नीतियों की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में इज़ाफा हुआ। इसे झुठलाया नहीं जा सकता।

Speaker: Members are requested not to interrupt. प्लीज़ इंट्रप्ट न कीजिये।

श्री किशोरी लालः मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। ठीक बोल रहा हूं। तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं। आज़ादी से पहले शिक्षा कहां थी। मैं बैजनाथ की बात करना चाहता हूं। उस वक्त एक प्राईमरी स्कूल था। उसके अलावा कोई स्कूल नहीं था। --(व्यवधान)--जब आपका समय आयेगा तब आपने बोलना। बैजनाथ में आज जो कुछ हुआ है कांग्रेस सरकार की वजह से हुआ है। बैजनाथ का 1962 का कॉलेज जो प्राइवेट था कांग्रेस सरकार ने उसे सरकारी किया। आज वहां आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से एम0ए0 की क्लासिज़ शुरू हुईं और उस महाविद्यालय में 2500 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या वह उपलब्धि नहीं है? शिक्षा का विरोध

06.03.2017/1905/SS-AG/2

करना कि संस्थाएं खुल गईं, अरे कई ऐसे स्कूल थे जहां पर हमारी बेटियां जंगल का रास्ता पार करके नहीं जाती थीं और शिक्षा से वंचित रह जाती थीं। पिछले सैशन में एम0ए0 इंग्लिश की कक्षाएं कॉलेज में शुरू हुईं और वहां गरीब लोगों की बेटियों ने एम0ए0 इंग्लिश की। क्या आप उसका विरोध करते हैं? अच्छी बात का विरोध करना विपक्ष की आदत है। आप अच्छा नहीं देख सकते क्योंकि आपके ज़हन में अच्छा नहीं है। बार-बार विरोध करना और कहना कि कुछ नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं हुआ? जो हुआ उसकी तो अच्छाई करिये और जो बुरा हुआ उसकी बुराई करिये। बैजनाथ कॉलेज में पूरा स्टाफ है। पूरे लैक्चरार

और प्रिंसीपल हैं। --(व्यवधान)-- आप अपना रोना रोओ, हमने तो अपना विकास दिखाना है। बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में जितनी भी सड़कें बनी हैं, पहले भी वहां हमारे पड़ोस के मुख्य मंत्री रहे, श्री शांता कुमार जी दो बार मुख्य मंत्री रहे और धूमल साहब दो बार मुख्य मंत्री रहे लेकिन बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में एक इंच सड़क नहीं बढ़ी। आज बिलिंग विश्व में प्रसिद्ध है। 25 करोड़ रुपया अभी सैंक्शन हुआ, वह किसकी बदौलत है। वह राजा वीरभद्र सिंह जी की बदौलत है। अगर यहां से स्कीमें गईं तब ही मंजूर हुईं। अब हमारे वहां बी0जे0पी0 के लीडर क्या कहते हैं? प्रधान मंत्री सड़क योजना। अरे भाई आप तो रोना रो रहे हैं, आपकी प्रधान मंत्री सड़क योजना क्यों मंजूर नहीं होती? हमारे क्यों हो रही है? इस बात को ज़रा सोचिये। जो प्रयत्न करता है, वहीं मंजूर होनी है। जो बच्चा रोता है, मां उसे दूध पिलायेगी।

(श्रीमती आशा कुमारी, सभापति महोदया पदासीन हुईं।)

तीन साल पहले केन्द्र में झूठ के सहारे बी0जे0पी0 की सरकार बनी। मोदी साहब लोगों को क्या कहते रहे कि हम विदेश से काला धन लायेंगे और उसका समर्थन बाबा रामदेव जी करते थे। विदेशों से काला धन आयेगा और 15-15 लाख आपके खाते में आ जायेगा। अरे भाई, कहां गया 15 लाख? लोगों को क्या कहते थे, सुनिये ज़रा, बहुत हुआ नौकरियों का इंतजाम, अब की बार मोदी सरकार।

सभापतिः माननीय सदस्य, एक मिनट इनको बोल लेने दीजिये।

06.03.2017/1905/SS-AG/3

श्री किशोरी लालः क्या कहते थे, महंगाई को कम करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो आटा बंद हो गया। आटे का रोना मोदी से रोईये।

जारी श्रीमती के0एस0

06.03.2017/1910/केएस/एएस/1

श्री किशोरी लाल जारी---

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि कहां गया वह 15-15 लाख रुपया? कहां गया हर घर का नलका? हर हाथ को काम कहां है? झूठे वायदे करने वाले मोदी से पूछो कि सस्ते राशन की दुकान कहां गई? आटा बन्द कर दिया, सिलैण्डर 100 रुपये बढ़ गया। मंहगाई का रोना रोते हैं कि हमने यह बढ़ाई। अरे, भाइयो अपना वक्त भूल गए? हमने वह आपकी सरकारें भी देखी है।

सभापति महोदया, पैंशन की बात की। साढ़े चार सौ से साढ़े छः सौ रुपये पैंशन हुई । 1200 रुपये पैंशन 80 साल से ऊपर की आयु वालों की हुई। आपकी सरकार के समय में पैंशन होल्डर जो अप्लाई करता था, अगर कोई पैंशन लेने वाला मर जाता था, तब पैंशन मिलती थी। उस वक्त को याद करिए। हिमाचल प्रदेश में टैंडैंसी एक्ट कांग्रेस पार्टी ने लागू किया। उसके विरोध में बैजनाथ में चौधरी हरदयाल की गाड़ी जला दी गई। वह किसने जलाई, याद करो। 1990 में ओ0बी0सी0 के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना था लेकिन उसका विरोध किसने किया? यहां की बी0जे0पी0 की सरकार ने किया। उस वक्त कहां था लॉ एण्ड ऑर्डर? अपने ही एम0एल0ए0 और मंत्री गाड़ियां रोकते थे। लोगों को परेशानियां हुई। आप क्या बात करते हैं? कहां था उस वक्त का लॉ एण्ड ऑर्डर? आज कानून व्यवस्था के बारे में कहते हैं? आज कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो चार सालों में काम किए हैं वह एक रिकॉर्ड है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में हिमाचल विकास की ओर बढ़ा है। आप लोगों ने विरोध किया कहा कि वकामुल्ला कौन है? कौन निकला? क्या रिश्तेदारी थी उससे आपकी? आप मुझे बताओ। आप चार साल रोना रोते रहे। क्या निकला? खोदा पहाड़, निकली चूहिया। वाह मेरे मित्रो, आप कहते हैं अच्छे दिन? अरे, जाएगी केन्द्र की सरकार बहुत जल्दी

जाएगी। जो वायदे किए वे तो पूरे नहीं हुए। प्रदेश सरकार ने काम किया है और वह दोबारा रिपीट होगी। आदरणीय मुख्य मंत्री जी सातवीं बार फिर से मुख्य मंत्री बनेंगें, यह मैं दावे से कह सकता हूं। आप अपने समय को भूल

06.03.2017/1910/केएस/एएस/1

जाते हैं। यहां किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, उस समय किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अपनी बारी में भूल जाते हो। उस सरकार को याद करिए। पिछली बार जब आपकी सरकार थी तो पांच सालों में बैजनाथ में कोई भी काम नहीं हुआ। सड़कें उखड़ गई तो दुकानदार क्या करते थ, उन पर पत्थर रखते थे ताकि उनकी दुकानों में छींटे न पड़ जाए लेकिन अब सभी कुछ ठीक है तो इनको तकलीफ हो रही है। अब इनको क्या तकलीफ हो रही है कि राजधानी धर्मशाला में क्यों बन गई? अरे, शिमला वालों क्यों विरोध करते हो? आपके हाथों में तो लड्डू है और अब हमें भी खाने दो। क्यों इसका विरोध करते हो? खुशी जाहिर करो कि प्रदेश सरकार ने दूसरी राजधानी बना दी और कांगड़ा वालों आप तो खुश हो जाओ। आप भी विरोध करते हैं कि राजधानी नहीं बननी चाहिए? आप किस बात से खुश हैं? विरोध ही आपका एक मात्र काम है क्योंकि आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है। विरोध करिए जितना करना है लेकिन जो विकास के आयाम यहां स्थापित हुए हैं, रिकॉर्ड विकास हुआ है।

सभापति महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं। हमारा चुनाव क्षेत्र हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। शिक्षा, सड़कों, पीने के पानी के क्षेत्र में यानि हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। 400 हैंड पम्प बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में लगे हैं । रवि जी, आपके समय में कूहलों की डी0पी0आर0 बनी, बड़े-बड़े चक्के लगे लेकिन किसान के खेत में पानी की बूंद नहीं पहुंची। अब मैंने कूहलें चालू की है। आपने अपने समय में बड़े-बड़े चक्के लगा दिए। उनसे अगर ईंटों को उखाड़ते तो किसी गरीब का घर बन जाना था लेकिन आपने तो वहां चक्के लगाए पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची और आपके ठेकेदार वहां काम करते रहे। किसी ने पूरा काम नहीं किया। सारा पैसा उनकी जेब में गया। पूरे हिमाचल में विकास हो रहा है। आपके आदत है विरोध करना, करिए लेकिन जो विकास बैजनाथ विधान सभा में हुआ है, उसका श्रेय आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है। मैं इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं अधिक न कहता हुआ इस चर्चा का समर्थन करता हूं । धन्यवाद । जय हिन्द, जय हिमाचल। जय बाबा बैजनाथ।

श्री बिन्दल जी अ0व0 की बारी में--

6.3.2017/1915/av/as/1

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी) : बिन्दल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?

डॉ.राजीव बिन्दल : आदरणीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अभी यहां पर स्वामी रामदेव जी का नाम लेकर चर्चा की है। स्वामी रामदेव जी ने हिमाचल में एक बेहतरीन संस्थान खड़ा किया था। सरकार ने उसको चार साल तक ताला लगा करके तथा वहां पर दो सौ पुलिस वाले बैठा करके रखे। चार साल के बाद सरकार को यह बात समझ में आ गई कि वह एक अच्छे आदमी है और अब दोबारा से उनको लीज़ अलॉट की जा सकती है। यानि सरकार को चार साल के बाद होश आई है जबकि उस संस्थान से किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता था। उसको आज किशोरी लाल जी जस्टिफाई कर रहे थे। यदि उसको चार साल पहले ही कर देते, उसको बंद क्यों किया? केवल इतना ध्यान दिलाने के लिए मैंने अपनी यह बात कही है।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी) : माननीय सदस्य, हो सकता है कि स्वामी रामदेव जी का हृदय परिवर्तन अब हुआ हो।

6.3.2017/1915/av/as/2

श्री गोविन्द राम शर्मा : आदरणीय सभापति महोदया, मैं यहां पर 1 मार्च, 2017 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले यहां पर कई वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे हैं।

सभापति जी, सरकार द्वारा आदरणीय राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़वाया गया वह कुछ भी नहीं है बल्कि सारा-का-सारा झूठ का पुलिन्दा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपने जब चुनाव लड़ना था तो उस समय आपने मेनिफैस्टो बनाया था। उस मेनिफैस्टो में बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा था। आपने युवा वर्ग को ठगने का प्रयास किया और उसमें आपने कहा था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आयेगी तो हम प्रत्येक युवा को 1000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे। सवा चार साल का समय बीत गया और आपने प्रदेश के युवा वर्ग को ठगा। अब जब चुनाव नज़दीक आने पर प्रैशर पड़ने लगा तो आप उसमें कुछ परिवर्तन करने का भी प्रयास कर रहे होंगे। आपका यह आज का ही नहीं बल्कि इससे पहले वर्ष 2003 में जब आप सत्ता में आये थे तब भी आपने यही कहा था कि प्रत्येक घर से एक बच्चे को नौकरी देंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने चोर दरवाजे से पी0टी0ए0 की भर्ती की जिनको आज तक नियमित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी जब दिल्ली से परवाणू आए थे और आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कर्मचारियों को 4-9-14 दिया था तो वह वर्ष 2009 से दिया था। वीरभद्र सिंह जी ने परवाणू पहुंचते ही कहा कि मैं यह वर्ष 2006 से दूंगा। मगर देने की बजाय जो धूमल जी ने दिया था उसको भी कर्मचारियों से स्नैच किया गया। आपकी सरकार का यह हाल है। आपने आशा वर्कर आज से दो-तीन साल पहले रखी, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। उनको रखने के बाद कैबिनेट में डिसिजन हुआ कि उनको 800 से 850 रुपये तक सैलरी देंगे। मगर अभी तक भी उन आशा वर्कर को

6.3.2017/1915/av/as/3

सैलरी नहीं दी जा रही है। अभी-अभी यहां पर एम्ज़ की बात हो रही थी। मगर आपकी सरकार ने जो एम्ज़ के लिए जमीन उपलब्ध करवानी थी वह अभी तक नहीं हो पाई है। (---व्यवधान---) बिल्कुल नहीं हुई है। आप (श्री बम्बर ठाकुर) स्वास्थ्य मंत्री जी से अभी पूछ लीजिए। ठाकुर जी यहीं पर बैठे हुए हैं आप, इनसे पूछिए।

श्री वर्मा द्वारा जारी

06/03/2017/1920/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
श्री गोविन्द राम शर्मा- - - जारी

भारत सरकार ने क्या -क्या दिया है, ये अभी-अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने गिनाया है। लेकिन आपकी सरकार नंगी सरकार है। आज प्रदेश के अन्दर जो विकास हो रहा है, वह केवल केन्द्र से जो पैसा आ रहा है, उसके माध्यम से हो रहा है। एम्ज़ के रूप में आदरणीय नड्डा जी ने जो तोफ़ाह हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए दिया है, उसके लिए जो ज़मीन आपने ट्रांसफर करनी थी, वह अभी तक नहीं हो पाई है। -(व्यवधान)- आप उसकी चिन्ता न करो। आप अपना परिवार संभालो। मुख्य मंत्री क्या बोल रहे हैं और आपके पार्टी अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, आप उसकी चिन्ता करो? भाजपा क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, वह सब आपके सामने आएगा। लेकिन यदि आप एम्ज़ के लिए जल्दी-से-जल्दी जगह ट्रांसफर करेंगे तो उससे प्रदेश के लोगों को सुविधा मिलेगी। बिलासपुर और अर्की वालों को तो इस अस्पताल (एम्ज़) के बनने से बहुत सुविधा मिलेगी। आपको (श्री बम्बर ठाकुर) तो इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन आप प्रदेश के हित में कार्य नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, आदरणीय बिंदल जी ने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग के लिए अरबों रूपये केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिए है, लेकिन आप उसको लगा नहीं पाये। आपने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि आपको लगा कि उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। अभी यहां पर एन0एच0 के बारे में चर्चा हुई। आज तक 61 एन0एच0 किसी केन्द्र सरकार ने प्रदेश को नहीं दिये हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार (केन्द्र) ने दिए है, लेकिन आपकी सरकार उसकी डी0पी0आर0 ही नहीं बना रही है। केन्द्र सरकार ने 262 करोड़ रूपया दिया है। आप डी0पी0आर0 बनाओ और पैसा केन्द्र सरकार देगी, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर जितने भी काम लगे हैं, एक भी काम प्रदेश सरकार के पैसों से नहीं चल रहा है। जो सड़कें चौड़ी हो रही है, शालाघाट से चण्डीगढ़ के लिए जो रोड़ बन रहा है या अर्की से भराड़ी के लिए जो सड़क चौड़ी की जा रही है, वह सारे-का -सारा पैसा केन्द्र सरकार का है। दूसरे, जो काम चले हुए हैं, वह "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत चले हुए हैं। मैंने नाबार्ड की 12-13 स्कीमों की डी0पी0आरज0 बनाई थी। उनमें से

9 डी0पी0आरज मैंने बड़ी मुश्किल से यहां से भिजवाई। लेकिन कांग्रेस के जहां-जहां से विधायक हैं, उनकी डी0पी0आरज आपने 2012 से 2016 तक नाबार्ड को भेजी हैं, लेकिन मैंने अपनी डी0पी0आरज0 अप्रैल के बाद बड़ी मुश्किल से नाबार्ड को

06/03/2017/1920/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

भिजवाई है। आप जानबूझकर पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि विकास सबका होना चाहिए, जहां से बी0जे0पी0 के विधायक जीतें हैं, विकास वहां भी हो और जहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं, विकास वहां पर भी होना चाहिए। लेकिन आप शिलान्यास और उद्घाटन करने का शोक रखते हैं और वह भी उन कामों/सड़कों/भवनों का जो बी0जे0पी0 के टाईम में हुए हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी कुनिहार में आये थे, उन्होंने 2 पी0एच0सीज0 की घोषणा वहां पर की है, लेकिन मुख्य मंत्री जी आपने घोषणा की है, उसके लिए आपका धन्यवाद। परन्तु इनके लिए डाक्टर कहां से लाएंगे? अभी जो सिविल हॉस्पिटल /सी0एच0सीज0 हैं, उनमें भी डाक्टर नहीं है और अब जो नई सी0एच0सीज0 खोली हैं, उनके लिए डाक्टर कहां से आएंगे?

श्रीमती एन0ए0 - - -द्वारा जारी।

06/03/2017/1925/ns/dc/1

श्री गोविन्द राम शर्मा------जारी।

जब वहां पर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो यह हॉस्पिटल खोलने की क्या आवश्यकता है? अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि आपने बहुत से स्कूल खोल दिए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्कूल खोलने से पहले वहां पर टीचर की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो पुराने स्कूल हैं पहले उनमें टीचर्ज़ की भर्ती होनी चाहिए उसके बाद नए स्कूल खोलें तो हम उसका स्वागत करेंगे। आज स्थिति यह है कि जहां 15 टीचर्ज़ की आवश्यकता

है वहां पर पांच टीचर्ज़ भी नहीं हैं। इन्टीरियर में तो कहीं-कहीं पर दो-दो टीचर्ज़ के सहारे हाई स्कूल चल रहे हैं। इस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। यह कोई आलोचना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जितना पैसा मोदी सरकार ने दिया उतना पैसा कभी नहीं आया । यह स्कीम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी और उसका लाभ आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? अभी लगभग इसी वर्ष 1955.29 करोड़ रूपये की धनराशि केन्द्र से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पैसा आया है। मैं केवल इसी वर्ष की बात कर रहा हूं। फिर आपने क्या किया? स्टेट की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। हमारे नालागढ़ से जो सड़क अर्की के लिए आती है उसकी भी यही स्थिति है। यहां पर नालागढ़ के माननीय विधायक बैठै हैं और जब यह रामशहर से अर्की के लिए आते होंगे तो लगभग दो घंटें लगते होंगे। जब मैं रामशहर से अर्की के लिए आता हूं तो हालत खराब हो जाती है। मैंने बार-बार बोला और प्लानिंग की मीटिंग में भी बोला लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मित्रों बस छः महीने की बात है। फिर आप इस तरफ और हम उस तरफ होंगे। अगर आप काम करते तो आप वहां ही रहते लेकिन आपने कोई काम नहीं किया इसलिए दिक्कत आपको आएगी। अभी केन्द्र सरकार ने फिर कहा है कि 15 मार्च तक जितनी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितनी भी

06/03/2017/1925/ns/dc/2

डी0पी0आर्ज़0 दे सकते हैं उनको भेज दें और उनको सही भेजें और आपको वहां से अप्रूवल आएगी। आज तक आपको कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है या ऐसी कोई सरकार मिली है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह योजना देकर पूरे देश के लिए लाभ दिया और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए (घण्टी) प्रधानमंत्री मोदी जी ने 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' लागू की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहां से भी बहुत सी डी0पी0आर्ज़ बनी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र और माननीय श्री राम कुमार जी की एक 28 करोड़ रूपये की डी0पी0आर0 बनी है। लेकिन वह डी0पी0आर0 इस तरीके से बनी कि मेरे क्षेत्र से कम एरिया लिया गया और दूसरे क्षेत्र से ज्यादा एरिया लिया गया। उसमें पक्षपात यह किया

गया कि जो सानन पंचायत, डुमैहर पंचायत और खरड़ पंचायत जो कि नीचे की पंचायतें हैं उनकी डी0पी0आर्ज0 बनायी ही नहीं गई हैं और जो टोप की पंचायतें हैं उनकी डी0पी0आर्ज़0 बनाई गई हैं। इसमें आपकी मंशा ठीक नहीं रही है। इस प्रकार की आपने कोई-न-कोई गड़बड़ की है। वर्तमान सरकार ने मेरे साथ भेदभाव किया है। सभापति महोदय, थोड़ी सी बात मैं ओर करना चाहूंगा। आपके कुछ तथाकथित नेता कर्मचारी और मज़दूर हितैषी नाटक करते रहते हैं। आप छोटे-छोटे कर्मचारियों को विकटीमाईज़ कर रहे हैं। हॉल्टिकल्चर के विनोद ठाकुर जो परिसंघ के प्रेजीडैंट हैं उनको आपने एक बार नहीं बल्कि तीन-चार बार विकटीमाईज़ कर दिया। उनका कसूर क्या था कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार का मुद्दा

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी।

06/03/2017/1930/RKS/AG/1

श्री गोविन्द राम शर्मा.....जारी

उठाया, यदि उसमें 12 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई है तो उस कर्मचारी को आपने सुपरिन्टेंडेंट ग्रेड-2 प्रमोट किया और उसे डायरेक्टरेट में लगाया गया। उसके दूसरे दिन आपने उस कर्मचारी की ट्रांसफर नाहन को कर दी। फिर उसको दिल्ली से रिलीव किया जा रहा है, उसमें लिखा गया है कैम्प एट दिल्ली, जिसके दस्तावेज़ मेरे पास यहां पर पड़े हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी को ट्रांसफर कर सोलन लगा दिया गया। उनकी दो पुत्रियां हैं, जो यहां पर पढ़ रही हैं। जो होनहार कर्मचारी काम के लिए सबसे टॉप में रहते हैं, जो कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं उनको इस तरह विक्टिमाइज़ करना क्या ठीक है? शायद आपको लग रहा होगा कि वे बी.जे.पी. के सुपपोर्टर हैं। एक नहीं अनेकों कर्मचारियों को आपने विक्टिमाइज़ किया है। कर्मचारियों के साथ पक्षपात करना, क्या यह शोभा देता है? वाटर कैरियर का सेमिनार हुआ तो उसमें एक कर्मचारी नेता ने भाषण दिया कि ये डी. कम्पनी के लोग हैं। क्या मतलब है डी0 कम्पनी? मुख्य मंत्री जी उनको सुन रहे थे। क्या मुख्य मंत्री जी को दूसरों की आलोचना करवाने के लिए इस प्रकार के प्यादे आगे खड़े करने चाहिए? क्या हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? हमने कभी भी

व्यक्तिग किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर विकास की चिन्ता करें। केन्द्र सरकार ने जो प्रदेश के हित में काम किए हैं उसका भी आपको धन्यवाद करना चाहिए। उसका विरोध नहीं करना चाहिए। आप महंगाई की बात कर रहे थे। पहले जो दालों के भाव होते थे उसके बारे में आपको पता है। इस केन्द्र सरकार ने तो सस्ती दालें उपलब्ध करवाई है। पहले सिलेंडर 1300-1400 रुपये का मिलता था। आप विधवा पैंशन, अपंग और बुजुर्गों की पैंशन की बात कर रहे थे। यह पैंशन किसने लगवाई। यह पैंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगवाई थी। कर्मचारियों को भी आज तक जितने स्केल दिए गए वे भी हमारी सरकार ने ही दिये। पहले आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने और बाद में प्रोफैसर धूमल जी ने दिए। आपको स्केल देने का मौका भी नहीं मिला। आपने लोगों को ठगा और ठगने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। मेरा आपसे निवेदन है कि जो अच्छे काम करे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, परन्तु आप प्रशंसा नहीं करते हैं, केवल आलोचना करते हैं। आप में प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

06/03/2017/1930/RKS/AG/2

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय संजय रतन जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हूं और इसका समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, जिसकी आलोचना करने के लिए विपक्ष यहां पर खड़ा हुआ, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र को लें तो बच्चों को 2-2 जोड़ियां वर्दियों की स्कूल तक पहुंचने के लिए फ्री यात्रा

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

06.03.2017/1935/SLS-AG-1

श्री बम्बर ठाकुर...जारी

यह माननीय मुख्य मंत्री ने हमें दी जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 17 नए डिग्री कॉलेज दिए जिनका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ सोहन लाल जी के क्षेत्र में डैहर में नया डिग्री कॉलेज दिया गया जिसमें 7 प्लस टू स्कूल मेरे हैं जिनको उसका लाभ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। यह दुःख का विषय है। कर्नल साहब के एरिया में सुपर हाईवे मिला, अगर आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो मैं आपका धन्यवादी हूं कि आप उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...आप कह रह थे कि सड़कों की हालत खराब है। सड़कों की हालत खराब है लेकिन घुमारवीं से लेकर सरकाघाट तक की सड़क का नक्शा बदल गया है। हम माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करते हैं और अगर आप भी उसके लिए धन्यवाद करते हैं तो मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री वीरभद्र सिंह जी ने 3-3 मैडिकल कॉलेज दिए। चम्बा में, हमीरपुर में और नाहन में मैडिकल कॉलेज दिए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि नाहन में यह नहीं मिला। आपको मैडिकल कॉलेज भी दिया, उसके साथ पैसे भी दिए। धूमल साहब के एरिया में मैडिकल कॉलेज दिया, उसके लिए पैसे भी मिले। आप उसका धन्यवाद नहीं कर रहे हैं बल्कि विरोध कर रहे हैं। यह दुःख का विषय है। मण्डी के अंदर नेरचौक में ESI Hospital को केंद्र सरकार को चलाना चाहिए था, उन्होंने वैसा नहीं किया। फिर आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का धन्यवाद करो। बाकी प्रदेशों में केंद्र सरकार ने ESI Hospital का अधिग्रहण किया, उनको चलाया। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव किया क्योंकि उन्होंने इस कॉलेज का अधिग्रहण नहीं किया। मैं वीरभद्र सिंह जी का और ठाकुर कौल सिंह जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने ESI Medical College का अधिग्रहण भी किया और 732 युवाओं को वहां पर नौकरी देने का इंतजाम भी किया। आप उसका विरोध कर रहे हैं? आप किसी मुद्दे के ऊपर विरोध करिए। 732 नौजवानों को हम नेरचौक में रोज़गार दे रहे हैं,

आप उसका विरोध करें, यह बात समझ में नहीं आती।

प्रदेश के अंदर 108 और 102 ऐंबुलैंस योजना चालू की गई। आज घर-घर में ऐंबुलैंस पहुंचाने का इंतजाम हुआ है। एक फोन के ऊपर ऐंबुलैंस आती है, फिर भी आपको यह विकास नज़र नहीं आता। आपको अपना चश्मा बदलने की आवश्यकता है। चश्मा बदलें और जाकर लोगों से पूछें। जो 108 और 102 ऐंबुलैंस प्रदेश के मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री महोदय की कृपा से उन्हें मिल रही है, उसके बारे में गांवों में जाकर लोगों से पूछिए, तब मालूम पड़ेगा। आप शिमला में बैठकर आराम करते हैं, गांवों में तो जाते नहीं है। आपको क्या मालूम कि गांवों के अंदर सड़कों की हालत बदल गई है, डिसपैंसरीज की हालत बदल गई है और स्कूलों की भी हालत बदल गई है। हर स्कूल की बिल्डिंग के लिए पैसा आ गया।

आप अध्यापकों की बात कर रहे हैं। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। पहले आप कहते थे कि मुख्य मंत्री महोदय, आप स्कूल दे रहे हैं लेकिन अध्यापक नहीं हैं। अब आपकी परेशानी वाज़िब है क्योंकि हर रोज़ हमीरपुर में सुबोर्डिनेट सर्विसिज कमीशन में इंटरव्यु हो रहे हैं और भर्तियां हो रही हैं। सैंकड़ों के हिसाब से टीजीटी और जेबीटी भर्ती किए गए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में आज कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर अध्यापक नहीं है। इसलिए आपकी परेशानी वाज़िब है। आपको डर सता रहा है कि 5-6 महीनों के बाद चुनाव होंगे और उसके बाद आपका आंकड़ा यहां से घटकर 6-7 पर आ जाएगा। आपका आंकड़ा ऐसा आने वाला है। इसलिए आपकी परेशानी और विरोध वाज़िब है कि आप स्कूलों का विरोध करें, कॉलेजों का विरोध करें। फिर वीरभद्र सिंह जी नौकरियां देंगे तो आप कैसे आएंगे। इसलिए ही आप विरोध कर रहे हैं। हम आपकी चिंता जानते हैं। लेकिन वीरभद्र सिंह जी के होते हुए आपको सत्ता में बैठने का सपना नहीं लेना चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने लेते रहो, वह ठीक है। बाकी आप यहां पर नहीं आ सकते।

जारी .. श्री गर्ग जी

06/03/2017/1940/RG/AS/1

श्री बम्बर ठाकुर----क्रमागत

विरोध केवल मात्र उन बातों का करना चाहिए अगर फील्ड में किसी बात की कमी हो। लेकिन ये काम का विरोध करते हैं। जो काम यहां हो रहे हैं, जो नौकरियां यहां मिल रही हैं, जो सड़कों की हालत सुधर रही है, जो अस्पतालों को पैसा मिल रहा है, नए अस्पताल खुल रहे हैं, नए डॉक्टर्ज एवं नर्सिज लग रही हैं। ये उसका विरोध कर रहे हैं। 400 नर्सें अभी तक हमारे अस्पतालों में लग चुकी हैं। अब उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए आपकी चिन्ता वाज़िब है।

सभापति महोदया, यहां पर कोई वक्ता कर रहे थे कि माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने चण्डीगढ़ में मरीजों की सहायता हेतु ओ.एस.डी. बैठाए हैं। हमारे बिलासपुर में कंद्रोर में एक आशा कुमारी नाम की महिला है। अपने आंगनबाड़ी के बच्चे को स्कूल से लाने के लिए जा रही थी। पीछे से कोई गाड़ी आई, उसने उसको टक्कर मारी और वह महिला नीचे गिर गई। उसकी टांग के तीन टुकड़े हो गए। चार दिन के प्रवास पर माननीय मंत्री महोदय वहां आए थे। आपकी ही पार्टी के मण्डल अध्यक्ष को लेकर एक डेलीगेशन गया। तो उस आशा कुमारी के इलाज के लिए इन्कार कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां ओ.एस.डी. किसलिए बैठाया हुआ है? हम श्री वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अढ़ाई लाख रुपये उसके इलाज के लिए दिया। आज वह हमारी बहन ठीक होकर वहां पर आई। तो केवल मात्र चमचों के लिए वहां ओ.एस.डी. रखा है। चमचों के घर से यदि कोई बीमार होता है, तो उसका इलाज करने के लिए रखा है। अच्छा होता कि वे पूरे प्रदेश के लोगों की वहां सहायता करते। प्रदेश का गरीब व्यक्ति वहां जाए, तो उसका इलाज हो। इसलिए आपने वहां ओ.एस.डी. बैठाए हैं और यह भेदभाव होता है। क्योंकि वह गरीब है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, उसकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं था इसलिए आप उन नेताओं से कहें।

सभापति महोदया, मैं ट्रॉमा सेन्टर की बात कर रहा हूं। बिलासपुर के जब वह वन मंत्री थे, तो ट्रॉमा सेन्टर की बिल्डिंग का उद्घाटन कर गए। ट्रॉमा सेन्टर की बिल्डिंग का

उद्गाटन करके चले गए। ट्रॉमा सेन्टर के साथ थियेटर होता है, बिल्डिंग का उद्घाटन किया, लेकिन स्टाफ का इन्तजाम नहीं किया। आज मैं अपने माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी एवं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करुंगा कि 43 लाख रुपये इन्होंने वहां के लिए दिया जिससे ट्रॉमा सेन्टर भी बन रहा

06/03/2017/1940/RG/AS/2

है और उसका थियेटर भी बन रहा है और स्टाफ का इन्तजाम भी वहां इन्होंने किया है। तो ऐसे काम आपने किए हैं।

सभापति महोदया, 22 करोड़ रुपये की सीवरेज की योजना का उद्घाटन करके वे चले गए। लेकिन उसमें एक फूटी कोड़ी नहीं थी। उसका उद्घाटन सुबह 7.00 बजे कर दिया। आज तक उसमें कोई पैसा नहीं था। सीवरेज टैंक और सेफ्टी टैंक बनाने के लिए बी.बी.एम.बी. से परमीशन चाहिए थी, लेकिन इसकी कोई परमीशन नहीं थी। केवल मात्र वोट लेने के लिए उसका उद्घाटन करके गए। लेकिन आज हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने उस योजना के लिए 22 करोड़ रुपये मंजूर किया है जिसका टेण्डर हो गया है और अब काम भी चल पड़ा है। हम किस बात के लिए आपका धन्यवाद करें? आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? इन चीजों का विरोध कर रहे हैं जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय हमारे इलाकों को दे रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं हमारे माननीय शहरी विकास मंत्री जी का धन्यवाद करुंगा कि इनकी और माननीय मुख्य मंत्री जी की वजह से हमारे जिले में एन.यू.एल.एम. प्रोजैक्ट आया जिसके तहत हमारे यहां नौजवानों को रोजगार भी मिला और बिलासपुर शहर का नक्शा बदल गया। आज बिलासपुर शहर में 108 की तर्ज पर जो ऐम्बूलेंस है, यदि किसी भी घर में सीवरेज की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए, तो हमारे यहां एम.सी. में एक टोल फ्री नंबर है वहां कोई भी आदमी यदि अपने घर से फोन करता है, तो इनका कर्मचारी शहरी विभाग से एन.यू.एल.एम. के तहत जाता है और दूसरे दिन उसकी समस्या हल हो जाती है। जितने भी लोग मैट्रिक होल्डर हैं और

एम.एस. द्वारा जारी

06/03/2017/1945/MS/DC/1

श्री बम्बर ठाकुर जारी-----

जितने भी लोगों ने मैट्रिक या दस जमा दो की है उन लोगों को मुफ्त में सुधीर शर्मा जी के विभाग के माध्यम से, वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुफ्त में ट्रेनिंग करवाई जा रही है। आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं? कोई भी गरीब माता-पिता जो अपने बच्चे को ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं और नौकरी लगवाना चाहते हैं, वे नहीं करवा पाते यदि हमारी सरकार ने जो एन0यू0एल0एम0 दिया है जिसके अंतर्गत वहां पर फ्री में ट्रेनिंग हो रही है, वह न दिया होता। यह घुमारवीं और नैनादेवी को भी दे दिया। यह कोई भेदभाव की बात है? नैनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा जी है और एन0यू0एल0एम0 वहां भी दे दिया और घुमारवीं को भी दे दिया। फिर आप भेदभाव की बात कर रहे हैं? आप लोग राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना सीखो। हमने एस0डी0एम0 दफ्तर झण्डुता को भी दिया और नैनादेवी स्वारघाट को भी दिया। दोनों की नोटिफिकेशन हो गई है और झण्डुता के अंदर एस0डी0एम0 ने बैठकर काम करना शुरू भी कर दिया है। आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आप लोग राजा साहब का धन्यवाद करना सीखो। इसके अलावा आई0टी0आई0 गेहड़वीं, सदर, नैनादेवी और झण्डुता को भी दी। बोलने के लिए कुछ नहीं हो तो व्यक्तिगत बातें मत करो। आप लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

इसी तरह से "एम्स" के ऊपर हमने कहा कि जमीन हमने दे दी है आप बजट का इंतजाम करवाइए, हम नड्डा जी का धन्यवाद करेंगे लेकिन यहां भी विरोधाभास है। अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि ये तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन जी ने दिया और आप कहते हैं कि नड्डा जी ने दिया। आप लोग पहले अपने आप को ठीक कीजिए। हम कहते हैं कि ये यू0पी0ए0 की मनमोहन सिंह सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया है।

श्री सुरेश भारद्वाजः इस झूठ के लिए आपको 100 नम्बर मिलने चाहिए।

श्री बम्बर ठाकुरः आपको मिलने चाहिए। आप फिक्स कीजिए कि ये आपके नड्डा जी ने दिया या हर्षवर्द्धन जी ने दिया। आप अनुराग जी के साथ हैं या नड्डा जी के साथ हैं? आप पहले यह देख लीजिए कि आप किसके साथ हैं?

06/03/2017/1945/MS/DC/2

सभापति महोदया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। हमने जमीन भी दे दी और एन0टी0पी0सी0 और एन0एच0पी0सी0 ने पैसा भी दे दिया। अब बताइए कि इसका उद्घाटन किसने रोका है? इसका उद्घाटन रोकने वाला कौन है? आप कहते हैं कि केन्द्र से मोदी जी आएंगे। जब मोदी जी पड्डल में आए थे तो वहां से आपने एन0टी0पी0सी0 का उद्घाटन करवा दिया तो मेरे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करवा देते। उस समय वह उद्घाटन क्यों नहीं करवाया? आप बिलासपुर का विकास रोक रहे हैं। -(व्यवधान)-आपके नेता ने विकास रोका है। आपने पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास रोका है। यहां पर कालिया जी की स्वां नदी का पैसा आपने रोका है। सेंट्रल युनिवर्सिटी आपने रोकी है इसलिए आपको प्रदेश और प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। मेरे बिलासपुर के कॉलेज के ब्वॉयज और गर्ल्ज होस्टल के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अढ़ाई करोड़ रुपये दिए। मैं राजा साहब का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आप इन चीजों का विरोध कर रहे हैं? हमारे बिलासपुर के अस्पताल में पीने-के-पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। 15 लाख रुपये मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने बिलासपुर के अस्पताल के लिए दिए। इसके अलावा वहां पर शिशु वार्ड नहीं था। आपका स्वास्थ्य मंत्री बोलता है कि मैं मुख्य मंत्री बनूंगा। -(व्यवधान)- मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शिशु वार्ड न होने की वजह से जब किसी बहन की डिलीवरी होती थी तो डॉक्टर उनको बोलते थे कि शिमला या चण्डीगढ़ चले जाओ। बिलासपुर में डिलीवरी नहीं होगी क्योंकि यहां पर इन्क्यूबेटर नहीं है। इसके लिए यदि हम वीरभद्र सिंह जी का और कौल सिंह जी का धन्यवाद न करें तो किसका धन्यवाद करें? आज 33 लाख रुपये का शिशु वार्ड वीरभद्र सिंह जी ने बनवाया है। आपका स्वास्थ्य मंत्री कहता था कि मैं मुख्य मंत्री बनूंगा। ऐसे मुख्य मंत्री बनते हैं? बिलासपुर के अस्पताल के अंदर शिशु वार्ड नहीं बना सके -(व्यवधान)- और सुन लीजिए थोड़ी देर। बिलासपुर के अस्पताल में जनरेटर नहीं दे सके। बिलासपुर के अस्पताल में डी0सी0 के बच्चे का ऑप्रेशन हुआ तो

ऑप्रेशन के दौरान पेट में कैंची रह गई फिर पी0जी0आई0 में जाकर पेट में दुबारा चीरा लगाकर कैंची को निकाला गया। यह बिलासपुर के अस्पताल की हालत थी।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

06.03.2017/1950/जेके/डीसी/1

श्री बम्बर ठाकुरः---**जारी**-------

जो आपका स्वास्थ्य मंत्री बोलता है कि मैं मुख्य मंत्री बनुंगा। ये हैं आपके स्वास्थ्य मंत्री के हाल।

सभापतिः माननीय सदस्य प्लीज वाईंड अप।

श्री बम्बर ठाकुरः आज तक आप बिलासपुर के अस्पताल को कुछ भी नहीं दे सके। हम कौल सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे श्री वीरभद्र सिंह जी का जिन्होंने 37 लाख रूपए के तीन जनरेटर बिलासपुर अस्पताल को दिए। हम उनका धन्यवाद करते हैं लेकिन आप नहीं दे सकें। एक और नेता आपका है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सभापति महोदया मैं केवल एक मिनट लूंगा। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदया मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये उस व्यक्ति को टिकट देते हैं जिसको पूरे संसार ने पैसे लेते हुए देखा है। भ्रष्टाचार की पार्टी आप है कि हम है। उस व्यक्ति को टिकट दिया और मेरे खिलाफ उस आदमी को चुनाव में उतारा। वह भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा। ....(व्यवधान).... भारद्वाज जी हम आपसे पूछ रहे हैं। ....(व्यवधान).... आप पूछो मैं ज़वाब देता हूं।

सभापतिः माननीय सदस्य please wind up. माननीय सदस्य उनको डिस्ट्रब मत कीजिए। please don't disturb him.

श्री बम्बर ठाकुरः उस भ्रष्टाचारी नेता ने आपको गुमराह किया। कैसे हो गया।

सभापतिः माननीय सदस्य please wind up.

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय सभापति महोदया, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कहा। बिन्दल साहब को मैं ज़वाब दूंगा। बिन्दल साहब ने कहा कि डॉक्टर को बम्बर

06.03.2017/1950/जेके/डीसी/2

ने धमकाया। मैं आपसे एक बात करता हूं कि एक लड़के की टांग कट गई। जिसकी टांग नीचे से कटी उसको दिया मेडिकल 80 परसेंट और जिसकी टांग ऊपर से कटी उसको दिया 35 परसेंट। क्या यह जिम्मेदारी प्रतिनिधि की नहीं है ? डॉक्टर को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास प्रूफ है और आज उसकी इन्क्वारी चल रही है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं आप उस भ्रष्टाचारी नेता का और उस भ्रष्टाचारी डॉक्टर का साथ दे रहे हैं, जिसने गरीब हरिजन के साथ अत्याचार किया और जिससे उसने 20 हजार रूपय रिश्वत के तौर पर मांगे। ऐसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए आपको हम बधाई देते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि दो करोड़ रूपये उन्होंने बिलासपुर अस्पताल को दिए। ....(व्यवधान)....

सभापतिःमाननीय सदस्य please wind up. भारद्वाज जी please don't disturb him. आपको मौका दे देंगे। आप प्लीज बैठें। please don't disturb him. मैंने उनको भी बोलने दिया था। He also spoke. please don't disturb him. माननीय सदस्य प्लीज वाईंड अप।

श्री बम्बर ठाकुरः सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैडम मैं केवल एक मिनट लूंगा।

Chairperson: Please windup, I will not give you time. Please wind up.

श्री बम्बर ठाकुरः सभापति महोदया, मैं केवल अपनी लाईन को खत्म करूंगा। उसके बाद धन्यवाद करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिलासपुर के अस्पतालों को 2 करोड़ रूपए की दवाईयां दी। सारे गरीब लोग जब अस्पताल में जाएं तो उनको मुफ्त में दवाईयां मिलनी चाहिए। हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम इनको बधाई देते हैं। हम आपको बधाई दे रहे हैं। आपने बिलासपुर में रैली की और हम आपको बधाई देते हैं। आप उस नकली दवाई बेचने वाले को और उस नकली दवाई लिखने वाले

06.03.2017/1950/जेके/डीसी/3

का समर्थन करते हैं और उस लिखने वाले का समर्थन कर रहे हैं। जो डॉक्टर नकली दवाईयां लिखता है, जाली दवाईयां लिखता है उन लोगों का आपने समर्थन किया। इन कामों के लिए हम आपको मुबारकवाद देते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं। धन्यवाद। सभापति महोदया आपने मुझे समय दिया आपका धन्यवाद। माननीय संजय रतन जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है मैं भी इस प्रस्ताव का पुरज़ोर समर्थन करता हूं और भ्रष्टाचार के लिए इनको बधाई देता हूं कि ये भ्रटाचार फैला रहे हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

06.03.2017/1955/SS-DC/1

सभापतिः माननीय सदस्य, श्री हंस राज जी।

श्री हंस राजः माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया था, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको यहां डिस्कस करें। विधान

सभा में पहली बार चुनकर जो विधायक आए हैं उनमें उमंग और उत्साह तो नज़र आना सहज-सी बात है क्योंकि वे हमारी तरह नए लोग होते हैं। उनमें तो हर चीज़ ऐसी होती है कि अगर किसी ने थोड़ा-सा शैल्टर दे दिया तो वे अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन कुछ सीनियर लोग भी बीच-बीच में इंट्रप्ट कर रहे थे और जैसे भाई किशोरी लाल जी ने दलित भेदभाव और अन्य बातों के बारे में कहा। जब मैं यहां पर बोलूंगा तो वे सारी चीज़ें सामने आ जायेंगी। इसमें हुआ यह है, भाई बम्बर जी भी ठीक बोल रहे थे कि हमारे कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने डी0एफ0ओज़0, डॉक्टरों को बहुत डराया-धमकाया। आज कौल सिंह जी बोल रहे थे कि डॉक्टर नहीं आ रहे, यह नहीं आ रहा, वह नहीं आ रहा, क्यों आयेंगे? जब जन-प्रतिनिधि ही अपने विधान सभा क्षेत्र में गुंडों को भेज करके उनको डरा-धमका रहे हैं तो लोग क्यों आयेंगे? इस तरह की सरकार चली हुई है। --(व्यवधान)-

श्री बम्बर ठाकुरः क्या आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट है?

श्री हंस राजः पूरा पेपरों में आया हुआ है।

सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया डिस्टर्ब न करिये। Let him speak. आप इनको बोलने दीजिये। आपने जो बोलना था, वह बोल लिया। अब इनको बोलने दीजिये। अगर ये गलत बोलेंगे तो आपको बोलने का मौका देंगे। आप प्लीज़ बैठिये । हंस राज जी, प्लीज़ कंटीन्यू।

श्री हंस राजः माननीय सभापति महोदया, बंदा चोर ही नहीं तो काहला क्यों? हमारी चम्बयाली भाषा में कहावत है, जब मैंने किया ही नहीं तो मैं क्यों बौखलाहट में हूं।

06.03.2017/1955/SS-DC/2

ऐसा है, जब से यह सरकार बनी है और हम इस विधान सभा में आए हैं मुझे भी लगता था कि विधान सभा में जा करके चुराह विधान सभा क्षेत्र का कुछ कल्याण करवा पायेंगे। लेकिन इस प्रदेश और चुराह विधान सभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि जिस भेदभाव की बात यहां पर सत्तापक्ष के कुछ सम्माननीय विधायकों ने कही कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव

की राजनीति करती है, कुछ आंकड़ें मैं भी पेश करूंगा जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि कौन भेदभाव करता है। चुराह विधान सभा क्षेत्र में 62 पंचायतें हैं। 14 लोअर चुराह में आती हैं और 47 अपर चुराह में आती हैं। दुर्भाग्य देखिये, सभापति महोदया, आप स्वयं चम्बा से हैं, एक तरफ 35 किलोमीटर के रेडिअस में तीन-तीन आई0टी0आईज़0 हैं और 47 पंचायतों में कोई आई0टी0आई0 नहीं है। इसका मतलब क्या था कि जो आई0टी0आई0 चुराह को मिली थी, अपने किसी निजी व्यक्ति को जोकि कांग्रेस से संबंधित है उसको फायदा पहुंचाने के लिए एक प्राइवेट आई0टी0आई0 वहां पर खुलवा दी और अपने ही किसी तथाकथित व्यक्ति के घर को किराये पर देने के लिए उस आई0टी0आई0 को शिफ्ट करके कोटी नामक स्थान पर ले आए। इस तरह का भेदभाव इस एक ही वाक्या से नज़र आता है। 82 हजार लोग चुराह विधान सभा क्षेत्र में आते हैं और तीसा हॉस्पिटल में फीड होते हैं जहां पर 9 पोस्टें सैंक्शन हैं और सिर्फ दो ही डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउंड के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। यहां तक कि एक्स-रे भी नहीं होता है। इस तरह का रवैया मौजूदा सरकार का चला हुआ है। एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 और अदर एक्स-सर्विसमैन जो हैं उनके साथ अन्याय क्या होता है? --(व्यवधान)--

सभापतिः माननीय सदस्य, एक सैकिंड। एक्चुअली सदन का समय हो गया है और अभी एक सदस्य और बोलने को है। अगर सदन की इजाज़त हो तो सदन का समय 8:30 बजे तक बढ़ाया जाए? अब इस माननीय सदन का समय 8:30 बजे तक बढ़ाया जाता है। श्री हंस राज जी।

06.03.2017/1955/SS-DC/3

श्री हंस राजः धन्यवाद मैडम। ऐसा है, एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के साथ अन्याय हुआ। भाई किशोरी लाल जी बड़े जोर-जोर से बोल रहे थे। देखिये, आप भी उस समुदाय से आते हैं जिससे हम आते हैं। आप आज इस सीट पर कायम हैं तो किसी वजह से हैं। देखो आज एस0एम0सी0 पर भर्तियां हुईं, आउटसोर्स पर भर्तियां हुई हैं, आपके हर डिपार्टमैंट में भर्तियां हुई हैं क्या कहीं रोस्टर लग रहा है? सरकार में जितने भी एस0सी0/एस0टी0 के

लोग बैठे हैं उनको यहां बैठना ही नहीं चाहिए था। हमने तो कई बार एस0सी0/एस0टी0 फोर्म में भी कहा है जो नॉर्थ इंडिया का बना हुआ है

जारी श्रीमती के0एस0

06.03.2017/2000/केएस/एजी/1

श्री हंस राज जारी----

जिसके अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल जी हैं। हमने कई बार कहा कि अगर किसी सरकार में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के साथ भेदभाव हुआ है तो इस सरकार में हो रहा है। मुझे तो शक है कि इस तरह की कांग्रेस की सरकारें अगर दिल्ली में भी काबिज़ होती तो शायद हम जैसे लोग इन सीटों पर नहीं बैठते। किशोरी लाल जी, अभी भी समय है नींद से जाग जाइए। संविधान में प्रावधान थे तो आप सीटों पर बैठे हुए हैं, नहीं तो राजाओं का शासन होता तो आप यहां भी नहीं होते। इस तरह की जो परिपाटी चली हुई है उससे मुझे तो लगता है कि आप अपने समुदाय और अपने वर्ग विशेष के प्रति आज भी उत्तरदायी नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए किसी की प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन प्रशंसा अन्धी भी नहीं होनी चाहिए। प्रशंसा कभी भी ऐसी मत करो, लॉजिक रखो। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन जो सच है उसको यहां पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वरोज़गार कैसे हो? आपकी इन्कम कैसे जनरेट हो? आपके पास तो कोई विज़न, कोई प्लान ही नहीं है। टूरिज्म एक सबसे बड़ा पोटैंशियल था, हाइड्रो पावर सबसे बड़ा पोटैंशियल है । इंडस्ट्रीज़ जिसमें हमारा सिकरी प्लांट जो सीमेंट का प्लांट है, 2014 में किसने रद्द किया, किसकी सरकार थी? आप लोगों ने रद्द किया। हमारे प्रयास निरन्तर चलते रहे। आप लोगों ने स्वरोज़गार और पर्यटन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पी.पी.पी. मोड पर हम लोग खुद एफ़ट्र्स कर रहे हैं। तीन नए होटल हमने खुद चुराह में अलग-अलग कम्पनियों के साथ, अलग-अलग लोगों के साथ मिलकर बनवाए हैं। जबकि वहां पर भी एक पर्यटन केन्द्र खुलना चाहिए था। मनाली में बारह महीने बर्फ नहीं मिलती है लेकिन साचपास में बर्फ मिलती है और वहां सिर्फ चुराह से ही जाते हैं। हमें नेशनल हाईवे मिला हुआ है, दो-दो टनल्ज़ मिली है। उसकी डी.पी.आर. बनवाओ, सर्वे करवाओ। काम

इसको कहते हैं । आलोचना तो लोग भगवान की भी कर देते हैं। मंदिर में जा कर प्रार्थना करते हैं कि यह मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला तो भगवान की भी आलोचना कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का या नरेन्द्र मोदी जी का आपको तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत, इस

06.03.2017/1820/केएस/डीसी/2

तरह का मंत्र मोदी जी ने रखा है और उसे 100 प्रतिशत हम सिद्ध भी कर रहे हैं और 11 मार्च की जो तारीख है, इसमें हमारे जितने भी चुनाव म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन के हुए हैं उसमें तो आपने देख ही लिया है। आप नोटबन्दी-नोटबन्दी करते रहे लेकिन लोगों ने तो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर हजारों चुटकुले भी बना दिए कि दो-दो करोड़ रुपये की गाड़ी ले कर चार हजार रुपये निकलवाने के लिए रोड़ पर खड़े हैं। मैं तो मामूली सा विधायक हूं परन्तु चार लोग मेरे साथ भी होते हैं और मैंने कभी ए.टी.एम. की शक्ल भी इन चार सालों में नहीं देखी है। इसलिए अगर ड्रामा ही करना है तो कोई और तरीका निकालो।

सभापति महोदया, एम.पी.डब्ल्यू. की भर्ती हुई । माननीय वन मंत्री यहां पर नहीं बैठे हैं। पहले चम्बा में एलमी के जंगल कटवा दिए उसके बाद आजकल भी चुराह के जंगल में देवदार के पेड़ कटवा रहे हैं, अपने किसी जिला परिषद को पूरा संरक्षण दे करके। उसके मकान में वह लग रहे हैं। उसका मेरे पास विडियो भी है वह हम नियम-62 के अंतर्गत लगाएंगें। उसके बारे में अखबारों में भी आया हुआ है। एम.पी.डब्ल्यू. चम्बा में 29 भर्ती हुए। मैडम, आपको पता होगा क्योंकि आप भी चम्बा से आते हैं। 24 लोग एक ही चुनाव क्षेत्र भरमौर से लगे, यह भेदभाव होता है। माननीय वन मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी अभी यहां नहीं बैठे हैं लेकिन लोगों ने तो चम्बा में यह भी शगूफ़ा छोड़ा हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को दिल्ली जाना होता है, वे कलैक्शन एजैंट बने हुए हैं। इस तरह की बातें वहां पर चली हुई है जबकि जो छः बार के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं चलनी चहिए। उनकी छवि ही ऐसी है। चम्बा के लोग हमें भी थू-थू करते हैं कि तुम लोग भी चुने हुए हो।बाथरी से द्रडा की तरफ चलो तो वहां रोड़ की इतनी खराब हालत है जो आज तक कभी नहीं हुई। इनके चुनाव क्षेत्र में मैं हाइड्रो पावर में नौकरी करता था । चम्बा से निकलता था और बाईक पर एक घण्टा सैंतालिस मिनट लगते थे और आज की तारीख में स्कॉरपिओ में ढाई घंटे लगते हैं वन मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में। इस तरह के मंत्री आपने रखे

हुए हैं। आज की तारीख में स्नो कटिंग के नाम पर करोड़ों रुपये का ठेका साचपास में इन्होंने किसी अपने ही ठेकेदार को दे दिया है और उसमें से पता नहीं कितना पैसा लिया है। इस तरह के काम वहां पर चल रहे हैं। भंजराडू से शिमला की तरफ बस लगनी थी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.3.2017/2005/av/as/1

श्री हंस राज क्रमागत

रूट भी मिला हुआ है लेकिन मुख्य मंत्री जी आज आयेंगे, कल आयेंगे; मेरे चुराह की तरफ वे कभी नहीं आते। पता नहीं, क्या कारण है? यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? हम पिछले तीन सालों से मुख्य मंत्री जी का वेट कर रहे हैं। लोगों ने बने-बनाये पुल जिन पर साल-साल, दो-दो सालों से गाड़ियां चलती रहीं लास्ट में अभी भी प्रोग्राम दिया था जिसमें यह कहा था कि मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं इस पुल को बंद कर दिया जाए। फिर हमें जबरदस्ती चलवाने पड़ते हैं, इनका इस तरह का रवैया चला हुआ है। गवर्नमैंट डिग्री कालेज बंझराडू में साईंस स्ट्रीम चलना था और वहां पर स्टाफ इत्यादि सबकुछ उपलब्ध था। मगर जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी इन्होंने उसको वहां से शिफ्ट करके चम्बा भेज दिया वहां कुछ नहीं है। साईंस क्लासिज सीनियर सैकेंडरी स्कूल में नहीं चलती। लोगों ने कहां कि स्कूल खुले, यह हुआ, वह हुआ मगर चुराह में कुछ नहीं हुआ। यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? हमने विधान सभा में पिछली बार भी चर्चा की की यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? तीसा और बंझराडू बस-स्टैंड के लिए पैसा स्वीकृत है लेकिन उन पर दो-ढाई सालों से कोई काम नहीं चल रहा है। हमारे समय में जो सड़कें स्वीकृत थी उनका काम रुका हुआ है, उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। शुखराली में पिछले तीन साल से पुल का निर्माण हो रहा है लेकिन वह काम पूरा ही नहीं हो रहा है और सरकार की तरफ से उनको इस तरह का संरक्षण दिया हुआ है।

पर्यटन की दृष्टि से चुराह के साथ-साथ प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको विकसित किया जा सकता है। मगर सरकार उस पर सीरियस ही नहीं है। पता नहीं हम हिमाचल में इनकम के सोर्सिज को कैसे जनरेट करेंगे? अब कई लोग तो उमरदराज हो गये हैं उन्होंने तो जाना है। हम सबने निकलना है, इसमें कोई गाली नहीं है। लेकिन हम लोग चिन्तित है कि

अगर दो-तीन बार जीत कर आएं तो लोग हम से ही पूछेंगे कि प्रदेश की इनकम कैसे जनरेट होगी। इसलिए आज का समय था जिसमें हम यह सोच सकते थे। आगे के लिए भी बड़ा विज़न रख कर कि इनकम कैसे जनरेट हो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। चम्बा की कोर्ट में जितने मामले चलते हैं उसमें चुराह विधान सभा क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत मामले होते है। जब एस0डी0एम0 कार्यालय खुला था उसी वक्त सब-जज कोर्ट खुलना होता है इस तरह का प्रावधान होता है। डी0एस0पी0 कार्यालय वहीं पर खुलता है। वहां पर किसी भी प्रकार का डिविजन जैसे आई0पी0एच0, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड या पी0डब्ल्यू0डी0; कोई

6.3.2017/2005/av/as/2

नहीं खोला गया है। इस तरह का भेदभाव पूर्ण रवैया क्यों रखा गया है? 55 साल तो आप ही सत्ता में रहे, हिसाब तो आप ही लोगों से मांगेंगे। यहां पर 'कांग्रेस मुक्त भारत' ठीक कहा गया है, यह तो होना ही है। इस वजह से भी होना है क्योंकि अब सारा राष्ट्र जानता है। आज की डेट में हमारे जैसे पिछड़े क्षेत्रों में हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन बना हुआ है। हमारे समय में लगभग 9 हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट लगे थे जिसमें सैंकड़ों लोगों को रोज़गार मिला था। कई लोगों के मकान भी पक्के हुए थे क्योंकि किसी ने सीमैंट लिया, किसी ने सरिया लिया और किसी ने बज़री ली। लेकिन आज की डेट में यानि पिछले चार वर्षों में कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट नहीं लगा तो रोजगार कैसे जनरेट होगा? अंतिम मुद्दा एस0पी0ओज0 का मुद्दा है। मेरी जानकारी के अनुसार एस0पी0ओज0 चम्बा और दो-तीन शायद लाहौल-स्पिति में है। इसमें लगभग 500 परिवार है और प्लस टू पास हैं। वे लोग 18-18 साल लगा चुके हैं और मैं इस बात के लिए यहां पर कई बार गला फाड़ चुका हूं। जब दिल्ली में आपकी सरकार थी तब भी आप यही कहते थे कि यह केंद्र सरकार का मुद्दा है। तब भी यही जुमला था और आज भी आपका वही जुमला चल रहा है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आपने क्या प्रयास किए हैं? मैं इसमें एक बात और दोहराना चाहता हूं कि फॉरैस्ट कॉर्पोरेशन में लोग मर्ज़ हुए थे। आप उस तर्ज पर इन लोगों को क्यों नहीं करते? एस0पी0ओज0 केवल चम्बा में है इसलिए आप उनको मर्ज़ नहीं करते? चम्बा में पांच ही सीटें हैं इसीलिए आप नहीं करते? मुझे तो यह लगता है कि अगर आपकी 5 में से दो सीटें आ गई तो भला हो गया, ठीक है। यह पक्षपात पूर्ण और भेदभाव पूर्ण रवैया है। जैसे एम0पी0डब्ल्यू0 की भर्ती हुई उसमें कई लोगों ने 18-18, 20-20 साल नर्सरी में लगाए थे। जब एम0पी0डब्ल्यू0 ने सफाई, चाय और पानी ही पिलाना है तो

फिर उसकी भर्ती ही क्यों की गई केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई? प्रदेश में इस तरह का भेदभाव पूर्ण रवैया चला हुआ है और इससे चुराह का कोई भला नहीं हुआ है। बीच में एक बात छूट गई, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि

जारी श्री वर्मा द्वारा

06/03/2017/2010/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्री हंस राज- - - जारी

जो मिड-डे हिमालयन प्रोजैक्ट है, इसको तो लोगों ने अपना निजी प्रोजैक्ट बना लिया है। कई वाईस चेयरमैंनों ने अपने घरों के लिए रास्ता/ब्रिजिज बनवाने के लिए इस धन का उपयोग करना शुरू किया है। उनकी अपनी गऊशालायें भी मिड-डे-हिमालयन प्रोजैक्ट के तहत ही बन रही है। माननीय मंत्री जी पता नहीं प्रदेश में क्या-क्या करवा रहे हैं और उनको माननीय मुख्य मंत्री जी पूरा-पूरा संरक्षण दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

सभापतिः आज के आखरी व़क्ता है, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः आदरणीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 1 मार्च, 2017 को जो अभिभाषण इस माननीय सदन में दिया गया, जिसका धन्यवाद प्रस्ताव मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) ने और अनुसमर्थन श्री संजय रतन ने किया, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मेरे से पूर्व (पक्ष/ विपक्ष) के वक्ताओं ने काफी डिटेल में चर्चाएं की है। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, इनका रवैया तो ऐसा है कि जैसे चार सालों में हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ है, जो बड़े अफ़सोस की बात है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्य मंत्री की चार साल की जो उपलब्धियां है, उनको अपने अभिभाषण के माध्यम से यहां माननीय सदन में रखा है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, जहां तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में इन 4 सालों के अलावा भी राजा वीरभद्र सिहं जी के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है। मैं आपको उदहारण के तौर

पर बताना चाहूंगा, रोहडू विधान सभा क्षेत्र में हमारे पास पहले कॉलेज नहीं था। हमें उच्च शिक्षा के लिए रामपुर या फिर शिमला आना पड़ता था जोकि आम आदमी की पहुंच से बाहर था। लड़कियों को तो सिर्फ नजदीक के स्कूल/कॉलेजों में ही भेजते थे। आज हमारे पास राजा साहब के आशीर्वाद से रोहडू में पी0जी0 कॉलेज-सीमा है, that college is also one of the best college in Himachal. जब वह कॉलेज खुला था, तो उस कॉलेज में केवल 16-17 विद्यार्थी थे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज उस कॉलेज में 2300-2400 विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। यहां पर अभी चर्चा हुई कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे कम है और स्टॉफ ज्यादा है, हो सकता है

06/03/2017/2010/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

कि कुछेक स्कूलों में ऐसा होगा। इसके लिए भी हम खुद ही जिम्मेवार है, हम अपने बच्चे सरकारी स्कूलों के बजाये प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। यदि कहीं ऐसी स्थिति है, तो उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। सरकारी स्कूलों में ट्रेंड टीचर होने के बावजूद भी हम इन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन 4 सालों में बहुत विकास हुआ है। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का उदहारण देना चाहूंगा। जब मैं नया-नया विधायक बना था, मेरे चुनाव क्षेत्र रोहडू में एक सिविल हॉस्पिटल था, उसमें कोई डॉक्टर/स्टॉफ नर्सिज़ नहीं थे।

श्रीमती एन0एस0- - द्वारा जारी।

06/03/2017/2015/ns/as /1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा ----- जारी।

आज राजा साहब और ठाकुर कौल सिंह जी के आर्शीवाद से रोहडू में डॉक्टर्ज़ और स्टॉफ नर्सिज़ हैं। इस सदन में क्षेत्रवाद की भी बात आई थी तो मैं उस तरफ भी जाना चाहूंगा। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है और विधान सभा क्षेत्रों से पार्टी आधार पर भेदभाव करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में

भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय प्रो0 धूमल जी मुख्य मंत्री थे, तब रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में पांच साल तक विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदया, मैं माननीय श्री भारद्वाज जी को उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि वह रोहड़ू क्षेत्र से भी संबंध रखते हैं,जब वर्ष 2007 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो रोहड़ू बस स्टैंड का काम शुरू हुआ था और वर्ष 2010 में बस स्टैंड का काम बंद किया गया था। अब, जब छठी बार राजा साहब मुख्य मंत्री बनें तो इनकी बदौलत आज रोहड़ू बस स्टैंड बन रहा है। मैं राजा साहब का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर राजा साहब मुख्य मंत्री न होते तो हमारा ठियोग-हाटकोटी और खड़ा पत्थर-रोहड़ू रोड कभी नहीं बनता। असली बात में छिपाऊंगा नहीं और झूठ बात मैं बोलूंगा नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय इस सड़क का काम चला हुआ था चाईनीज़ कम्पनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए चाहे रीज़न जो भी रहा होगा लेकिन दो साल तक काम बंद रहा। राजा साहब ने 25 दिसम्बर, 2012 को मुख्य मंत्री की शपथ ली और इन्होंने 30 दिसम्बर तक फौरन छोटे लैवल से सेक्रेटरी लैवल तक के अधिकारी तलब किए और उसमें मुझे और श्री रोहित ठाकुर जी को भी बुलाया गया और वहां पर जायजा लिया गया कि सड़क का काम क्यों बंद है? अधिकारियों ने जो भी कारण बताये उसके बावजूद भी राजा साहब ने तुरन्त आदेश किए कि जो भी कारण रहे हों इस सड़क का काम तुरन्त होना चाहिए। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग रोहड़ू से शिमला अढ़ाई-तीन घंटें में पहुंच जाते हैं। यहा पर भेदभाव की भी बात आई कि

06/03/2017/2015/ns/as /2

कांग्रेस वाले भेदभाव करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं करते हैं। इसी तरह अगर आपको याद होगा कि जो वर्ष 2010 का सेब सीज़न था तब तीन-चार दिनों तक जगह-जगह सड़कों, बसों और ट्रकों में लोगों को सोना पड़ा था। माननीय भारद्वाज जी इस चीज़ से वाकिफ हैं। मेंदली का पुल मोटरेबल पुल बन करके आपकी सरकार के समय में तैयार हो चुका था। पुल तो तैयार हो गया लेकिन मोटरेबल रोड नहीं बना। इसका कारण

यह था कि जो लोगों की लैंड एक्वायर की थी, उसका पैसा नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती थी कि रोहड़ू वालों को रोड मिले। मैं और पूरी रोहड़ू की जनता राजा साहब का बहुत-बहुत धन्यवादी और शुक्रगुज़ार रहेगी। राजा साहब ने तुरन्त लोगों का मुआवज़ा दिया जिसके कारण हमारा बाईपास बना। इतिहास गवाह है कि राजा साहब और कांग्रेस पार्टी ने किसी भी क्षेत्र से भेदभाव नहीं किया है। यहां पर और भी बहुत सारी बातें आईं हैं कि बागवानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपकी जब सरकार थी तो आपने बागवानों पर गोलियां चलाई, घोड़े दौड़ाये। यहां पर स्वां नदी की बात भी आई। इसके लिए मैं इनका भी समर्थन करता हूं। मेरे क्षेत्र में एक पब्बर नदी है। उसका भी चैनलाईजेशन हुआ है। उसका बजट लगभग 200 करोड़ का है।

श्री आर0के0 एस0 ------ जारी।

06.03.2016/2020/RKS/DC/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा .... जारी

पिछली बार वह सैंक्शन हुई और अब केन्द्र सरकार ने इसका पैसा बंद कर दिया। इसी तरह जो दूसरी सैंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्ज हैं, सारी बंद कर दी गई। जब मोदी जी ने प्रचार किया था तो लोगों को क्या-क्या सपने दिखाए। कहा गया था कि 15-15 लाख हर आदमी के खाते में आएगा। बेरोज़गारी दूर होगी। अढाई साल केंद्र में बी.जे.पी. की सरकार बने हुए हो गए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से तो ऐसा कोई नौजवान नहीं है जिसे केंन्द्र सरकार की तरफ से रोजगार मिला हो। ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार दिया है। महंगाई खत्म होगी परन्तु आज महंगाई कहां खत्म हुई। महंगाई चरम सीमा पर चढ़ी हई है। आज पैट्रोल, सिलेंडर, दालें हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं राजा साहब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने चार वर्षों में हजारों की संख्या में रोजगार दिया। चाहे एस.एम.सी, वाटर कैरियर, चतुर्थ श्रेणी या क्लास वन ऑफिसर की बात हो। हमारे कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर, पब्लिक सर्विस कमीशन में हर रोज इंटरव्यू चले हुए हैं। नोटबंदी आपके सामने है। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। कई लोगों के बच्चों की शादियां थी लेकिन लोगों को लाइनों में लगना पड़ा। कई लोगों की तो लाइन में लगकर

मृत्यु भी हो गई। सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है वह तथ्य के आधार पर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चार वर्षों में जो भी कार्य किए हैं वे सब तथ्य के आधार पर हैं। मैं इस अभिभाषण का जोरदार समर्थन करता हूं। सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापतिः अब इस मान्य सदन की बैठक मंगलवार, 7 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **श्री सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 06 मार्च, 2017 **सचिव ।**